Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

JANUARY 2026 MONTH BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

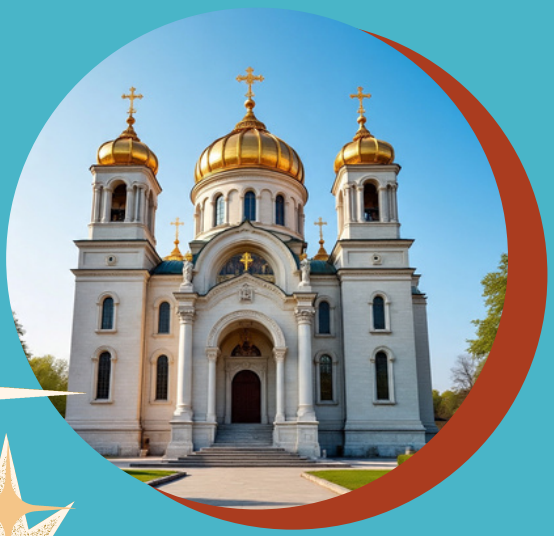

120+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: From which date will Oman's first polymer one-rial banknote start circulating?
ओमान का पहला पॉलिमर वनआएगा में प्रचलन से तिथि किस बैंकनोट रियाल-?

A) January 1, 2025
B) January 11, 2026
C) March 15, 2026
D) July 1, 2026
E) December 31, 2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Oman has introduced its first-ever polymer one-rial banknote to enhance durability and security.
• ओमान ने अधिक टिकाऊपन और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अपना पहला पॉलिमर वन- है। किया जारी बैंकनोट रियाल
• The new polymer banknote will officially enter circulation from January 11, 2026.
• नया पॉलिमर बैंकनोट 11 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से प्रचलन में आएगा।
• Polymer banknotes last longer and are more resistant to wear and tear compared to traditional paper notes.
• पॉलिमर बैंकनोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते।
• The banknote incorporates advanced security features to prevent counterfeiting.
• जालसाजी रोकने के लिए इस बैंकनोट में उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ शामिल की गई हैं।
• Its design showcases Oman's cultural heritage and economic achievements.
• इसके डिज़ाइन में ओमान की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
• This initiative aligns Oman with global best practices in modern currency design.
• यह पहल ओमान को आधुनिक मुद्रा डिज़ाइन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाती है।

Ques: Which regulator has simplified the procedure for issuance of duplicate securities by doubling the monetary threshold for simplified documentation to ₹10 lakh?
डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ₹10 लाख तक की सीमा बढ़ाने का निर्णय किस नियामक ने लिया है?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
C) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
D) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has simplified the procedure for issuance of duplicate securities by increasing the monetary threshold for simplified documentation from ₹5 lakh to ₹10 lakh.
• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)SEBI) ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है।
• The decision follows a consultation paper issued in November 2025, aimed at improving ease of investor services and bringing uniformity in procedures.
• यह निर्णय नवंबर 2025 में जारी परामर्श पत्र के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य निवेशक सेवाओं को आसान बनाना और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है।
• Investors holding securities valued up to ₹10 lakh will now need to submit fewer documents for reissuance of lost or damaged securities.
• ₹10 लाख तक मूल्य की प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशकों को अब खोई या क्षतिग्रस्त प्रतिभूतियों के पुनः निर्गमन के लिए कम दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
• For securities up to ₹10,000, investors can submit a simple undertaking on plain paper.
• ₹10,000 तक की प्रतिभूतियों के लिए निवेशक साधारण कागज़ पर एक साधारण

अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं।
• For securities above ₹10,000 and up to ₹10 lakh, only a standard Affidavit-cum-Indemnity Bond on appropriate non-judicial stamp paper is required.
• ₹10,000 से अधिक और ₹10 लाख तक की प्रतिभूतियों के लिए उपयुक्त गैर स्टाम्प न्यायिक-क्ष-सह-शपथपत्र मानक केवल पर पेपरतिपूर्ति बांड की आवश्यकता होगी।
• For securities exceeding ₹10 lakh, additional safeguards such as FIRs, court-related documents, and mandatory newspaper advertisements by listed companies will continue to apply.
• ₹10 लाख से अधिक की प्रतिभूतियों के मामलों में एफआईआर, न्यायालय से संबंधित दस्तावेज़ और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनिवार्य समाचार अतिरिक्त जैसी विज्ञापन पत्र-रहेंगी। लागू शर्तें सुरक्षा

Ques: Which company received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India to commence operations as a Non-Banking Financial Company (NBFC)?
भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में कार्य शुरू करने के लिए प्रमाणपत्र)CoR) किस कंपनी को प्राप्त हुआ?

A) Aryaman Finance (India) Limited / आर्यमन फाइनेंस लिमिटेड (इंडिया)
B) Bajaj Finance Limited / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
C) Shriram Finance Limited / श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
D) Tata Capital Limited / टाटा कैपिटल लिमिटेड
E) L&T Finance Limited / एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Aryaman Finance (India) Limited (AFIL) has received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India (RBI) to start the business of a Non-Banking Financial Company (NBFC).
• आर्यमन फाइनेंस) लिमिटेड (इंडिया)AFIL) को गैर) कंपनी वित्तीय बैंकिंग-NBFC) के रूप में व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र)CoR) प्राप्त हुआ है।
• The RBI grants NBFC registration under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

• आरबीआई एनबीएफसी का पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत प्रदान करता है।
• Following this approval, AFIL will operate as a Type-II NBFC-ND-ICC (Non-Deposit Taking – Investment and Credit Company).
• इस स्वीकृति के बाद, AFIL टाइप-II NBFC-ND-ICC (गैर वाली करने स्वीकार जमा-– निवेश एवं ऋण कंपनी कार्य में रूप के (करेगी।

Ques: As per the RBI report, what was the total deposits of payments banks in India as of March 2025?
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत में पेमेंट्स बैंकों की कुल जमा राशि कितनी थी?

A) ₹18,000 crore
B) ₹22,450 crore
C) ₹25,605 crore
D) ₹28,900 crore
E) ₹30,000 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI report, deposits in India's payments banks increased by 57% year-on-year to ₹25,605 crore as of March 2025.
• आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत के पेमेंट्स बैंकों की जमा राशि साल-साल-दर57% बढ़कर ₹25,605 करोड़ हो गई।
• As of March 2025, a total of six payments banks were operational in India with 81 branches across the country.
• मार्च 2025 तक भारत में कुल 6 पेमेंट्स बैंक कार्यरत थे, जिनकी 81 शाखाएँ थीं।
• Deposits, including savings and current accounts, accounted for 68.1% of the total liabilities of payments banks.
• जमा राशि का देनदारियों कुल की बैंकों पेमेंट्स (खाते चालू एवं बचत)68.1% हिस्सा रही।
• On the asset side, investments were mainly in Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities due to restrictions on lending.
• ऋण देने पर प्रतिबंध के कारण परिसंपत्ति पक्ष में मुख्य रूप से वैधानिक तरलता अनुपात)SLR) प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

• Payments banks remained profitable for the third consecutive year in FY25, indicating improving financial stability.
• FY25 में पेमेंट्स बैंक लगातार तीसरे वर्ष लाभ में रहे, जो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाता है।

Ques: Which Russian bank has been authorised by India's Ministry of Commerce and Industry to import gold for FY 2025–26 under the Foreign Trade Policy 2023?
विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सोना आयात करने हेतु भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस रूसी बैंक को अधिकृत किया है?

A) VTB Bank / वीटीबी बैंक
B) Gazprombank / गज़प्रोमबैंक
C) Sber Bank / स्बेर बैंक
D) Alfa-Bank / अल्फा बैंक
E) Rosbank / रोसबैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Commerce and Industry has added Russia's Sber Bank to the list of banks authorised to import gold for FY 2025–26, expanding the authorised importer base.
• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सोना आयात करने हेतु रूस के स्बेर बैंक को अधिकृत बैंकों की सूची में शामिल किया है।
• The authorisation has been granted under the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time.
• यह प्राधिकरण समय) नीति व्यापार विदेश संशोधित पर समय-FTP) 2023 के तहत दिया गया है।
• Sber Bank's authorisation is valid from June 25, 2025, to March 31, 2026, and is restricted exclusively to gold imports meant for domestic consumption.
• स्बेर बैंक की अनुमति 25 जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक मान्य है और यह केवल घरेलू उपभोग के लिए सोना आयात करने तक सीमित है।
• With this inclusion, Sber Bank becomes the third bank—after Indian Overseas

Bank and Union Bank of India—authorised to import only gold during FY 2025–26.
• इस शामिल किए जाने के साथ, स्बेर बैंक वित्त वर्ष 2025–26 में केवल सोना आयात करने के लिए अधिकृत तीसरा बैंक बन गया है; इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यह अनुमति दी गई थी।

Ques: As per the RBI report, what was the total number of ATMs in India as of March 31, 2025?
RBI रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत में ATM की कुल संख्या कितनी थी?

A) 2,53,417
B) 2,48,900
C) 2,51,057
D) 2,60,000
E) 2,45,120

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI report, the total number of ATMs in India declined to 2,51,057 as of March 31, 2025, from 2,53,417 a year earlier.
• RBI रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत में ATM की कुल संख्या घटकर 2,51,057 रह गई, जो एक वर्ष पहले 2,53,417 थी।
• The decline in ATM numbers is attributed to the rapid rise in digital payments and increased digitisation of banking services.
• ATM की संख्या में यह गिरावट डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण में वृद्धि के कारण हुई है।
• Private sector banks saw a decline in ATMs to 77,117 from 79,884 in the previous year.
• निजी क्षेत्र के बैंकों के ATM घटकर 77,117 रह गए, जो पिछले वर्ष 79,884 थे।
• Public sector banks' ATMs also fell to 1,33,544 from 1,34,694.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ATM भी घटकर 1,33,544 हो गए, जो पहले 1,34,694 थे।
• Banks have been shutting down offsite ATMs as customer dependence on cash transactions continues to decline.
• ग्राहकों की नकद लेन ऑफसाइट बैंक कारण के होने कम निर्भरता पर देन-ATM बंद कर रहे

हैं।
• Despite the decline in ATMs, the number of bank branches increased by over 2%, led mainly by public sector banks.
• ATM में गिरावट के बावजूद बैंक शाखाओं की संख्या 2% से अधिक बढ़ी, जिसमें सार्वजनिक बैंकों की प्रमुख भूमिका रही।
• As of March 31, 2025, India had around 1.64 lakh bank branches, reflecting a year-on-year growth of 2.8%.
• 31 मार्च 2025 तक भारत में लगभग 1.64 लाख बैंक शाखाएँ थीं, जो 2.8% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती हैं।
• The number of white-label ATMs increased to 36,216 from 34,602, indicating expansion in this segment.
• व्हाइट लेबल-ATM की संख्या बढ़कर 36,216 हो गई, जो पहले 34,602 थी।

Ques: Which scheme launched in Union Budget 2024–25 aims to promote early savings and long-term financial security for minors in India?
भारत में नाबालिगों के लिए प्रारंभिक बचत और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2024–25 के केंद्रीय बजट में कौनगई की शुरू योजना सी-?

A) Atal Pension Yojana / अटल पेंशन योजना
B) Sukanya Samriddhi Yojana / सुकन्या समृद्धि योजना
C) Public Provident Fund / सार्वजनिक भविष्य निधि
D) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana / प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
E) National Pension System Vatsalya / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The National Pension System Vatsalya (NPS Vatsalya) was announced in the Union Budget 2024–25 on 23 July 2024 and launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य)NPS Vatsalya) की घोषणा 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया।
• The scheme is administered and regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

• इस योजना का संचालन और नियमन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण)PFRDA) द्वारा किया जाता है।
• It is a saving-cum-pension scheme for all minor citizens up to 18 years, with the account opened in the name of the minor and operated by a parent or guardian.
• यह 18 वर्ष तक के सभी नाबालिग नागरिकों के लिए एक बचतहै योजना पेंशन-सह-, जिसमें खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाता है और अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।
• The minimum contribution is ₹1,000 to open the account and ₹1,000 per annum thereafter, with no upper limit on maximum contribution.
• खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान ₹1,000 और उसके बाद प्रति वर्ष ₹1,000 है, जबकि अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।
• At the age of 18, the account automatically converts into an NPS Tier-I (All Citizen) account, subject to fresh KYC within three months.
• 18 वर्ष की आयु पर यह खाता स्वतः NPS टियर-I (ऑल सिटीजन हो परिवर्तित में खाते (है जाता, जिसके लिए तीन माह के भीतर नया KYC आवश्यक है।

Ques: According to the RBI's *Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25*, by how much did the banking system's balance sheet expand during 2024–25?
RBI की *बैंकिंग में रुझान और प्रगति* रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट कितने प्रतिशत बढ़ा?

A) 9.5%
B) 10.2%
C) 11.2%
D) 12.0%
E) 12.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• As per the RBI's *Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25*, the banking system's balance sheet expanded by 11.2% during the year.
• RBI की *बैंकिंग में रुझान और प्रगति* रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट 11.2% बढ़ा।

• The total size of the banking system's balance sheet reached ₹312.2 lakh crore in 2024–25.
• 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का कुल बैलेंस शीट आकार ₹312.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
• During the same period, bank deposits registered a growth of 11.1%.
• इसी अवधि में बैंक जमाओं)Deposits) में 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई।
• Bank credit, including loans and advances, increased by 11.5%, broadly matching the pace of deposit growth.
• बैंक ऋण)Loans एवं Advances) में 11.5% की वृद्धि हुई, जो जमा वृद्धि के लगभग समान रही।
• Overall, the report reflects steady and balanced growth in India's banking sector.
• कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट भारत के बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर और संतुलित वृद्धि को दर्शाती है।

Ques: Which institution provided a ₹300 crore loan to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited, marking its first-ever RMBS investment in India?
भारत में पहली बार RMBS निवेश करते हुए, गृहुम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल मॉर्गेज) सिक्योरिटीज़ बैक्ड-RMBS) को ₹300 करोड़ का ऋण किस संस्था ने प्रदान किया?

A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
B) World Bank / विश्व बैंक
C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
D) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक
E) International Finance Corporation (IFC) / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The International Finance Corporation (IFC) has provided a loan of ₹300 crore (about USD 30 million) to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited.
• अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम)IFC) ने गृहुम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल

मॉर्गेज) सिक्योरिटीज़ बैक्ड-RMBS) को ₹300 करोड़ लगभग)30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (है। किया प्रदान ऋण का

• This investment marks IFC's first-ever RMBS investment in India.
• यह भारत में IFC का पहला RMBS निवेश है।
• The International Finance Corporation was established in 1956 and is headquartered in Washington, D.C., United States.
• अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
• IFC focuses on private sector development in emerging economies by providing investments, advisory services, and asset management.
• IFC उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र के विकास के लिए निवेश, परामर्श सेवाएँ और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है।
• The current Managing Director of IFC is Makhtar Diop.
• IFC के वर्तमान प्रबंध निदेशक मख़्तार दियोप हैं।

Ques: As per RBI, how many Urban Co-operative Banks (UCBs) were operational at the end of FY25?
RBI के अनुसार FY25 के अंत में कितने शहरी सहकारी बैंक)UCBs) कार्यरत थे?

A) 1,472
B) 1,463
C) 1,457
D) 1,489
E) 1,426

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI's *Report on Trend and Progress of Banking in India*, the number of Urban Co-operative Banks (UCBs) declined by 15 during FY25, bringing the total down to 1,457.
• RBI की *ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया* रिपोर्ट के अनुसार FY25 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 15 घटकर 1,457 रह गई।
• The decline in the number of UCBs was mainly due to mergers and cancellation of licences.

• UCBs की संख्या में यह गिरावट मुख्य रूप से विलय और लाइसेंस रद्द होने के कारण हुई।
• During FY25, a total of 7 mergers of UCBs were carried out, with 6 mergers in Maharashtra and 1 in Telangana.
• FY25 में UCBs के कुल 7 विलय किए गए, जिनमें से 6 महाराष्ट्र में और 1 तेलंगाना में हुआ।
• In comparison, FY24 witnessed 6 mergers of Urban Co-operative Banks.
• तुलना में FY24 के दौरान UCBs के 6 विलय हुए थे।
• The RBI initiated the consolidation process of UCBs in 2004–05, focusing on amalgamation of weak banks and closure of unviable ones.
• RBI ने 2004–05 में UCBs के समेकन की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें कमजोर बैंकों का विलय और अव्यवहारिक बैंकों को बंद करना शामिल है।
• As a result of this long-term consolidation, the total number of UCBs declined steadily from 1,926 in March 2004 to 1,457 in March 2025.
• इस दीर्घकालिक समेकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मार्च 2004 में 1,926 से घटकर मार्च 2025 में UCBs की संख्या 1,457 रह गई।

Ques: Which Government Security has been announced for re-issue by the Government of India through a price-based auction in January 2026?
जनवरी 2026 में मूल्यके नीलामी आधारित- माध्यम से भारत सरकार द्वारा किस सरकारी प्रतिभूति के पुनः निर्गम है गई की घोषणा की (इश्यू-री)?

A) 6.48% Government Security 2035
B) 6.18% Government Security 2033
C) 7.10% Government Security 2034
D) 6.95% Government Security 2036
E) 5.89% Government Security 2032

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India has announced the re-issue of "6.48% Government Security 2035" for a notified amount of ₹32,000 crore through a price-based auction using the multiple price method.
• भारत सरकार ने ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए बहु तहत के पद्धति मूल्य-से माध्यम के नीलामी आधारित-मूल्य"6.48% सरकारी प्रतिभूति 2035" के पुनः निर्गम की घोषणा की है।

• The Government has the option to retain additional subscription of up to ₹2,000 crore against this security.
• सरकार के पास इस प्रतिभूति के विरुद्ध ₹2,000 करोड़ तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प है।
• The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, on January 02, 2026.
• यह नीलामी 02 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।
• Up to 5% of the notified amount will be allotted to eligible individuals and institutions under the Non-Competitive Bidding Facility scheme.
• अधिसूचित राशि का अधिकतम 5% गैर सुविधा बोली प्रतिस्पर्धी-योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
• Both competitive and non-competitive bids must be submitted electronically through the RBI Core Banking Solution (E-Kuber system).
• प्रतिस्पर्धी और गैरबोल की कारप्र दोनों प्रतिस्पर्धी-ियां आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान जाएंगी। की प्रस्तुत से रूप इलेक्ट्रॉनिक से माध्यम के (प्रणाली कुबेर-ई)
• The security will also be eligible for "When Issued" trading as per RBI guidelines issued on July 24, 2018, and amended from time to time.
• यह प्रतिभूति आरबीआई द्वारा 24 जुलाई 2018 को जारी (संशोधित पर समय-समय) अनुसार के दिशानिर्देशों"व्हेन इश्यूड" ट्रेडिंग के लिए भी पात्र होगी।

Ques: By when does the Unique Identification Authority of India (UIDAI) plan to expand the total number of Aadhaar Seva Kendras to 473 across India?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)UIDAI) कब तक पूरे भारत में आधार सेवा केंद्रों की संख्या 473 करने की योजना बना रहा है?

A) September 2025
B) December 2025
C) September 2026
D) March 2027
E) June 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has inaugurated a new Aadhaar Seva Kendra (ASK) at Mangaluru in Dakshina Kannada district of Karnataka.
• भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)UIDAI) ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में एक नया आधार सेवा केंद्र)ASK) शुरू किया है।
• UIDAI has announced plans to open a total of 22 Aadhaar Seva Kendras across Karnataka.
• UIDAI कर्नाटक में कुल 22 आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना बना रहा है।
• The total number of Aadhaar Seva Kendras across India will be expanded to 473 by September 2026 to improve accessibility and service delivery.
• देशभर में आधार सेवा केंद्रों की कुल संख्या बढ़ाकर सितंबर 2026 तक 473 कर दी जाएगी, जिससे नागरिकों की पहुंच और सेवा वितरण में सुधार होगा।
• Aadhaar Seva Kendras are full-service centres that provide Aadhaar enrolment, biometric updates, and demographic correction services, especially for adults.
• आधार सेवा केंद्र पूर्णहैं होते केंद्र सेवा-, जो आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और जनसांख्यिकीय सुधार जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं, विशेष रूप से वयस्कों के लिए।

Ques: How many lenders are live on RBI's Unified Lending Interface (ULI) platform as of December 12, 2025?
12 दिसंबर 2025 तक RBI के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस)ULI) प्लेटफॉर्म पर कितने ऋणदाता लाइव हैं?

A) 52
B) 58
C) 60
D) 64
E) 70

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• As of December 12, 2025, a total of 64 lenders are onboard the Reserve Bank of India's Unified Lending Interface (ULI) platform.
• 12 दिसंबर 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस)ULI)

प्लेटफॉर्म पर कुल 64 ऋणदाता शामिल हो चुके हैं।
• These include 41 banks and 23 Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
• इनमें 41 बैंक और 23 गैर) कंपनियां वित्तीय बैंकिंग-NBFCs) शामिल हैं।
• Lenders are utilising more than 136 data services through ULI across 12 different types of loan journeys.
• ULI के माध्यम से 12 प्रकार की ऋण प्रक्रियाओं में 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
• The data services cover authentication and verification, land records from 8 States, satellite data, property search, dairy insights, transliteration, and credit guarantee services.
• डेटा सेवाओं में प्रमाणीकरण व सत्यापन, 8 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, संपत्ति खोज, डेयरी इनसाइट्स, ट्रांसलिटरेशन और क्रेडिट गारंटी सेवाएं शामिल हैं।
• ULI operates on a standardised, protocol-driven, open API-based plug-and-play architecture, eliminating complex one-to-one integrations between lenders and data providers.
• ULI एक मानकीकृत, प्रोटोकॉलआधारित-, ओपन API आधारित प्लगप्ले-एंड- संरचना पर कार्य करता है, जिससे ऋणदाताओं और डेटा प्रदाताओं के बीच जटिल वन की इंटीग्रेशन वन-टू- है। जाती हो समाप्त आवश्यकता
• RBI has not disclosed the total value of loans sanctioned through the ULI platform so far.
• RBI ने अब तक ULI प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकृत कुल ऋण राशि का खुलासा नहीं किया है।

Ques: Rediff.com India Limited has received final approval from which organisation to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP) for its digital payments platform 'RediffPay'?
रेडिफलिमि इंडिया कॉम.टेड को 'रेडिफपे' डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए थर्ड पार्टी-) प्रोवाइडर एप्लिकेशनTPAP) के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी किस संस्था से मिली है?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Ministry of Electronics & IT (MeitY) / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
E) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Rediff.com India Limited, a subsidiary of Infibeam Avenues Limited, received final approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
• इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी रेडिफ को लिमिटेड इंडिया कॉम.TPAP के रूप में कार्य करने के लिए NPCI से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई।
• Following the approval, the company initiated Closed User Group (CUG) testing of its digital payments platform 'RediffPay'.
• मंजूरी के बाद कंपनी ने अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म 'रेडिफपे' का क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप)CUG) परीक्षण शुरू किया।
• This testing phase is being conducted ahead of the public launch of RediffPay on the Unified Payments Interface (UPI).
• यह परीक्षण चरण UPI पर रेडिफपे के सार्वजनिक लॉन्च से पहले किया जा रहा है।

Ques: Which insurance company was penalised ₹1 crore by IRDAI for serious lapses related to claims settlement, policyholder protection, and corporate governance?
दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया?

A) Star Health and Allied Insurance / स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस
B) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस
C) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
D) Niva Bupa Health Insurance / निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस
E) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Care Health Insurance following a remote inspection.
• बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)IRDAI) ने रिमोट निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The penalty was levied due to serious lapses in claims settlement, policyholder protection, and corporate governance standards.
• यह दंड दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के कारण लगाया गया।
• The charges included failure in grievance redressal, cybersecurity lapses, lack of transparency in claims settlement, reinsurance accounting irregularities, and improper handling of unidentified proposal deposits.
• आरोपों में शिकायत निवारण में विफलता, साइबर सुरक्षा में चूक, दावों के निपटान में पारदर्शिता की कमी, पुनर्बीमा लेखांकन में अनियमितताएँ तथा अज्ञात प्रस्ताव जमा राशि के अनुचित प्रबंधन शामिल थे।

Ques: As per RBI data, what was the total value of bank frauds reported in the first half of FY26 (H1FY26)?
RBI के अनुसार FY26 की पहली छमाही)H1FY26) में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि कितनी थी?

A) ₹16,569 crore
B) ₹18,336 crore
C) ₹21,515 crore
D) ₹25,000 crore
E) ₹17,501 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• According to RBI data, banks reported 5,092 fraud cases amounting to ₹21,515 crore during the first half of FY26 (H1FY26).
• RBI के आँकड़ों के अनुसार FY26 की पहली छमाही)H1FY26) में बैंकों ने 5,092 मामलों में ₹21,515 करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी।
• The largest share of fraud value was related to advances (loans), accounting

for ₹17,501 crore across 4,255 cases.
• धोखाधड़ी की सबसे बड़ी राशि ऋणरही जुड़ी से एडवांस/, जिसमें 4,255 मामलों में ₹17,501 करोड़ शामिल थे।
• Other areas of fraud included deposits, foreign exchange transactions, and card/internet-based frauds.
• धोखाधड़ी के अन्य प्रमुख क्षेत्र जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और कार्ड आधारित इंटरनेट/ रहे। धोखाधड़ी
• Compared to H1FY25, when frauds worth ₹16,569 crore were reported, the amount increased while the number of cases declined in FY26.
• H1FY25 में ₹16,569 करोड़ की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई थी, यानी FY26 में राशि बढ़ी लेकिन मामलों की संख्या घटी।
• RBI clarified that the rise in value was mainly due to reclassification and re-reporting of earlier fraud cases.
• RBI के अनुसार राशि में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पुराने मामलों का पुनर्वर्गीकरण और पुनः रिपोर्टिंग है।
• To tackle digital frauds, the AI-driven MuleHunter.ai platform has been implemented in 23 banks as of 17 December 2025 to identify mule accounts.
• डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए AI आधारित MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म को 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया गया है, जो म्यूल खातों की पहचान में मदद करता है।

Ques: 'Gaj', the premium metal credit card, has been launched by which bank and is available exclusively for which category of customers?
'गज' प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विशेष रूप से किस वर्ग के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है?

A) HDFC Bank – Mass Retail Customers / एचडीएफसी बैंक – सामान्य ग्राहक
B) Axis Bank – Corporate Clients / एक्सिस बैंक – कॉरपोरेट ग्राहक
C) ICICI Bank – Premium Salary Account Holders / आईसीआईसीआई बैंक – प्रीमियम सैलरी खाताधारक
D) IDFC First Bank – High-Net-Worth Individuals (HNIs) / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक – उच्च) व्यक्ति मूल्य-निवल-HNIs)
E) SBI – Wealth Management Clients / एसबीआई – वेल्थ मैनेजमेंट ग्राहक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• 'Gaj' is a premium metal credit card launched by IDFC First Bank Limited on an invitation-only basis.
• 'गज' एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है, जिसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने केवल आमंत्रण है। किया लॉन्च पर आधार के (ओनली-इनविटेशन)
• The card is available exclusively for High-Net-Worth Individuals (HNIs).
• यह कार्ड विशेष रूप से उच्च) व्यक्तियों मूल्य-निवल-HNIs) के लिए उपलब्ध है।
• The joining fee for the 'Gaj' credit card is ₹12,500 plus applicable GST.
• 'गज' क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस ₹12,500 + लागू जीएसटी है।
• 'Gaj' represents the top tier of IDFC First Bank's premium metal credit card series known as the Ashva–Mayura–Gaj trilogy.
• 'गज' आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रीमियम मेटल कार्ड श्रृंखला 'अश्व–मयूर–गज' ट्रिलॉजी का शीर्ष स्तर है। (टियर टॉप)

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: How much does the Government of India plan to borrow through short-term Treasury Bills (T-Bills) over 12 weeks in Q4 of the current financial year?
भारत सरकार चालू वित्त वर्ष की Q4 में 12 सप्ताह के दौरान अल्पकालिक ट्रेजरी बिल)T-Bills) के माध्यम से कितनी राशि उधार लेने की योजना बना रही है?

A) ₹2.47 lakh crore
B) ₹3.94 lakh crore
C) ₹3.50 lakh crore
D) ₹4.10 lakh crore
E) ₹3.84 lakh crore

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India plans to borrow ₹3.84 lakh crore through short-term Treasury Bills over 12 weeks in Q4 to meet short-term funding requirements.
• भारत सरकार अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए Q4 में 12 सप्ताह के दौरान ₹3.84 लाख करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करेगी।
• Weekly T-Bill auctions will be in the range of ₹29,000 crore to ₹35,000 crore, as per the Finance Ministry.
• वित्त मंत्रालय के अनुसार साप्ताहिक T-Bill नीलामी ₹29,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ के बीच होगी।
• The planned Q4 borrowing is ₹10,000 crore lower than the ₹3.94 lakh crore raised in Q4 of the previous financial year.
• यह उधारी पिछले वित्त वर्ष की Q4 में जुटाए गए ₹3.94 लाख करोड़ से ₹10,000 करोड़ कम है।
• Earlier, the government had announced a Q3 T-Bill auction calendar of ₹2.47 lakh crore, ending on 31 December 2025.
• इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली Q3 T-Bill नीलामी योजना ₹2.47 लाख करोड़ की घोषित की थी।

Ques: Who published the *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition)*, which provides a consolidated and comparable statistical database for Indian States and Union Territories?
भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय डाटाबेस प्रदान करने वाली Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण(किसके द्वारा प्रकाशित की गई है?

A) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
B) NITI Aayog / नीति आयोग
C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
E) National Statistical Office / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition)* has been published by the Reserve Bank of India (RBI).
• *Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण(* भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) द्वारा प्रकाशित की गई है।
• The handbook serves as a consolidated and comparable statistical resource for Indian States and Union Territories, with time-series data available from 1951 onwards.
• यह पुस्तिका भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय संसाधन है, जिसमें 1951 से समयहै। उपलब्ध डेटा श्रृंखला-
• It is prepared by the Regional Economy Monitoring Division (REMD) under the Department of Economic and Policy Research (DEPR), using inputs from RBI regional offices and multiple data sources.
• इसे आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग)DEPR) के अंतर्गत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रभाग)REMD) द्वारा RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है।
• The 10th edition introduces a new External Sector section and adds 11 new state-wise statistical tables, enhancing analysis of regional trends and disparities.
• 10वें संस्करण में एक नया बाह्य क्षेत्र)External Sector) अनुभाग जोड़ा गया है तथा 11 नए राज्यहैं गई की शामिल तालिकाएँ सांख्यिकीय वार-, जिससे क्षेत्रीय प्रवृत्तियों और असमानताओं का विश्लेषण बेहतर होता है।

Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), which digital payment system accounted for the largest share in transaction volume during FY 2024–25?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लेन के संख्या की देन-आधार पर किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही?

A) RTGS / आरटीजीएस
B) NEFT / एनईएफटी
C) IMPS / आईएमपीएस
D) UPI / यूपीआई

E) Cheques / चेक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to the RBI report, the share of small-value retail digital payments is increasing rapidly in India.
• RBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे मूल्य के खुदरा डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है।
• During FY 2024–25, digital payments recorded a growth of 17.9 percent in value terms.
• वित्त वर्ष 2024–25 में डिजिटल भुगतानों में मूल्य के आधार पर 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
• Digital payments accounted for 97.6 percent of India's total payments in value terms, highlighting their dominance in the payment ecosystem.
• मूल्य के आधार पर भारत के कुल भुगतानों में डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी 97.6 प्रतिशत रही, जो इनके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
• In volume terms, digital payments witnessed a much higher growth of 35 percent during the year.
• लेनड पर आधार के संख्या की देन-िजिटल भुगतानों में 35 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि देखी गई।
• This surge in transaction volumes was mainly driven by the increasing use of digital modes for small-value transactions.
• यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेनउपय बढ़ते के माध्यमों डिजिटल में देन-ोग के कारण हुई।
• UPI emerged as the digital payment system with the largest share in transaction volume, reflecting its widespread adoption for everyday payments.
• UPI लेनउभरा बनकर माध्यम भुगतान डिजिटल बड़ा सबसे पर आधार के संख्या की देन-, जो दैनिक भुगतानों में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
• In contrast, RTGS accounted for the largest share in value terms, as it is primarily used for high-value transactions.
• इसके विपरीत, मूल्य के आधार पर RTGS की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही, क्योंकि इसका उपयोग मुख्यतः उच्च मूल्य के लेनहै। जाता किया लिए के देन-
• The RBI also noted that the average value of retail digital payments declined to ₹3,830 in 2024–25 from ₹4,382 in 2023–24, indicating a rise in smaller-ticket digital transactions.
• RBI ने यह भी बताया कि खुदरा डिजिटल भुगतानों का औसत मूल्य 2023–24 के ₹4,382

से घटकर 2024–25 में ₹3,830 हो गया, जो छोटे मूल्य के डिजिटल लेन को वृद्धि में देन-
है। दर्शाता

Ques: The nationwide campaign "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" (Your Money, Your Right) was concluded by which department?
"आपकी पूँजी, आपका अधिकार" अभियान का समापन किस विभाग द्वारा किया गया?

A) Department of Economic Affairs (DEA) / आर्थिक कार्य विभाग
B) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवाएँ विभाग
C) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
D) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
E) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Financial Services (DFS) concluded the nationwide campaign "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" on January 1, 2026.
• वित्तीय सेवाएँ विभाग)DFS) ने "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" राष्ट्रीय अभियान का समापन 1 जनवरी 2026 को किया।
• The campaign was launched on October 4, 2025, at Gandhinagar, Gujarat, and concluded on December 31, 2025, spanning three months.
• यह अभियान 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ, जिसकी अवधि तीन महीने रही।
• The strategy was built on three pillars: Awareness, Access, and Action, guided by the principle of Antyodaya.
• यह रणनीति तीन स्तंभों—जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई—पर आधारित थी, जिसे अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित किया गया।
• The campaign was conducted in phases across 748 districts and helped return around ₹4,200 crore of unclaimed assets to rightful owners or their heirs.
• यह अभियान देश के 748 जिलों में चरणबद्ध रूप से चलाया गया, जिससे लगभग ₹4,200 करोड़ की लावारिस संपत्ति वास्तविक हकदारों या उनके उत्तराधिकारियों को लौटाई गई।

• At the start of the campaign, it was estimated that the Indian financial system held over ₹1.84 lakh crore in unclaimed assets (including bank deposits, insurance, and dividends).
• अभियान की शुरुआत में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में ₹1.84 लाख करोड़ से अधिक की लावारिस संपत्ति (बैंक जमा, बीमा और लाभांश सहित) मौजूद थी।
• Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF): Insurance proceeds unclaimed for over 10 years are transferred here, though they remain claimable by beneficiaries for up to 25 years.
• वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (SCWF): 10 वर्षों से अधिक समय से लावारिस बीमा राशि यहाँ स्थानांतरित की जाती है, हालाँकि लाभार्थी 25 वर्षों तक इस पर दावा कर सकते हैं।
• Unclaimed bank deposits (inactive for 10 years) are transferred to the Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) maintained by the RBI.
• 10 वर्षों से निष्क्रिय लावारिस बैंक जमा राशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEA फंड) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

Ques: Which institution, in partnership with IDFC First Bank, launched a new cohort under the IGNITE programme to support technology startups?
IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में IGNITE कार्यक्रम के तहत नए स्टार्ट (कोहोर्ट) समूह अप-की ने संस्था किस शुरुआत की?

A) Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), IIT Delhi / फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर)FITT), आईआईटी दिल्ली
B) Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru / भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
C) NITI Aayog / नीति आयोग
D) Atal Innovation Mission / अटल इनोवेशन मिशन
E) Startup India / स्टार्टअप इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), the technology transfer and incubation arm of IIT Delhi, launched a new cohort of 15 startups under the Innovation Growth & Nurturing Initiative for Technology Entrepreneurs (IGNITE) programme.

• भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)IIT) दिल्ली की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और इनक्यूबेशन इकाई FITT ने IGNITE कार्यक्रम के तहत 15 स्टार्टकी। शुरुआत की कोहोर्ट नए के अप्स-
• The programme has been launched in partnership with IDFC First Bank.
• यह कार्यक्रम IDFC फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
• IGNITE is being implemented as part of IDFC First Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, in collaboration with FITT.
• IGNITE कार्यक्रम को IDFC फर्स्ट बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व)CSR) पहल के अंतर्गत FITT के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
• Under the programme, each selected startup receives non-dilutive funding of up to ₹30 lakh.
• इस कार्यक्रम के तहत चयनित प्रत्येक स्टार्ट को अप-₹30 लाख तक की नॉन डायल्यूटिव-ह जाती की प्रदान फंडिंगै।
• Mentorship is provided by IIT faculty, industry experts, and CSR leaders from IDFC First Bank.
• IIT के संकाय सदस्यों, उद्योग विशेषज्ञों और IDFC फर्स्ट बैंक के CSR लीडर्स द्वारा मेंटरशिप प्रदान की जाती है।

Ques: Which two institutions signed a Memorandum of Understanding to implement a nationwide Contact Point Verification system for Informal Micro Enterprises (IMEs)?
कौन) उद्यमों सूक्ष्म अनौपचारिक ने संस्थाओं दो सी-IMEs) के लिए देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

A) Department of Posts and RBI / डाक विभाग और RBI
B) Department of Posts and SIDBI / डाक विभाग और SIDBI
C) SIDBI and NABARD / SIDBI और NABARD
D) Ministry of MSME and SIDBI / MSME मंत्रालय और SIDBI
E) India Post Payments Bank and SIDBI / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और SIDBI

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Posts and the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) signed a landmark MoU to implement a nationwide Contact Point

Verification system.

• डाक विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)SIDBI) ने देशव्यापी कॉन्टैक्ट प्वाइंट वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• The initiative targets Informal Micro Enterprises registered on the Udyam Assist Platform (UAP).

• यह पहल उद्योगम असिस्ट प्लेटफॉर्म)UAP) पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करती है।

• The objective is to provide banks and NBFCs with reliable and verified data, enabling them to extend credit under Priority Sector Lending with greater confidence.

• इसका उद्देश्य बैंकों और NBFCs को विश्वसनीय एवं सत्यापित डेटा उपलब्ध कराना है, जिससे वे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आसानी से ऋण प्रदान कर सकें।

• The app captures geo-tagged photographs of business premises to prevent ghost or fraudulent registrations.

• ऐप व्यवसाय स्थल की जियोहै लेता तस्वीरें टैग्ड-, जिससे फर्जी या "घोस्ट" पंजीकरण रोके जा सकें।

• After successful verification, IMEs receive a Udyam Assist Certificate, which is treated at par with regular Udyam Registration for banking purposes.

• सफल सत्यापन के बाद IMEs को उद्योगम असिस्ट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिसे बैंकिंग उद्देश्यों के लिए सामान्य उद्योगम पंजीकरण के समकक्ष माना जाता है।

About SIDBI :

- Established : 1990
- HQ : Lucknow, Uttar Pradesh
- Chairman & MD : Manoj Mittal

Ques: Which country has introduced a new national currency with redesigned banknotes removing portraits of former leaders and undergoing redenomination?

किस देश ने पूर्व नेताओं के चित्र हटाकर और पुनर्मूल्यांकन राष्ट्रीय नई साथ के (रेडिनोमिनेशन) शुरू मुद्राकी है?

A) Lebanon / लेबनान
B) Iraq / इराक
C) Syria / सीरिया

D) Jordan / जॉर्डन
E) Egypt / मिस्र

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Syria has introduced a new national currency with redesigned banknotes.
• सीरिया ने नई डिज़ाइन वाली राष्ट्रीय मुद्रा की शुरुआत की है।
• The new banknotes have completely removed the portraits of ousted leader Bashar al-Assad and his father Hafez al-Assad, which earlier appeared on the 2,000 and 1,000 pound notes.
• नए बैंकनोटों से अपदस्थ नेता बशर अलपि उनके और असद-ता हाफ़िज़ अल चित्र के असद- हैं गए दिए हटा, जो पहले क्रमशः 2000 और 1000 पाउंड के नोटों पर थे।
• The redesigned currency now features agricultural and cultural symbols such as roses, wheat, olives, oranges, and mulberries, reflecting Syria's historical heritage.
• नई मुद्रा में गुलाब, गेहूं, जैतून, संतरे और शहतूत जैसे कृषि एवं सांस्कृतिक प्रतीक दर्शाए गए हैं, जो सीरिया की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं।
• The currency has undergone redenomination by removing two zeros to simplify daily transactions.
• दैनिक लेनदेन को सरल बनाने के लिए मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसमें दो शून्य हटाए गए हैं।
• Under the new system, 100 old Syrian pounds are equal to 1 new Syrian pound.
• नई व्यवस्था के अनुसार 100 पुराने सीरियाई पाउंड =1 नया सीरियाई पाउंड है।
• New denominations include 10, 25, 50, 100, 200, and 500 Syrian pounds.
• नई मुद्रा के मूल्यवर्ग 10, 25, 50, 100, 200 और 500 सीरियाई पाउंड हैं।
• The exchange period began on January 1, 2026, and will continue for 90 days, during which both old and new banknotes will circulate simultaneously.
• विनिमय अवधि 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई है और 90 दिनों तक चलेगी, इस दौरान पुराने और नए दोनों नोट साथरहेंगे। में प्रचलन साथ-

---

Ques: Under the RBI's Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs, which layer accounts for the largest share of total NBFC assets?

आरबीआई के स्केल) रेगुलेशन बेस्ड-SBR) ढांचे के तहत एनबीएफसी की कुल परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किस लेयर का है?

A) Base Layer (NBFC-BL) / बेस लेयर (बीएल-एनबीएफसी)
B) Middle Layer (NBFC-ML) / मिडिल लेयर (एमएल-एनबीएफसी)
C) Upper Layer (NBFC-UL) / अपर लेयर (यूएल-एनबीएफसी)
D) Top Layer / टॉप लेयर
E) All layers have equal share / सभी लेयरों का समान हिस्सा है

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Scale-Based Regulation (SBR) framework for NBFCs was introduced by the RBI in 2022 and classifies NBFCs into layers based on size, risk profile, and systemic importance.
• स्केल) रेगुलेशन बेस्ड-SBR) ढांचा आरबीआई द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, जो एनबीएफसी को आकार, जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत महत्व के आधार पर विभिन्न लेयरों में वर्गीकृत करता है।
• The Middle Layer (NBFC-ML) includes all deposit-taking NBFCs and non-deposit-taking NBFCs with assets of ₹1,000 crore and above.
• मिडिल लेयर)एनबीएफसी तथा एनबीएफसी वाली करने स्वीकार जमा सभी में (एमएल-₹1,000 करोड़ या उससे अधिक परिसंपत्ति वाली गैरहैं। शामिल एनबीएफसी जमा-
• This layer accounts for the largest share, i.e., 64.6% of total NBFC assets.
• इस लेयर का कुल एनबीएफसी परिसंपत्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 64.6% है।
• The Base Layer has a share of 5.2%, while the Upper Layer accounts for 30.2% of total NBFC assets.
• बेस लेयर का हिस्सा 5.2% है, जबकि अपर लेयर का कुल परिसंपत्तियों में 30.2% हिस्सा है।

Ques: Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) is India's first NBFC dedicated exclusively to which sector?
सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड)SMFCL) भारत का पहला एनबीएफसी किस क्षेत्र के लिए समर्पित है?

A) Road Infrastructure / सड़क अवसंरचना

B) Power & Energy / ऊर्जा एवं विद्युत
C) Maritime Sector / समुद्री क्षेत्र
D) Aviation Sector / विमानन क्षेत्र
E) Railway Infrastructure / रेलवे अवसंरचना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Sagarmala Finance Corporation Limited (SMFCL) has formally commenced its lending operations, marking a historic milestone.
• सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड)SMFCL) ने औपचारिक रूप से अपने ऋण परिचालन की शुरुआत की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
• It is India's first Non-Banking Financial Company (NBFC) dedicated exclusively to the maritime sector.
• यह भारत की पहली गैर) कंपनी वित्तीय बैंकिंग-NBFC) है, जो विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र को समर्पित है।
• SMFCL approved loans worth ₹4,300 crore during its 51st Board Meeting and is targeting a loan book of ₹8,000 crore by the end of the current financial year.
• SMFCL ने अपनी 51वीं बोर्ड बैठक में ₹4,300 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक ₹8,000 करोड़ के ऋण पोर्टफोलियो का लक्ष्य रखा है।
• The Board has approved an overall borrowing limit of ₹25,000 crore.
• बोर्ड ने कुल ₹25,000 करोड़ की उधारी सीमा को मंजूरी दी है।
• Major beneficiaries include a Greenfield Port Project with an allocation of ₹4,000 crore, Dredging Corporation of India (₹150 crore), and Goa Shipyard (₹110 crore) for indigenous shipbuilding.
• प्रमुख लाभार्थियों में ₹4,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)₹150 करोड़औ (र स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड)₹110 करोड़ (हैं। शामिल
• SMFCL is the nodal agency for the Maritime Development Fund (MDF) with a total corpus of ₹25,000 crore, comprising the Maritime Investment Fund (₹20,000 crore) and the Interest Incentivisation Fund (₹5,000 crore).
• SMFCL समुद्री विकास कोष)MDF) की नोडल एजेंसी है, जिसकी कुल राशि ₹25,000 करोड़ है, जिसमें मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड)₹20,000 करोड़ इंसेंटिवाइजेशन इंटरेस्ट और ( ) फंड₹5,000 करोड़हैं। शामिल (
• The corporation also plays a key role in channelising funds under the

Shipbuilding Financial Assistance Scheme (SBFAS), which has an outlay of ₹44,700 crore.
• यह निगम शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम)SBFAS) के तहत ₹44,700 करोड़ की सहायता राशि के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Ques: What was the total number of UPI transactions recorded in December 2025, marking an all-time high?
दिसंबर 2025 में UPI पर दर्ज किए गए कुल लेनदेन की संख्या कितनी थी, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है?

A) 18.45 billion
B) 19.80 billion
C) 20.12 billion
D) 21.63 billion
E) 22.90 billion

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• India's home-grown Unified Payments Interface (UPI) recorded an all-time high transaction volume of 21.63 billion transactions in December 2025.
• भारत के स्वदेशी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)UPI) ने दिसंबर 2025 में 21.63 बिलियन लेनदेन के साथ अब तक का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया।
• The total transaction value during the month stood at ₹27.97 lakh crore.
• इस महीने के दौरान कुल लेनदेन मूल्य ₹27.97 लाख करोड़ रहा।
• Transaction volumes grew by 29 per cent year-on-year, while transaction value increased by 20 per cent.
• लेनदेन की संख्या में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लेनदेन मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ा।
• On average, UPI handled about 698 million transactions per day with a daily transaction value of ₹90,217 crore.
• औसतन, UPI ने प्रतिदिन लगभग 698 मिलियन लेनदेन संभाले, जिनका दैनिक मूल्य ₹90,217 करोड़ रहा।
• In the calendar year 2025, UPI recorded around 228 billion transactions worth nearly ₹300 lakh crore, compared to 172 billion transactions worth

₹246.82 lakh crore in 2024.
• कैलेंडर वर्ष 2025 में UPI पर लगभग 228 बिलियन लेनदेन दर्ज किए गए, जिनका मूल्य करीब ₹300 लाख करोड़ था, जबकि 2024 में 172 बिलियन लेनदेन ₹246.82 लाख करोड़ के थे।

Ques : As per RBI stress tests, what is the expected GNPA ratio of NBFCs under the baseline scenario by September 2026?
आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक आधारभूत परिदृश्य में NBFC का GNPA अनुपात कितना होने का अनुमान है?

A) 2.3%
B) 2.5%
C) 2.7%
D) 2.9%
E) 3.5%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

• Under the baseline scenario, RBI's stress tests project that the system-level Gross Non-Performing Assets (GNPA) ratio of NBFCs will rise from 2.3% in September 2024 to 2.9% by September 2026.
• आधारभूत परिदृश्य के तहत, आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार NBFC का सकल गैर-) परिसंपत्ति निष्पादितGNPA) अनुपात सितंबर 2024 के 2.3% से बढ़कर सितंबर 2026 तक 2.9% होने का अनुमान है।
• This indicates a gradual deterioration in asset quality, although overall capital adequacy (CRAR) is expected to remain well above the regulatory minimum of 15%.
• यह परिसंपत्ति गुणवत्ता में धीरेहै दर्शाता को गिरावट धीरे-, हालांकि समग्र पूंजी पर्याप्तता)CRAR) नियामकीय न्यूनतम 15% से काफी ऊपर बनी रहने का अनुमान है।
• RBI also highlighted uneven resilience within the NBFC sector, with 8 NBFCs potentially falling below the minimum CRAR threshold even under the baseline scenario.
• आरबीआई ने NBFC क्षेत्र में असमान लचीलापन की ओर संकेत किया, जिसमें आधारभूत परिदृश्य में ही 8 NBFCs का CRAR न्यूनतम सीमा से नीचे जाने की संभावना है।

Ques: What key change has the Ministry of Corporate Affairs introduced regarding KYC compliance for company directors under the Companies Act, 2013?
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी निदेशकों के लिए KYC अनुपालन को लेकर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कौनहै किया बदलाव प्रमुख सा-?

A) Mandatory monthly KYC filing / अनिवार्य मासिक KYC फाइलिंग
B) Replacement of annual KYC with once-in-five-years filing / वार्षिक KYC को पाँच वर्ष में एक बार की फाइलिंग से बदलना
C) Replacement of annual KYC with once-in-three-years simplified KYC / वार्षिक KYC को तीन वर्ष में एक बार सरल KYC से बदलना
D) Complete removal of KYC requirement for directors / निदेशकों के लिए KYC आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करना
E) KYC filing applicable only to newly appointed directors / केवल नए नियुक्त निदेशकों पर KYC फाइलिंग लागू करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Ministry of Corporate Affairs has eased compliance norms for company directors by replacing the mandatory annual KYC filing with a simplified KYC requirement once every three years.
• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी निदेशकों के लिए अनिवार्य वार्षिक KYC फाइलिंग को हटाकर तीन वर्ष में एक बार सरल KYC की व्यवस्था लागू की है।
• This change follows a review of Rule 12A of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014, based on the recommendations of the High-Level Committee on Non-Financial Regulatory Reforms and stakeholder suggestions.
• यह बदलाव कंपनियाँ नियम (अर्हता एवं नियुक्ति की निदेशकों), 2014 के नियम 12A की समीक्षा के बाद किया गया है, जो गैर की समिति उच्चस्तरीय पर सुधारों विनियामक वित्तीय- है। आधारित पर सुझावों के हितधारकों और सिफारिशों
• The amended rules were notified on December 31, 2025, and will come into effect from March 31, 2026.
• संशोधित नियमों को 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किया गया और ये 31 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे।

• Under the revised framework, directors must submit a simplified KYC intimation once every three years instead of filing KYC annually.
• संशोधित ढांचे के तहत, निदेशकों को अब हर वर्ष के बजाय तीन वर्ष में एक बार सरल KYC सूचना देनी होगी।
• The revised KYC Form can be used for KYC compliance, updating mobile number, email address, residential address, and re-activation of Director Identification Number (DIN).
• संशोधित KYC फॉर्म का उपयोग KYC अनुपालन, मोबाइल नंबर, ईपता मेल-, आवासीय पता अद्यतन करने तथा DIN के पुनः सक्रियण के लिए किया जा सकता है।
• Digital signature verification by the director and certification by a professional will be mandatory only when the KYC form is submitted for updating mobile number, email address, or residential address.
• डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन और किसी पेशेवर द्वारा प्रमाणन केवल तभी अनिवार्य होगा, जब KYC फॉर्म मोबाइल नंबर, ई दाखिल लिए के अद्यतन के पते आवासीय या मेल- जाए। किया
• Directors who have already completed their KYC requirements are covered under the new provisions, and their next KYC filing will be due by June 30, 2028.
• जिन निदेशकों ने अब तक अपना KYC पूरा कर लिया है, वे नए प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे और उनकी अगली KYC फाइलिंग 30 जून 2028 तक देय होगी।
• Directors who have not yet submitted their KYC Form can continue to get their DIN re-activated under existing provisions till March 31, 2026.
• जिन निदेशकों ने अब तक KYC फॉर्म जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च 2026 तक मौजूदा प्रावधानों के तहत अपना DIN पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

Ques : What percentage of the FY26 Budget Estimate did India's fiscal deficit reach during April–November 2025?
अप्रैल–नवंबर 2025 के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा FY26 बजट अनुमान का कितना प्रतिशत रहा?

A) 52.5%
B) 58.4%
C) 60.1%
D) 62.3%
E) 65.0%

Answer : Option D

Explanation | व्याख्या:

• According to data released by the Controller General of Accounts (CGA), India's fiscal deficit during April–November FY26 stood at **₹9.77 trillion**, which is **62.3% of the Budget Estimate (BE)** for the full financial year 2025–26.
• कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) CGA) के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 में भारत का राजकोषीय घाटा **₹9.77 ट्रिलियन** रहा, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का **62.3%** है।
• In the same period last year, the fiscal deficit was **₹8.5 trillion (52.5% of BE)**, indicating a higher pace of spending in the current fiscal.
• पिछले वर्ष इसी अवधि में राजकोषीय घाटा **₹8.5 ट्रिलियन)BE का 52.5%)** था, जिससे चालू वित्त वर्ष में व्यय की तेज़ गति स्पष्ट होती है।
• The rise in the deficit was mainly driven by a **28% year-on-year increase in capital expenditure**, even as **non-tax revenues remained strong**, supported by higher dividends from PSUs, public sector banks, and the RBI.
• घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण **पूंजीगत व्यय में 28% की वार्षिक वृद्धि** रही, हालांकि **PSU, सरकारी बैंकों और RBI से अधिक लाभांश** मिलने से गैर मजबूत राजस्व कर-बना रहा।
• The Centre has targeted a **fiscal deficit of 4.4% of GDP for FY26**.
• केंद्र सरकार ने FY26 के लिए **GDP के 4.4%** का राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा है।

Ques: Which group has received in-principle approval from SEBI to act as sponsor and establish a new Mutual Fund?
किस समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और नया म्यूचुअल फंड स्थापित करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

A) Motilal Oswal Group / मोतीलाल ओसवाल समूह
B) Edelweiss Group / एडलवाइस समूह
C) Ashika Group / आशिका समूह
D) JM Financial Group / जेएम फाइनेंशियल समूह
E) IIFL Group / आईआईएफएल समूह

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Ashika Group has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to act as a sponsor and establish Ashika Mutual Fund.
• आशिका समूह को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और आशिका म्यूचुअल फंड की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) सेबी (से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है।
• This approval allows the group to form an Asset Management Company (AMC) and initiate preparations for launching mutual fund schemes, subject to final registration.
• इस मंजूरी के तहत समूह को एसेट मैनेजमेंट कंपनी) AMC) गठित करने और अंतिम पंजीकरण के अधीन म्यूचुअल फंड योजनाओं की तैयारी करने की अनुमति मिली है।
• Ashika Group was established in 1994 and operates as a comprehensive financial services platform.
• आशिका समूह की स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक वित्तीय सेवा मंच के रूप में कार्य करता है।

Ques: Who has been given additional charge as the interim Managing Director & CEO of Canara Bank?
केनरा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है?

A) Satyanarayana Raju | सत्यनारायण राजू
B) Brajesh Kumar Singh | ब्रजेश कुमार सिंह
C) Hardeep Singh Ahluwalia | हरदीप सिंह अहलूवालिया
D) Rajnish Kumar | रजनीश कुमार
E) Ashok Chandra | अशोक चंद्र

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या:

• Canara Bank has assigned the additional charge of Managing Director & CEO to its Executive Director, Hardeep Singh Ahluwalia, with effect from January 1, 2026.

• केनरा बैंक ने 1 जनवरी 2026 से अपने कार्यकारी निदेशक हरदीप सिंह अहलूवालिया को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
• The interim appointment will remain valid for three months, or until a regular MD & CEO is appointed, or until further orders.
• यह अंतरिम नियुक्ति तीन महीनों के लिए या नियमित एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।
• The decision follows the superannuation of the incumbent MD & CEO, Satyanarayana Raju.
• यह निर्णय वर्तमान एमडी एवं सीईओ सत्यनारायण राजू के सेवानिवृत्त होने के बाद लिया गया है।
• Hardeep Singh Ahluwalia joined the banking sector in 1992 as an Agricultural Field Officer at Allahabad Bank (now Indian Bank) and has over three decades of experience across diverse banking segments.
• हरदीप सिंह अहलूवालिया ने 1992 में इलाहाबाद बैंक) अब इंडियन बैंक (में कृषि क्षेत्र अधिकारी के रूप में बैंकिंग करियर शुरू किया था और उन्हें विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
• The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) has recommended Brajesh Kumar Singh, currently Executive Director at Indian Bank, as the next regular MD & CEO of Canara Bank.
• वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो) FSIB) ने वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक के अगले नियमित एमडी एवं सीईओ के रूप में सिफारिश की है।

Ques: What decision did the Department of Economic Affairs (DEA) take regarding Small Savings Schemes (SSS) interest rates for January–March 2026?
जनवरी–मार्च 2026 के लिए लघु बचत योजनाओं)SSS) की ब्याज दरों को लेकर आर्थिक कार्य विभाग)DEA) ने क्या निर्णय लिया?

A) Interest rates were increased / ब्याज दरें बढ़ाई गईं
B) Interest rates were reduced / ब्याज दरें घटाई गईं
C) Interest rates were kept unchanged / ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी गईं
D) Only select schemes saw a hike / केवल कुछ योजनाओं में वृद्धि हुई
E) Quarterly revision system was discontinued / तिमाही संशोधन प्रणाली समाप्त की गई

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance kept interest rates unchanged for all Small Savings Schemes from January 01, 2026 to March 31, 2026, continuing the rates of Q3FY26.
• वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को Q3FY26 के समान अपरिवर्तित रखा।
• This is the 8th consecutive quarter with no change in SSS interest rates.
• यह लगातार आठवीं तिमाही है जब SSS की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• The interest rates were last revised in Q4FY24.
• SSS की ब्याज दरों में अंतिम संशोधन Q4FY24 में किया गया था।
• Small Savings Schemes are Government of India–backed instruments that promote household savings and provide risk-free investment options.
• लघु बचत योजनाएं भारत सरकार समर्थित साधन हैं, जिनका उद्देश्य घरेलू बचत को बढ़ावा देना और जोखिमहै। देना विकल्प निवेश मुक्त-
• Since 2016, SSS interest rates have been notified quarterly by the DEA based on bond yields and market trends.
• 2016 से SSS की ब्याज दरें बॉन्ड यील्ड और बाजार रुझानों के आधार पर तिमाही रूप से DEA द्वारा अधिसूचित की जाती हैं।
• The methodology for determining SSS interest rates was recommended by the श्यामला गोपीनाथ समिति in January 2023.
• SSS की ब्याज दर तय करने की पद्धति जनवरी 2023 में श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाई गई थी।
• The committee recommended rates should be 25 to 100 basis points higher than government bond yields.
• समिति ने सुझाव दिया कि इन योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड से 25 से 100 बेसिस प्वाइंट अधिक होनी चाहिए।

Interest Rates on Small Savings Schemes for Q4FY26 (1st January, 2026 to 31st March, 2026):

- Post Office Savings Deposit : 4.0%
- 1-Year Post Office Time Deposits : 6.9%
- 2-Year Post Office Time Deposits : 7.0%
- 3-Year Post Office Time Deposits : 7.1%
- 5-Year Post Office Time Deposits : 7.5%

- 5-Year Post Office Recurring Deposits : 6.7%
- Kisan Vikas Patra : 7.5% (will mature in 115 months)
- Public Provident Fund : 7.1%
- Sukanya Samriddhi Yojana : 8.2%
- National Savings Certificate : 7.7%
- Senior Citizen Savings Scheme : 8.2%
- Post Office Monthly Income Scheme : 7.4%
- Mahila Samman Savings Certificate : 7.5%

Ques: What is the title of the podcast series launched by the Reserve Bank of India to enhance public communication?
सार्वजनिक संचार को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला का नाम क्या है?

A) RBI Speaks: Economy Explained / RBI स्पीक्सएक्सप्लेंड इकोनॉमी :
B) Paisa aur Arthvyavastha / पैसा और अर्थव्यवस्था
C) RBI Talks: Paisa to Policy / RBI टॉक्सपॉलिसी टू पैसा :
D) Monetary Matters by RBI / RBI द्वारा मॉनेटरी मैटर्स
E) Policy to Public / पॉलिसी टू पब्लिक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India proposed adding podcasts to its communication toolkit to widely disseminate information of public interest.
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए पॉडकास्ट को अपने संचार साधनों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
• Accordingly, RBI launched its podcast series titled “RBI Talks: Paisa to Policy.”
• इसके तहत RBI ने “RBI Talks: Paisa to Policy” नामक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की।
• The first episode of the series is titled “Demystifying KYC.”
• इस श्रृंखला का पहला एपिसोड “Demystifying KYC” शीर्षक से जारी किया गया है।

Ques: What is the key objective of RBI's NBFC (Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026?
RBI द्वारा जारी NBFC (पूंजी पर्याप्तता विवेकपूर्ण मानदंडनिर्देश संशोधन (, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) Increasing capital requirements for all NBFC loans / सभी NBFC ऋणों के लिए पूंजी आवश्यकता बढ़ाना
B) Providing subsidies for infrastructure projects / अवसंरचना परियोजनाओं को सब्सिडी देना
C) Easing capital adequacy norms for NBFC lending to high-quality infrastructure projects / उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी मानदंडों में ढील देना
D) Restricting NBFC exposure to infrastructure sector / NBFC के अवसंरचना क्षेत्र में जोखिम को सीमित करना
E) Introducing new licensing norms for NBFCs / NBFC के लिए नए लाइसेंसिंग नियम लागू करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The RBI has eased capital adequacy norms for Non-Banking Finance Companies (NBFCs) lending to high-quality infrastructure projects through Amendment Directions, 2026.
• RBI ने उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने वाले NBFC के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है।
• Risk weight has been reduced to 75% if at least 2% of sanctioned project debt is repaid, instead of the earlier draft requirement of 5% but less than 10%.
• यदि स्वीकृत परियोजना ऋण का कम से कम 2% चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 75% होगा।
• A lower 50% risk weight will apply if at least 5% of the sanctioned project debt is repaid, relaxed from the earlier 10% threshold.
• यदि कम से कम 5% ऋण चुका दिया गया है, तो जोखिम भार 50% होगा।
• The directions will be applicable from April 1, 2026, or earlier if adopted fully by an NBFC.
• ये निर्देश 1 अप्रैल 2026 से या NBFC द्वारा पहले अपनाने पर लागू होंगे।
• A project will be considered high-quality if it has completed one year after

Commercial Operation Date (COD), has no material covenant breach, and is classified as standard.
• परियोजना को उच्च गुणवत्ता वाली माना जाएगा यदि COD के बाद एक वर्ष पूरा हो चुका हो और वह स्टैंडर्ड श्रेणी में हो।
• NBFCs may continue existing risk weights until the next review or March 31, 2027, whichever is earlier.
• NBFC अगले पुनरीक्षण या 31 मार्च 2027 तक मौजूदा जोखिम भार जारी रख सकते हैं।

Ques: What percentage of ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 has been returned so far?
19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के नोटों में से अब तक कितना प्रतिशत वापस आ चुका है?

A) 95.20%
B) 96.85%
C) 97.40%
D) 98.41%
E) 99.10%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The total value of ₹2000 banknotes in circulation was ₹3.56 lakh crore on May 19, 2023, when their withdrawal was announced.
• 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों की कुल प्रचलित राशि ₹3.56 लाख करोड़ थी।
• This value declined sharply to ₹5,669 crore by the close of business on December 31, 2025.
• 31 दिसंबर 2025 तक यह घटकर ₹5,669 करोड़ रह गई।
• As a result, 98.41% of the ₹2000 banknotes in circulation as on May 19, 2023 have been returned.
• इस प्रकार 19 मई 2023 को प्रचलन में मौजूद ₹2000 के 98.41% नोट वापस आ चुके हैं।
• The facility for deposit and/or exchange was available at all bank branches till October 7, 2023.
• जमा या विनिमय की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।
• Exchange of ₹2000 banknotes continues at 19 RBI Issue Offices since May 19,

2023.
• ₹2000 के नोटों के विनिमय की सुविधा 19 RBI इश्यू कार्यालयों में 19 मई 2023 से उपलब्ध है।

Ques: What is the interest rate on the RBI Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) for the period January–June 2026?
जनवरी–जून 2026 की अवधि के लिए RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य की (है क्या दर ब्याज?

A) 7.70%
B) 7.85%
C) 8.00%
D) 8.05%
E) 8.35%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The interest rate on the Floating Rate Savings Bond, 2020 (Taxable) has been announced for the period January 1, 2026 to June 30, 2026.
• फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, 2020 (करयोग्य दर ब्याज की (1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए घोषित की गई है।
• The bond carries a floating interest rate, which is reset every six months, and has a maturity period of seven years.
• इस बॉन्ड की ब्याज दर परिवर्तनीय है, जिसे हर छह महीने में रीसेट किया जाता है, और इसकी परिपक्वता अवधि सात वर्ष है।
• Interest on the bond is paid twice a year, on January 1 and July 1.
• इस बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
• The coupon rate is fixed at 35 basis points (0.35%) above the National Savings Certificate (NSC) rate.
• कूपन दर राष्ट्रीय बचत पत्र)NSC) की ब्याज दर से 35 बेसिस पॉइंट)0.35%) अधिक निर्धारित की जाती है।
• For the current half-year, the NSC rate is 7.70%, making the FRSB interest rate 8.05%.
• वर्तमान अर्धवार्षिक अवधि के लिए NSC की दर 7.70% है, जिससे FRSB की ब्याज दर

8.05% बनती है।
• Interest for this period will be paid on July 1, 2026, and since the bond is taxable, the interest is added to income and taxed as per applicable slabs.
• इस अवधि का ब्याज 1 जुलाई 2026 को दिया जाएगा और यह करयोग्य होगा, जिसे आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

Ques: Asian Development Bank (ADB) provided ₹4,100 crore assistance to which state for Musi Riverfront Development Project Phase-I?
एशियाई विकास बैंक)ADB) ने मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना चरण-I के लिए किस राज्य को ₹4,100 करोड़ की सहायता दी?

A) Telangana / तेलंगाना
B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
D) Karnataka / कर्नाटक
E) Maharashtra / महाराष्ट्र

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Asian Development Bank provided ₹4,100 crore (USD 500 million) to the Government of Telangana.
• एशियाई विकास बैंक ने तेलंगाना सरकार को ₹4,100 करोड़)500 मिलियन अमेरिकी डॉलरकिए। प्रदान (
• The amount was given to the Minister for Industries and Commerce, Government of Telangana.
• यह राशि तेलंगाना सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री को दी गई।
• The assistance is for Phase-I of the Musi Riverfront Development Project.
• यह सहायता मुसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना के प्रथम चरण के लिए है।
• The project aims to rejuvenate and restore the Musi River.
• इस परियोजना का उद्देश्य मुसी नदी का पुनर्जीवन करना है।

Ques: Who chaired the first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB)?
पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड)PRB) की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?

A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
B) S Krishnan / एसकृष्णन .
C) T Rabi Sankar / टीशंकर रबी .
D) Aruna Sundararajan / अरुणा सुंदरराजन
E) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The first meeting of the Payments Regulatory Board (PRB) was held in Mumbai under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.
• पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड)PRB) की पहली बैठक मुंबई में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई।
• The Board reviewed the functioning of the Department of Payment and Settlement Systems and domestic and global payment systems.
• बोर्ड ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग तथा घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों की समीक्षा की।
• The draft Payments Vision 2028 was presented for strategic guidance.
• ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028 प्रस्तुत किया गया।
• PRB was constituted after amendment to the Payment and Settlement Systems Act, 2007, effective from 9 May 2025.
• PRB का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में 9 मई 2025 से प्रभावी संशोधन के बाद किया गया।
• PRB replaced the Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS).
• PRB ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड)BPSS) का स्थान लिया।
• Members present included S Krishnan, Nagaraju Maddirala, Aruna Sundararajan, T Rabi Sankar, and Vivek Deep.
• बैठक में एसकृष्णन ., नागराजू मड्डीराला, अरुणा सुंदरराजन, टी विवेक और शंकर रबी . थे। उपस्थित दीप

Ques: Who has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank?
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) R. P. Ramakrishnan / आररामकृष्णन .पी .
B) Karthikeyan Manickam / कार्तिकेयन मणिक्कम
C) K. Paul Thomas / केथॉमस पॉल .
D) Rajnish Kumar / रजनीश कुमार
E) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Karthikeyan Manickam, former Executive Director (ED) of Bank of India, has been appointed as the Chairman of ESAF Small Finance Bank (ESAF SFB).
• बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक)ED) कार्तिकेयन मणिक्कम को ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
• He replaced R. P. Ramakrishnan in this position.
• उन्होंने इस पद पर आरहै। लिया स्थान का रामकृष्णन .पी .
• ESAF Small Finance Bank was established on 10 March 2017.
• ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई थी।
• The headquarters of ESAF Small Finance Bank is located in Thrissur, Kerala.
• ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय त्रिशूर, केरल में स्थित है।
• Shri K. Paul Thomas is the Managing Director and CEO of the bank.
• श्री के) निदेशक प्रबंध के बैंक थॉमस पॉल .MD) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) हैं।

Ques: Which bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card offering zero foreign exchange markup for frequent international travellers?
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शून्य विदेशी मुद्रा) फॉरेक्स (मार्कअप वाला ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• IDFC FIRST Bank launched the Zero-Forex Diamond Reserve Credit Card as a premium offering for frequent international travellers.
• आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रीमियम ज़ीरो-फॉरेक्स डायमंड रिज़र्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
• The card provides zero foreign exchange (forex) markup along with travel and lifestyle rewards.
• यह कार्ड शून्य विदेशी मुद्रा) फॉरेक्स (मार्कअप के साथ यात्रा और लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स प्रदान करता है।
• The annual fee is ₹3,000 plus GST, which is waived from the second year on annual spends of ₹6 lakh.
• इसका वार्षिक शुल्क ₹3,000 प्लस जीएसटी है, जो ₹6 लाख के वार्षिक खर्च पर दूसरे वर्ष से माफ कर दिया जाता है।

Ques: What time lag has SEBI proposed for sharing and using price data in investor education and awareness programmes?
निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के साझा करने और उपयोग के लिए सेबी ने कितने समय के अंतराल) टाइम लैग (का प्रस्ताव किया है?

A) 1 day
B) 7 days
C) 15 days
D) 30 days
E) 90 days

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• SEBI has proposed a uniform 30-day time lag for sharing and using price data

in investor education and awareness programmes.
• सेबी ने निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में मूल्य डेटा के उपयोग के लिए 30 दिनों के समान समय अंतराल का प्रस्ताव किया है।
• The proposal aims to prevent misuse of sensitive market data while ensuring educational content remains relevant and timely for investors.
• इस प्रस्ताव का उद्देश्य संवेदनशील बाजार डेटा के दुरुपयोग को रोकते हुए निवेशकों के लिए शैक्षिक सामग्री को प्रासंगिक बनाए रखना है।
• This move replaces the earlier system where exchanges shared data with a one-day lag while educators could use only data that was at least three months old.
• यह कदम पुराने तंत्र की जगह लेता है, जिसमें एक्सचेंज एक दिन की देरी से डेटा साझा करते थे जबकि शिक्षकों को कम से कम तीन महीने पुराने डेटा का उपयोग करना पड़ता था।

Ques: With which institution did the Delhi Government sign an MoU to bring its finances under a complete banking, cash management, and debt management framework for the first time?
दिल्ली सरकार ने पहली बार अपनी बैंकिंग, नकद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन व्यवस्था को किस संस्था के अंतर्गत लाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन)MoU) पर हस्ताक्षर किए?

A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) NITI Aayog / नीति आयोग
E) Comptroller and Auditor General / नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• The Delhi Government signed a Memorandum of Understanding with the Reserve Bank of India to operate under RBI's complete banking, cash management, and debt management framework for the first time.
• दिल्ली सरकार ने पहली बार भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण बैंकिंग, नकद प्रबंधन और

ऋण प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत कार्य करने के लिए RBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• This move aligns Delhi's financial governance with nationally accepted fiscal practices.

• यह कदम दिल्ली की वित्तीय व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राजकोषीय प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

• The Reserve Bank of India traditionally acts as banker and debt manager for state governments.

• भारतीय रिज़र्व बैंक परंपरागत रूप से राज्य सरकारों के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक की भूमिका निभाता है।

• RBI manages state governments' borrowings, cash balances, and debt instruments under frameworks approved by the Centre.

• RBI केंद्र द्वारा स्वीकृत ढांचे के तहत राज्यों की उधारी, नकद शेष और ऋण साधनों का प्रबंधन करता है।

Ques: Which bank will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees through a Special Rupee Vostro Account?

भारत और इज़राइल के बीच भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से कौन सा बैंक सुगम बनाएगा?

A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's largest lender, the State Bank of India, will facilitate bilateral trade settlements between India and Israel in Indian rupees.

• भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, भारत और इज़राइल के बीच रुपये में द्विपक्षीय व्यापार निपटान को सुगम बनाएगा।

• The move is aligned with ongoing discussions between the two countries

towards a comprehensive Free Trade Agreement.
• यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में चल रही चर्चाओं से जुड़ा है।
• Under the mechanism, Israeli exporters and importers will make and receive payments in rupees through a Special Rupee Vostro Account linked to trade invoices.
• इस व्यवस्था के तहत इज़राइली निर्यातक और आयातक व्यापार चालानों से जुड़े विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये में भुगतान करेंगे।
• SBI's Tel Aviv branch has obtained all regulatory approvals to operationalise the arrangement and is promoting awareness among stakeholders.
• एसबीआई की तेल अवीव शाखा ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी नियामक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ा रही है।

Ques: Which company became the first payments firm in India, the Middle East, APAC, and South Africa to receive the ISO/IEC 42001 certification for Artificial Intelligence Management Systems?
भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी?

A) Paytm / पेटीएम
B) Razorpay / रेज़रपे
C) PhonePe / फोनपे
D) NPCI / एनपीसीआई
E) Financial Software and Systems (FSS) / फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Financial Software and Systems (FSS) became the first payments company across India, the Middle East, APAC, and South Africa to earn the ISO/IEC 42001 certification.
• फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स) FSS) भारत, मध्य पूर्व, एशिया-प्रशांत और दक्षिण अफ्रीका में ISO/IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी।
• ISO/IEC 42001 is the world's first international standard for Artificial

Intelligence Management Systems (AIMS).
• ISO/IEC 42001 कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबंधन प्रणाली) AIMS) के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है।
• The certification recognises organisations that demonstrate responsible, ethical, and trustworthy use of artificial intelligence.
• यह प्रमाणन एआई के जिम्मेदार, नैतिक और विश्वसनीय उपयोग को प्रदर्शित करने वाले संगठनों को मान्यता देता है।

Ques: Which bank launched 'The Fortuna Wave' as its refreshed brand identity to signal modernization and future-readiness?
आधुनिकीकरण और भविष्य लिए के दर्शाने को तैयारी-'द फॉर्चुना वेव' नामक नया ब्रांड पहचान किस बैंक ने लॉन्च किया?

A) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
B) Federal Bank Limited / फेडरल बैंक लिमिटेड
C) Bandhan Bank / बंधन बैंक
D) Yes Bank / यस बैंक
E) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Federal Bank Limited launched 'The Fortuna Wave', a refreshed brand identity, in Mumbai in the presence of Vidya Balan, the bank's brand ambassador.
• फेडरल बैंक लिमिटेड ने मुंबई में बैंक की ब्रांड एंबेसडर विद्या बालन की उपस्थिति में 'द फॉर्चुना वेव' नामक नई ब्रांड पहचान लॉन्च की।
• The new identity reflects the bank's transformation from a locally trusted institution into a national player with a growing global presence.
• यह नई पहचान बैंक के एक स्थानीय रूप से विश्वसनीय संस्थान से राष्ट्रीय स्तर के और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति वाले खिलाड़ी में परिवर्तन को दर्शाती है।

About Federal Bank :

- Established : 1931

- HQ : Kochi, Kerala
- MD & CEO : KVS Manian
- Tagline : Your Perfect Banking Partner

Ques: **Which public sector bank was the most penalised by RBI in FY25 by value?**
FY25 में RBI द्वारा मूल्य के आधार पर सबसे अधिक जुर्माना किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर लगाया गया?

A) Canara Bank / केनरा बैंक
B) Indian Bank / इंडियन बैंक
C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
D) Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• In FY25 / CY25, the Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties totaling about ₹8.78 crore on Public Sector Banks (PSBs) for regulatory and compliance violations.
• FY25 / CY25 में भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)PSBs) पर नियामक और अनुपालन उल्लंघनों के लिए कुल मिलाकर लगभग ₹8.78 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• State Bank of India (SBI) was the most penalised PSB, with a penalty of ₹1.72 crore.
• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)SBI) पर ₹1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जो सबसे अधिक था।
• The penalty on SBI was mainly due to non-compliance with Priority Sector Lending (PSL) norms and deposit account regulations.
• SBI पर जुर्माना मुख्य रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)PSL) और जमा खाता नियमों के अनुपालन से जुड़ी कमियों के कारण लगाया गया।
• Other PSBs penalised include Canara Bank (₹1.63 crore), Indian Bank (₹1.61 crore), Bank of India (₹1 crore), and Union Bank of India, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, and PNB (₹29.60 lakh to ₹63.60 lakh).

• अन्य दंडित बैंकों में केनरा बैंक)₹1.63 करोड़(, इंडियन बैंक)₹1.61 करोड़(, बैंक ऑफ इंडिया)₹1 करोड़(, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और PNB (₹29.60 लाख से ₹63.60 लाखहैं। शामिल (
• RBI imposes such penalties to ensure regulatory compliance and strengthen banking discipline.
• RBI ऐसे दंड नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और बैंकिंग अनुशासन मजबूत करने के लिए लगाता है।

Ques: Till which date is the Special Revival Campaign launched by LIC for reviving lapsed individual policies valid?
LIC द्वारा लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया विशेष पुनरुद्धार अभियान किस तिथि तक मान्य है?

A) 31 December 2025
B) 31 March 2026
C) 2 March 2026
D) 30 June 2026
E) 1 January 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) has launched a Special Revival Campaign to revive lapsed individual policies.
• भारतीय जीवन बीमा निगम) LIC) ने लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू किया है।
• The campaign is applicable from 1 January 2026 to 2 March 2026.
• यह अभियान 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
• Policies can be revived within five years from the date of the first unpaid premium.
• पॉलिसियों को पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है।
• The maximum late fee concession allowed under the scheme is ₹5,000. For outstanding premium up to ₹1 lakh, a concession of up to ₹3,000 is provided.
• इस योजना के तहत लेट फीस पर अधिकतम ₹5,000 तक की छूट दी जाएगी।₹1 लाख

तक के बकाया प्रीमियम पर ₹3,000 तक की छूट मिलेगी।
• For premium between ₹1,00,001 and ₹3 lakh, the concession is up to ₹4,000. For premium of ₹3,00,001 and above, concession up to ₹5,000 is available.
• ₹1,00,001 से ₹3 लाख के बीच प्रीमियम पर ₹4,000 तक की छूट दी जाएगी।₹3,00,001 या उससे अधिक प्रीमियम पर ₹5,000 तक की छूट उपलब्ध है।
• In micro-insurance plans, 100% concession on late fee will be given.
• माइक्रो-इंश्योरेंस योजनाओं में लेट फीस पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।

Ques: Which private sector bank faced the highest monetary penalty by value in CY25?
CY25 में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक मौद्रिक जुर्माना किस निजी क्षेत्र के बैंक पर लगाया गया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) Jammu & Kashmir Bank / जम्मू एंड कश्मीर बैंक
E) Yes Bank / यस बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• In FY25 / CY25, the Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties totalling about ₹16.28 crore on private sector banks for various regulatory and compliance violations.
• FY25 / CY25 में भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने विभिन्न विनियामक और अनुपालन उल्लंघनों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर कुल लगभग ₹16.28 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
• Among all private sector banks, Jammu & Kashmir Bank faced the highest single monetary penalty by value.
• सभी निजी क्षेत्र के बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर मूल्य के आधार पर सबसे अधिक एकल जुर्माना लगाया गया।
• The RBI imposed a penalty of ₹3.31 crore on Jammu & Kashmir Bank in March 2025.

• मार्च 2025 में RBI ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर ₹3.31 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The violations included deficiencies in loan-related practices and non-compliance with customer protection norms.
• उल्लंघनों में ऋण से जुड़ी प्रक्रियाओं में कमी और ग्राहक संरक्षण मानदंडों का अनुपालन न करना शामिल था।
• Due to this, Jammu & Kashmir Bank emerged as the most penalised private sector bank by value in CY25.
• इसी कारण CY25 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक मूल्य के आधार पर सबसे अधिक दंडित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया।

Ques: Which regulator notified the phased rollout of revised net worth and liquid net worth requirements for existing Merchant Bankers through amendments to the 1992 regulations?

मर्चेंट बैंकरों के लिए 1992 के विनियमों में संशोधन कर संशोधित नेटवर्थ एवं लिक्विड नेटवर्थ आवश्यकताओं के चरणबद्ध क्रियान्वयन की अधिसूचना किस नियामक ने जारी की?

A) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) SEBI / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
C) IRDAI / बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
D) PFRDA / पेंशन निधि विनियामक
E) MCA / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI amended the SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992, now called the SEBI (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025.
• सेबी ने 1992 के मर्चेंट बैंकर विनियमों में संशोधन कर 2025 संशोधन विनियम लागू किए।
• Net worth requirement: Category-I ₹25 crore by 02 Jan 2027 and ₹50 crore by 02 Jan 2028; Category-II ₹7.5 crore by 02 Jan 2027 and ₹10 crore by 02 Jan 2028.
• नेटवर्थ आवश्यकता-श्रेणी :I ₹25 करोड़)02 जनवरी 2027) व ₹50 करोड़)02 जनवरी

2028); श्रेणी-II ₹7.5 करोड़)02 जनवरी 2027) व ₹10 करोड़)02 जनवरी 2028)।
• Liquid Net Worth (LNW): Category-I ₹6.25 crore (2027) and ₹12.5 crore (2028); Category-II ₹1.875 crore (2027) and ₹2.5 crore (2028).
• लिक्विड नेटवर्थ-श्रेणी :I ₹6.25 करोड़)2027) व ₹12.5 करोड़)2028); श्रेणी-II ₹1.875 करोड़)2027) व ₹2.5 करोड़)2028)।
• Underwriting limit capped at 20 times of LNW, defined as unencumbered liquid assets like cash, bank deposits, G-Secs and select MF units.
• अंडरराइटिंग सीमा LNW के 20 गुना तक, जिसमें नकद, बैंक जमा, सरकारी प्रतिभूतियाँ व चयनित म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
• Minimum revenue over 3 years mandated: ₹25 crore (Category-I) and ₹5 crore (Category-II), failing which registration may be cancelled.
• 3 वर्षों में न्यूनतम राजस्व अनिवार्य :₹25 करोड़ -श्रेणी)I) व ₹5 करोड़ -श्रेणी)II), अन्यथा पंजीकरण रद्द हो सकता है।
• Independent compliance officer to be appointed by 03 April 2026; principal officers need 5 years' market experience with one-year compliance window.
• 03 अप्रैल 2026 तक स्वतंत्र अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति; प्रिंसिपल ऑफिसर हेतु 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक।
• Core merchant banking activities cannot be outsourced and existing arrangements must be unwound by 03 April 2026.
• मुख्य मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों का आउटसोर्सिंग निषिद्ध, 03 अप्रैल 2026 तक मौजूदा व्यवस्थाएँ समाप्त करनी होंगी।
• MBs cannot manage issues where connected persons hold over 0.1% equity or shares exceeding ₹10 lakh (whichever is lower).
• जिन मामलों में संबंधित व्यक्तियों की हिस्सेदारी 0.1% या ₹10 लाख से (हो कम जो) हो अधिक, वहाँ इश्यू प्रबंधन प्रतिबंधित है।

Ques: Which State recorded the highest growth in own tax revenue (excluding Union taxes) during April–November FY26?
अप्रैल–नवंबर FY26 के दौरान केंद्र के करों के हिस्से को छोड़कर स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की?

A) Gujarat / गुजरात
B) Maharashtra / महाराष्ट्र
C) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
D) Karnataka / कर्नाटक
E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• As per data released by the Comptroller and Auditor General (C&AG), Karnataka recorded the highest growth rate in States' own tax revenue during April–November FY26, excluding the share of Union taxes.
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)C&AG) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 के दौरान केंद्र के करों के हिस्से को छोड़कर राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक ने दर्ज की।
• Karnataka was followed by Maharashtra and Uttar Pradesh in terms of growth rate, though in absolute tax collection Maharashtra and Uttar Pradesh remain ahead of Karnataka.
• कर राजस्व की वृद्धि दर में कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे, हालांकि कुल कर संग्रह के वास्तविक आंकड़ों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अब भी कर्नाटक से आगे हैं।
• The growth in tax revenue was influenced by post-GST rate rationalisation, which particularly impacted SGST collections.
• कर राजस्व वृद्धि पर GST दरों के युक्तिकरण का प्रभाव पड़ा, जिससे विशेष रूप से SGST संग्रह प्रभावित हुआ।
• In capital expenditure (capex), Gujarat emerged as the leading State, followed by Maharashtra and Karnataka.
• पूंजीगत व्यय रहा पर शीर्ष गुजरात में मामले के (कैपेक्स), उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे।
• Several States are increasing capital expenditure aggressively to strengthen infrastructure in line with the Centre's push, while keeping fiscal deficits within recommended limits.
• कई राज्य केंद्र की नीति के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आक्रामक रूप से कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि राजकोषीय घाटा अनुशंसित सीमा के भीतर बना हुआ है।

Ques: Which bank integrated the RBI's Central Bank Digital Currency (Digital Rupee – e₹) into its online merchant payment platform SmartGateway?
किस बैंक ने RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया डिजिटल)– e₹) को अपने

ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म SmartGateway में एकीकृत किया है?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation :

• HDFC Bank included the Digital Rupee (e₹), the Reserve Bank of India's (RBI) Central Bank Digital Currency (CBDC), into their online merchant payment platform, SmartGateway.
• एचडीएफसी बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की केंद्रीय डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) डिजिटल रुपी (ई₹) को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्टगेटवे में शामिल कर लिया है।
• It's As a result, in addition to current payment methods like UPI, cards, and net banking, SmartGateway merchants may now take payments using the Digital Rupee at no transaction fee.
• इसके परिणामस्वरूप, यूपीआई, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे मौजूदा भुगतान तरीकों के अलावा, स्मार्टगेटवे के व्यापारी अब बिना किसी लेनदेन शुल्क के डिजिटल रुपी का उपयोग करके भी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

About HDFC Bank :

- Established : August 1994
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Sashidhar Jagdishan
- Tagline : We Understand Your World

Ques: Tamilnad Mercantile Bank (TMB) has partnered with which fintech company to strengthen its UPI acquiring and issuing capabilities?

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक)TMB) ने अपनी UPI अधिग्रहण और जारी करने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है?

A) TechFini / टेकफिनी
B) Razorpay / रेज़रपे
C) PayU / पेयू
D) PhonePe / फोनपे
E) NPCI / एनपीसीआई

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Tamilnad Mercantile Bank has entered into a strategic partnership with TechFini to enhance its UPI acquiring and issuing capabilities.
• तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने अपनी UPI अधिग्रहण और जारी करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टेकफिनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
• Under the collaboration, TechFini will act as the Technology Service Provider for TMB and manage UPI switching through its TechFini UPI Switch.
• इस सहयोग के तहत, टेकफिनी TMB के लिए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा और अपने TechFini UPI स्विच के माध्यम से UPI स्विचिंग का प्रबंधन करेगा।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of HSBC Private Bank?

HSBC प्राइवेट बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Jane Fraser / जेन फ्रेजर
B) Ida Liu / आइडा लियू
C) Alison Rose / एलिसन रोज
D) Nuno Matos / नूनो माटोस
E) Georges Elhedery / जॉर्जेस एलहदरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Ida Liu has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of HSBC Private Bank.
• आइडा लियू को HSBC प्राइवेट बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) नियुक्त किया गया है।
• Prior to joining HSBC, she served as the Global Head of Citi Private Bank since 2007.
• HSBC में शामिल होने से पहले, वह 2007 से सिटी प्राइवेट बैंक की ग्लोबल हेड के रूप में कार्यरत थीं।
• HSBC Private Bank is headquartered in Geneva, Switzerland, and its Chairman is Peter Widmer.
• HSBC प्राइवेट बैंक का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके चेयरमैन पीटर विडमर हैं।

Ques: What is the maximum dividend payout cap proposed for commercial banks, small finance banks and payments banks under the revised framework?
संशोधित ढांचे के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों के लिए अधिकतम लाभांश वितरण सीमा क्या प्रस्तावित की गई है?

A) 60% of net profit / शुद्ध लाभ का 60%
B) 70% of net profit / शुद्ध लाभ का 70%
C) 75% of net profit / शुद्ध लाभ का 75%
D) 80% of net profit / शुद्ध लाभ का 80%
E) No upper limit / कोई ऊपरी सीमा नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Under the proposed framework, dividend payouts are capped at 75% of net

profit for commercial banks, small finance banks and payments banks.
• प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों के लिए लाभांश वितरण की सीमा शुद्ध लाभ के 75% तक निर्धारित की गई है।
• Regional rural banks and local area banks will be allowed to distribute dividends up to 80% of net profit.
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लोकल एरिया बैंकों को शुद्ध लाभ का 80% तक लाभांश वितरित करने की अनुमति होगी।
• Banks incorporated in India must report positive adjusted profit after tax for the relevant period to be eligible for dividend payout.
• भारत में स्थापित बैंकों को पात्र होने के लिए संबंधित अवधि में सकारात्मक समायोजित कर पश्चात लाभ दिखाना अनिवार्य होगा।
• Foreign banks operating through branches must have positive profit after tax from Indian operations to remit earnings to their head offices.
• शाखा मोड में कार्यरत विदेशी बैंकों को अपने मुख्यालय को लाभ भेजने के लिए भारतीय परिचालन से कर पश्चात सकारात्मक लाभ होना आवश्यक है।
• The proposed directions apply to commercial banks, small finance banks, payments banks, regional rural banks and local area banks.
• ये प्रस्तावित दिशानिर्देश वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंकों पर लागू होंगे।
• The revised directions also cover all commercial banks, including State Bank of India and foreign banks operating in India through branches.
• संशोधित दिशानिर्देश भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों और भारत में शाखा के माध्यम से कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू होंगे।
• Eligible foreign banks can remit profits to their head offices without prior RBI approval, subject to audited accounts and continued compliance with capital requirements.
• पात्र विदेशी बैंक, खातों के ऑडिट और पूंजी आवश्यकताओं के अनुपालन की शर्त पर, RBI की पूर्व अनुमति के बिना अपने मुख्यालय को लाभ प्रेषित कर सकेंगे।

Ques: What is the purpose of the Supervisory Data Quality Index (sDQI) created by the Reserve Bank of India?
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स)sDQI) का उद्देश्य क्या है?

A) To assess profitability of banks / बैंकों की लाभप्रदता का आकलन
B) To measure data quality in regulatory returns / नियामकीय रिटर्न में डेटा गुणवत्ता

का मापन
C) To rank banks based on customer service / ग्राहक सेवा के आधार पर बैंकों की रैंकिंग
D) To evaluate credit growth / ऋण वृद्धि का मूल्यांकन
E) To monitor monetary transmission / मौद्रिक संचरण की निगरानी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has created the Supervisory Data Quality Index (sDQI) to measure the quality of data submitted by banks.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता को मापने के लिए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स)sDQI) बनाया है।
• The index evaluates data quality based on accuracy, timeliness, completeness and consistency in submission of regulatory returns.
• यह सूचकांक नियामकीय रिटर्न के प्रस्तुतिकरण में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता के आधार पर डेटा गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।
• RBI reported that the sDQI score of Scheduled Commercial Banks improved to 90.7 in the September 2025 quarter from 89.9 in April–June 2025.
• RBI के अनुसार, सितंबर 2025 तिमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का sDQI स्कोर अप्रैल–जून 2025 की 89.9 से बढ़कर 90.7 हो गया।
• Among bank groups, Small Finance Banks recorded the highest sDQI score of 91.5, followed by Public Sector Banks at 91.1.
• बैंक समूहों में स्मॉल फाइनेंस बैंकों का sDQI स्कोर सबसे अधिक 91.5 रहा, इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 91.1 रहा।
• Private Sector Banks (90.6) and Foreign Banks (90.4) also remained in the “good” category.
• निजी क्षेत्र के बैंक)90.6) और विदेशी बैंक)90.4) भी “अच्छी” श्रेणी में रहे।
• In September 2025, no Scheduled Commercial Bank scored below 80, indicating overall improvement in data quality.
• सितंबर 2025 में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का स्कोर 80 से नीचे नहीं रहा, जो डेटा गुणवत्ता में समग्र सुधार को दर्शाता है।
• As per sDQI grading: less than 70 indicates “major concerns”, 70–80 “needs improvement”, 80–90 “acceptable”, and above 90 “good”.
• sDQI ग्रेडिंग के अनुसार :70 से कम “गंभीर चिंता”, 70–80 “सुधार आवश्यक”, 80–90 “स्वीकार्य” और 90 से अधिक “अच्छा” दर्शाता है।

• The sDQI currently covers 87 Scheduled Commercial Banks and assesses returns related to asset quality, liquidity, risk-based supervision, and capital adequacy.
• sDQI वर्तमान में 87 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है और परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता, जोखिम का रिटर्न संबंधित से पर्याप्तता पूंजी और पर्यवेक्षण आधारित- है। करता मूल्यांकन

Ques: Which bank has introduced the 'Safety Centre' feature on its mobile banking app to enhance protection against digital fraud?
डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'Safety Centre' फीचर किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर शुरू किया है?

A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Axis Bank has introduced a new feature called 'Safety Centre' on its mobile banking app to strengthen customer protection against digital fraud.
• एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर 'Safety Centre' नामक नया फीचर शुरू किया है।
• The initiative aims to provide customers with greater control over digital banking security and fraud prevention.
• इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra

- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: How many Non-Banking Financial Companies (NBFCs) had their Certificate of Registration (CoR) cancelled by the RBI during December 2025, including voluntary surrenders?
दिसंबर 2025 के दौरान RBI द्वारा कितन (सहित समर्पण स्वैच्छिक)ी नॉन बैंकिंग-) कंपनियों फाइनेंशियलNBFCs) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया?

A) 35
B) 45
C) 50
D) 51
E) 55

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the Certificate of Registration (CoR) of 35 NBFCs for non-compliance with regulatory requirements.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने नियामकीय आवश्यकताओं का पालन न करने पर 35 NBFCs का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया।
• These cancellations were effective between December 9 and December 31, 2025.
• ये रद्दीकरण 9 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रभावी हुए।
• Additionally, 16 NBFCs voluntarily surrendered their CoR to the RBI. This brought the total number of cancelled registrations to 51 NBFCs.
• इसके अतिरिक्त, 16 NBFCs ने स्वेच्छा से अपना CoR RBI को सौंप दिया। इससे कुल रद्द पंजीकरणों की संख्या 51 NBFCs हो गई।
• RBI exercised its powers under Section 45-IA(6) of the RBI Act, 1934.
• RBI ने यह कार्रवाई RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) के अंतर्गत की।

Ques: Which entity launched the 'Axis Finance Vyapar Business Loan', a collateral-free credit solution for Micro and Small Enterprises (MSEs) in India?

'एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन', जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों)MSEs) के लिए एक बिना गारंटी ऋण समाधान है, किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया?

A) Axis Bank Limited / एक्सिस बैंक लिमिटेड
B) Axis Finance Limited / एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) SIDBI / सिडबी
E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Axis Finance Limited (AFL), a wholly owned subsidiary of Axis Bank Limited, launched the 'Axis Finance Vyapar Business Loan'.
• एक्सिस बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड)AFL) ने 'एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन' लॉन्च किया।
• The loan is a collateral-free credit solution designed for Micro and Small Enterprises (MSEs) across semi-urban and rural markets in India.
• यह ऋण भारत के अर्धक् ग्रामीण और शहरी-षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों)MSEs) के लिए एक बिना गारंटी का ऋण समाधान है।
• The product offers collateral-free loans up to Rs 10 lakh with flexible repayment tenures.
• इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण और लचीली पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाती है।
• In addition, Axis Bank also launched the Safety Centre on its mobile banking application to enhance digital banking security for customers.
• इसके अलावा, एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर ग्राहकों की डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर भी लॉन्च किया।

Ques: What is the purpose of the Capital Gains Account Scheme (CGAS) authorised by the Government of India?
भारत सरकार द्वारा अधिकृत कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम)CGAS) का उद्देश्य क्या है?

A) To provide short-term loans to taxpayers / करदाताओं को अल्पकालिक ऋण देना
B) To deposit unutilised long-term capital gains and claim tax exemption / अप्रयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जमा कर कर छूट का दावा करना
C) To promote savings among non-residents / अनिवासी भारतीयों में बचत को बढ़ावा देना
D) To invest capital gains directly in equity markets / पूंजीगत लाभ को सीधे इक्विटी बाजार में निवेश करना
E) To replace existing capital gains tax provisions / मौजूदा पूंजीगत लाभ कर प्रावधानों को प्रतिस्थापित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Capital Gains Account Scheme (CGAS) is authorised by the Government of India to help taxpayers manage uninvested long-term capital gains or sale proceeds of specified capital assets.
• कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम)CGAS) भारत सरकार द्वारा अधिकृत योजना है, जो निर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अप्रयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को सुरक्षित रखने में सहायता करती है।
• The scheme allows taxpayers to deposit such uninvested amounts in a designated bank account.
• यह योजना करदाताओं को अप्रयुक्त राशि को एक विशेष बैंक खाते में जमा करने की अनुमति देती है।
• By depositing under CGAS, taxpayers can earn interest, claim tax exemption, and plan reinvestment for a period of up to three years.
• CGAS के अंतर्गत राशि जमा करने से करदाता ब्याज अर्जित कर सकते हैं, कर छूट का लाभ ले सकते हैं और तीन वर्ष तक पुनर्निवेश की योजना बना सकते हैं।
• From 1 January 2026, the scheme is applicable to Resident Individuals and Hindu Undivided Families (HUFs).
• 1 जनवरी 2026 से यह योजना निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों)HUFs) पर लागू होगी।
• CGAS accounts can be opened at ICICI Bank branches, excluding rural

branches, as per the scheme rules.
• CGAS खाते ICICI बैंक की शाखाओं में खोले जा सकते हैं, लेकिन योजना के नियमों के अनुसार ग्रामीण शाखाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।

Ques: According to the IRDAI Annual Report 2024–25, what does the rise in Unfair Business Practices (UFBP) grievances indicate in India's insurance sector?
IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, बीमा क्षेत्र में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं)UFBP) से संबंधित शिकायतों में वृद्धि क्या दर्शाती है?

A) Improvement in customer awareness / ग्राहकों की जागरूकता में सुधार
B) Decline in insurance penetration / बीमा पैठ में गिरावट
C) Rising concerns related to mis-selling / मिसबढ़त जुड़ी से सेलिंग-ी चिंताएँ
D) Reduction in total insurance policies / कुल बीमा पॉलिसियों में कमी
E) Increase in global insurance density / वैश्विक बीमा घनत्व में वृद्धि

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) released its Annual Report for 2024–25 highlighting trends in grievances, penetration, and density.
• भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)IRDAI) ने 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शिकायतों, बीमा पैठ और घनत्व से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं।
• Mis-selling refers to the sale of insurance products without proper disclosure of terms and conditions, product features, or suitability to customer needs.
• मिसशर्तों बिना बिक्री की उत्पादों बीमा है अर्थ का सेलिंग-, विशेषताओं या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूपता की सही जानकारी दिए।
• Such practices lead to higher premiums, frequent policy lapses, and erosion of customer trust.
• इससे प्रीमियम का बोझ बढ़ता है, पॉलिसी लैप्स होती हैं और ग्राहकों का भरोसा कम होता है।
• Total grievances related to life insurers remained almost unchanged at 1,20,726 in 2023–24 and 1,20,429 in 2024–25.

• जीवन बीमा कंपनियों से जुड़ी कुल शिकायतें 2023–24 में 1,20,726 और 2024–25 में 1,20,429 रहीं, यानी लगभग स्थिर रहीं।
• However, UFBP-related grievances increased from 23,335 in 2023–24 to 26,667 in 2024–25.
• लेकिन अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से जुड़ी शिकायतें 2023–24 में 23,335 से बढ़कर 2024–25 में 26,667 हो गईं।
• The share of UFBP grievances rose from 19.33 percent in FY24 to 22.14 percent in FY25, indicating growing mis-selling concerns.
• कुल शिकायतों में UFBP की हिस्सेदारी FY24 में 19.33 प्रतिशत से बढ़कर FY25 में 22.14 प्रतिशत हो गई, जो मिसहै। दर्शाती को समस्या बढ़ती की सेलिंग-
• Insurance penetration in India stood at 3.7 percent in FY25, much lower than the global average of 7.3 percent.
• FY25 में भारत की बीमा पैठ 3.7 प्रतिशत रही, जो वैश्विक औसत 7.3 प्रतिशत से काफी कम है।
• Life insurance penetration declined from 2.8 percent in FY24 to 2.7 percent in FY25, while non-life insurance remained unchanged at 1 percent.
• जीवन बीमा पैठ FY24 में 2.8 प्रतिशत से घटकर FY25 में 2.7 प्रतिशत हो गई, जबकि नॉन-बीमा लाइफ1 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
• Insurance density increased marginally from 95 dollars in FY24 to 97 dollars in FY25, showing a gradual upward trend since 2016–17.
• बीमा घनत्व FY24 में 95 डॉलर से बढ़कर FY25 में 97 डॉलर हो गया, जो 2016–17 से निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

Ques: Which company has received a ₹1,000 crore, 10-year ATM cash outsourcing contract from SBI?
SBI से ₹1,000 करोड़ का 10-वर्षीय ATM कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है?

A) Hitachi Payments / हिटाची पेमेंट्स
B) FIS Global / एफआईएस ग्लोबल
C) CMS Info Systems Ltd / CMS इंफो सिस्टम्स लिमिटेड
D) NCR Corporation / एनसीआर कॉर्पोरेशन
E) AGS Transact / एजीएस ट्रांजैक्ट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India (SBI) has awarded a ₹1,000 crore, 10-year cash outsourcing contract to CMS Info Systems Ltd.
• भारतीय स्टेट बैंक)SBI) ने CMS Info Systems Ltd को ₹1,000 करोड़ का 10-वर्षीय कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
• This is the first direct large cash outsourcing contract awarded by a PSU bank.
• यह किसी PSU बैंक द्वारा दिया गया पहला प्रत्यक्ष बड़ा कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है।
• The contract covers 5,000 SBI-owned ATMs across India, including managed services, improved cash efficiency, and higher ATM uptime.
• यह अनुबंध पूरे भारत में SBI के 5,000 स्वामित्व वाले ATM को कवर करता है, जिसमें मैनेज्ड सर्विसेज, बेहतर कैश दक्षता और उच्च ATM अपटाइम शामिल हैं।
• The contract is expected to go live this month.
• यह कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने शुरू)go live) होने की उम्मीद है।
• CMS Info Systems is a leading player in ATM management and cash logistics services in India.
• CMS Info Systems भारत में ATM प्रबंधन और कैश लॉजिस्टिक्स सेवाओं की अग्रणी कंपनी है।

Ques: According to the RBI's draft amendments, what is the minimum cooling-off period required for a director who has completed 10 years of continuous tenure on the board of a co-operative bank before being eligible for re-appointment to the same bank?
RBI के मसौदा संशोधनों के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में 10 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशक को उसी बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितना कूलिंग-होगा करना पूरा पीरियड ऑफ?

A) One year / एक वर्ष
B) Two years / दो वर्ष
C) Three years / तीन वर्ष
D) Five years / पाँच वर्ष
E) No cooling-off period / कोई कूलिंगनहीं अवधि ऑफ-

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Under the draft amendments issued by the RBI, a director who has completed 10 years of continuous tenure on the board of a UCB, State Co-operative Bank, or Central Co-operative Bank will be eligible for re-appointment to the same bank only after a minimum cooling-off period of three years.
• RBI द्वारा जारी मसौदा संशोधनों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक)UCB), राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड में 10 वर्षों का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाला निदेशक कम से कम तीन वर्ष के कूलिंग पात्र का पुनर्नियुक्ति में बैंक उसी ही बाद के पीरियड ऑफ- होगा।
• During this cooling-off period, the director cannot be associated with the bank in any capacity other than as a regular member or customer.
• इस कूलिंग अलावा के ग्राहक या सदस्य सामान्य से बैंक निदेशक दौरान के अवधि ऑफ- सकता। रह नहीं जुड़ा में भूमिका भी किसी
• The restriction does not prevent such individuals from being appointed as directors on the board of another co-operative bank.
• यह प्रतिबंध ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य सहकारी बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने से नहीं रोकता।
• For calculating continuous tenure, the RBI will count the total time served on the boards of UCBs, State Co-operative Banks, and Central Co-operative Banks, including periods before any interruption of less than three years.
• निरंतर कार्यकाल की गणना के लिए RBI शहरी, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा की कुल अवधि को शामिल करेगा, जिसमें तीन वर्ष से कम के अंतराल से पहले की अवधि भी जोड़ी जाएगी।
• However, periods of directorship preceding an interruption of at least three years will be excluded from the calculation.
• हालांकि, कम से कम तीन वर्षों के अंतराल से पहले की निदेशक अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

Ques: Which public sector bank has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to set up a wholly-owned subsidiary for undertaking Standalone Primary Dealer (SPD) business?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर)SPD) व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को मिली है?

A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) Canara Bank / केनरा बैंक
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda (BoB) has secured in-principle approval from the RBI to convert its existing Bank Primary Dealer (PD) authorization into a wholly-owned subsidiary for undertaking Standalone Primary Dealer (SPD) business.
• बैंक ऑफ बड़ौदा)BoB) को अपने मौजूदा बैंक प्राइमरी डीलर)PD) प्राधिकरण को स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर)SPD) के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंज़ूरी मिली है।
• Primary Dealers are authorised to buy and sell Government Securities (G-Secs), such as bonds and Treasury Bills (T-bills), directly from the RBI and resell them in the market.
• प्राइमरी डीलर्स को RBI से सीधे सरकारी प्रतिभूतियाँ)G-Secs) जैसे बॉन्ड और ट्रेज़री बिल)T-bills) खरीदने और बेचने की अनुमति होती है।
• In India, Primary Dealers are classified into two categories: Bank PDs and Standalone Primary Dealers (SPDs).
• भारत में प्राइमरी डीलर्स को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है बैंक :PDs और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स)SPDs)।
• Bank PDs are specialised departments within existing commercial banks, while SPDs are subsidiaries of Scheduled Commercial Banks (SCBs).
• बैंक PDs मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के भीतर विशेष विभाग होते हैं, जबकि SPDs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों)SCBs) की सहायक कंपनियाँ होती हैं।
• The RBI introduced the system of Primary Dealers in 1995 to strengthen the infrastructure of the Government Securities market.
• RBI ने सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए 1995 में प्राइमरी डीलर प्रणाली की शुरुआत की थी।
• Currently, there are 7 Standalone Primary Dealers (SPDs) and 14 bank-affiliated PDs operating in India.
• वर्तमान में भारत में 7 स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स)SPDs) और 14 बैंक प्राइमरी संबद्ध-

हैं कार्यरत डीलर्स।
• RBI has increased the aggregate limit available to SPDs under the Standing Liquidity Facility at the existing repo rate from ₹10,000 crore to ₹15,000 crore, effective from 2 April 2025.
• RBI ने स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत SPDs को उपलब्ध कुल सीमा को मौजूदा रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ कर दिया है, जो 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
- HQ : Vadodara, Gujarat
- Tagline : India's International Bank
- MD & CEO : Debadatta Chand

Ques: Which company has received a contract from India Post Payments Bank (IPPB) to launch a comprehensive digital investment platform for its customers across India?
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)IPPB) से देशभर के ग्राहकों के लिए एक व्यापक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शुरू करने का अनुबंध किस कंपनी को मिला है?

A) Choice Wealth Private Limited / चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
B) CAMS Investor Services / कैम्स इन्वेस्टर सर्विसेज
C) Karvy Fintech / कार्वी फिनटेक
D) Zerodha Broking Limited / ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड
E) HDFC Securities / एचडीएफसी सिक्योरिटीज

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Choice Wealth Private Limited has received a contract from India Post Payments Bank (IPPB) to launch a comprehensive digital investment platform.
• चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)IPPB) से एक व्यापक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शुरू करने का अनुबंध मिला है।

• This platform will enable IPPB customers across the country to seamlessly access formal financial investment services.
• यह प्लेटफॉर्म IPPB के देशभर के ग्राहकों को औपचारिक वित्तीय निवेश सेवाओं तक सहज रूप से पहुँच प्रदान करेगा।
• India Post Payments Bank Limited (IPPB) was established in 2017.
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड)IPPB) की स्थापना 2017 में हुई थी।

About India Post Payments Bank Limited (IPPB):

- Established : 2017
- HQ : New Delhi, Delhi
- CEO & MD : R. Viswesvaran
- Tagline : Your Bank at Your Doorstep

Ques: Which company has received the Reserve Bank of India (RBI)'s approval to operate as both Payment Aggregator–Physical (PA-P) and Cross-Border Payment Aggregator (PA-CB)?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल)PA-P) और क्रॉस पेमेंट बॉर्डर-) एग्रीगेटरPA-CB) के रूप में संचालन की मंज़ूरी किस कंपनी को मिली है?

A) Paytm / पेटीएम
B) PhonePe / फोनपे
C) Razorpay / रेज़रपे
D) PayG / पेजी-
E) Cashfree / कैशफ्री

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• PayG has secured approval from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator–Physical (PA-P) and Cross-Border Payment Aggregator (PA-CB).
• पे) जी-PayG) को पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल)PA-P) और क्रॉस) एग्रीगेटर पेमेंट बॉर्डर-PA-CB) के रूप में संचालन के लिए RBI की मंज़ूरी मिली है।
• With this approval, PayG has completed its full suite of Payment Aggregator

licences under the RBI regulatory framework.
• इस मंज़ूरी के साथ PayG ने RBI के नियामक ढांचे के अंतर्गत पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसों का पूरा सेट प्राप्त कर लिया है।
• The company can now facilitate digital transactions across multiple modes such as online, offline (in-person), and cross-border use cases.
• कंपनी अब ऑनलाइन, ऑफलाइन में माध्यमों विभिन्न जैसे बॉर्डर-क्रॉस और (पर्सन-इन) है। सकती बना सक्षम को देन-लेन डिजिटल
• PayG was established in 2021 and is headquartered in Bengaluru, Karnataka.
• PayG की स्थापना 2021 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

Ques: According to the First Advance Estimates (FAE) released by NSO, what is the projected real GDP growth rate of India for FY2025–26?
NSO द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान)FAE) के अनुसार FY2025–26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है?

A) 6.5%
B) 6.8%
C) 7.0%
D) 7.4%
E) 8.0%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The National Statistics Office (NSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), released the First Advance Estimates (FAE) of GDP for FY2025–26 at constant (2011–12) and current prices.
• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)NSO) ने FY2025–26 के लिए GDP के प्रथम अग्रिम अनुमान)FAE) स्थिर)2011–12) और चालू मूल्यों पर जारी किए।
• As per the estimates, real GDP growth for FY26 is projected at 7.4%, higher than 6.5% recorded in FY25.
• अनुमान के अनुसार FY26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.4% रहने की संभावना है, जो FY25 के 6.5% से अधिक है।
• Real GDP at constant prices is estimated at ₹201.90 lakh crore in FY26,

compared to ₹187.97 lakh crore in FY25.
• स्थिर मूल्यों पर वास्तविक GDP FY26 में ₹201.90 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि FY25 में यह ₹187.97 लाख करोड़ थी।
• Nominal GDP growth is estimated at 8% in FY26, lower than 10.4% in FY25, with nominal GDP at current prices pegged at ₹357.14 lakh crore in FY26, up from ₹330.68 lakh crore in FY25.
• नाममात्र GDP वृद्धि FY26 में 8% अनुमानित है, जो FY25 के 10.4% से कम है। चालू मूल्यों पर नाममात्र GDP FY26 में ₹357.14 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो FY25 में ₹330.68 लाख करोड़ थी।
• Gross Value Added (GVA) at constant prices is estimated at ₹184.50 lakh crore in FY26, registering a growth of 7.3%.
• स्थिर मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन)GVA) FY26 में ₹184.50 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• Nominal GVA is estimated at ₹323.48 lakh crore in FY26, growing by 7.7%, compared to ₹300.22 lakh crore in FY25.
• नाममात्र GVA FY26 में ₹323.48 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें 7.7% की वृद्धि हुई है, जबकि FY25 में यह ₹300.22 लाख करोड़ था।

Ques: Which company recently launched 'PhonePe PG Bolt' for Visa and Mastercard transactions to provide secure and efficient in-app payments?
कौन सी कंपनी ने हाल ही में Visa और Mastercard लेन लिए के देन-'PhonePe PG Bolt' लॉन्च किया, जो इनहै बनाता प्रभावी और सुरक्षित को पेमेंट्स ऐप-?

A) Paytm / पेटीएम
B) PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) / फोनपे पेमेंट गेटवे
C) Razorpay / रेज़रपे
D) Cashfree / कैशफ्री
E) Google Pay / गूगल पे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) has launched 'PhonePe PG Bolt' for Visa and Mastercard credit and debit card transactions.

• फोनपे पेमेंट गेटवे)PhonePe PG) ने Visa और Mastercard क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन-के देन लिए 'PhonePe PG Bolt' लॉन्च किया है।
• The solution uses device tokenization to provide a secure and efficient in-app checkout experience for PhonePe users and merchant partners.
• यह समाधान डिवाइस टोकनाइजेशन का उपयोग करता है ताकि PhonePe प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं और व्यापारी साझेदारों को सुरक्षित और प्रभावी इन अनुभव चेकआउट ऐप-सके। मिल
• By replacing sensitive card details with secure tokens, the system eliminates the need for CVV entry during subsequent transactions on the same device, simplifying the payment journey.
• संवेदनशील कार्ड विवरण को सुरक्षित टोकन से बदलकर, यह प्रणाली एक ही डिवाइस पर बाद के लेन में देन-CVV दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल बनती है।

About PhonePe:

- Established : 2015
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CEO : Sameer Nigam

Ques: Which bank won multiple awards including Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, and Best IT Risk Management at the 21st Annual Banking Technology Awards 2025?
21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption और Best IT Risk Management सहित कई पुरस्कार किस बैंक ने जीते?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda emerged as the winner of multiple awards at the 21st Annual Banking Technology Awards 2025.
• 21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई पुरस्कार जीते।
• The bank won awards for Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, Best IT Risk Management, and Best Tech Talent.
• बैंक ने Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, Best IT Risk Management और Best Tech Talent के पुरस्कार प्राप्त किए।
• Bank of Baroda also received a Special Mention in the category of Best Technology Bank.
• बैंक ऑफ बड़ौदा को Best Technology Bank श्रेणी में विशेष उल्लेख)Special Mention) भी मिला।
• The awards were received by Dr Debadatta Chand, Managing Director and CEO, and Shri Sanjay V Mudaliar, Executive Director of Bank of Baroda.
• ये पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं CEO डॉ कार्यकारी और चंद देबदत्त . गए। किए प्राप्त द्वारा मुदलियार .वी संजय श्री निदेशक

Ques: What is the Ways and Means Advances (WMA) limit fixed by the RBI for the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD)?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)GNCTD) सरकार के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा कितनी तय की है?

A) ₹750 crore
B) ₹820 crore
C) ₹890 crore
D) ₹950 crore
E) ₹1,000 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has fixed the Ways and Means Advances (WMA) limit for the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) at ₹890 crore.

• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)GNCTD) सरकार के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा ₹890 करोड़ निर्धारित की है।
• The revised WMA limit is effective from January 09, 2026, and is meant to manage temporary mismatches in receipts and payments.
• संशोधित WMA सीमा 9 जनवरी 2026 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को संभालना है।
• With this revision, the aggregate WMA limit for all State Governments and Union Territories has increased to ₹61,008 crore from the earlier ₹60,118 crore.
• इस संशोधन के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कुल WMA सीमा ₹60,118 करोड़ से बढ़कर ₹61,008 करोड़ हो गई है।
• The highest WMA limits among states are Uttar Pradesh (₹6,519 crore), Maharashtra (₹6,139 crore), and Tamil Nadu (₹4,582 crore).
• राज्यों में सबसे अधिक WMA सीमा उत्तर प्रदेश)₹6,519 करोड़(, महाराष्ट्र)₹6,139 करोड़) तमिलनाडु और (₹4,582 करोड़है। की (
• The interest rate on WMA is linked to the RBI repo rate, making it a policy-aligned liquidity management tool.
• WMA पर ब्याज दर RBI की रेपो दर से जुड़ी होती है, जिससे यह एक नीति तरलता संगत-है। बनता उपकरण प्रबंधन
• Overdrafts (OD) beyond the WMA limit attract an interest rate 2 percentage points above the repo rate.
• WMA सीमा से अधिक लिए गए ओवरड्राफ्ट)OD) पर रेपो दर से 2 प्रतिशत अंक अधिक ब्याज लगता है।
• The repayment period for WMA is capped at 90 days, ensuring short-term liquidity management discipline.
• WMA की चुकौती अवधि अधिकतम 90 दिन है, जिससे अल्पकालिक तरलता प्रबंधन में अनुशासन बना रहता है।

Ques: What was India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), in December 2025, and what was the average CPI inflation for the year 2025?
दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति) CPI के अनुसारथी कितनी (, और 2025 में औसत CPI मुद्रास्फीति क्या रही?

A) 1.33% in December; 2.2% average in 2025 / दिसंबर में 1.33%; 2025 में औसत 2.2%

B) 2.5% in December; 3.0% average in 2025 / दिसंबर में 2.5%; 2025 में औसत 3.0%
C) 1.0% in December; 1.8% average in 2025 / दिसंबर में 1.0%; 2025 में औसत 1.8%
D) 1.8% in December; 2.5% average in 2025 / दिसंबर में 1.8%; 2025 में औसत 2.5%
E) 2.2% in December; 1.33% average in 2025 / दिसंबर में 2.2%; 2025 में औसत 1.33%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), increased to 1.33% in December 2025, marking a three-month high.
• दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति)CPI के अनुसार (1.33% तक बढ़ गई, जो पिछले तीन महीनों में सबसे अधिक है।
• The average CPI-based inflation for the year 2025 was 2.2%, the lowest in 12 years.
• 2025 में औसत CPI आधारित मुद्रास्फीति 2.2% रही, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है।
• The data was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
• यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)MoSPI) द्वारा जारी किया गया।

Ques : According to the World Gold Council, India became the world's ___ largest holder of gold Exchange Traded Funds (ETFs) in 2025.
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 में भारत गोल्ड ETF का दुनिया का कौन-सा सबसे बड़ा धारक बना?

A) 4th
B) 5th
C) 6th
D) 7th
E) 8th

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Domestic gold Exchange Traded Fund (ETF) holdings in India increased by 65% to reach 95 tonnes in 2025.
• भारत में घरेलू गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की होल्डिंग्स 2025 में 65% बढ़कर 95 टन हो गईं।
• Due to this increase, India became the 6th largest holder of gold ETFs globally, improving from the 8th position in 2024.
• इस बढ़ोतरी के कारण भारत 2024 में 8वें स्थान से ऊपर उठकर दुनिया में गोल्ड ETF का छठा सबसे बड़ा धारक बन गया।
• According to the World Gold Council (WGC), India's gold ETF holdings were 57.5 tonnes in 2024.
• वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार 2024 में भारत की गोल्ड ETF होल्डिंग्स 57.5 टन थीं।
• Net inflows into Indian gold ETFs reached $4.4 billion in 2025, compared to $1.3 billion in 2024, showing a sharp rise in investor participation.
• भारतीय गोल्ड ETF में 2025 में $4.4 बिलियन का शुद्ध निवेश आया, जबकि 2024 में यह $1.3 बिलियन था, जो निवेशकों की भागीदारी में तेज़ बढ़ोतरी दर्शाता है।
• India emerged as the third-largest gold ETF market globally after the United States ($50 billion) and China ($15.5 billion).
• भारत अमेरिका ($50 बिलियन) और चीन ($15.5 बिलियन) के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड ETF बाजार बन गया।

Ques : Which bank became the first Regional Rural Bank (RRB) in India to introduce a fully solar-powered mobile ATM van?
भारत की पहली पूरी तरह सोलर-पावर्ड मोबाइल ATM वैन शुरू करने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन-सा है?

A) Tripura Gramin Bank / त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
B) Uttar Bihar Gramin Bank / उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
C) Assam Gramin Vikash Bank / असम ग्रामीण विकास बैंक
D) Kerala Gramin Bank / केरल ग्रामीण बैंक
E) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank / छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Tripura Gramin Bank (TGB) achieved a national milestone by becoming the first Regional Rural Bank (RRB) in India to introduce a fully solar-powered mobile ATM van.
• त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (TGB) भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना जिसने पूरी तरह सोलर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल ATM वैन शुरू की।
• The solar-powered ATM van has been named 'TGB on Wheels'.
• इस सोलर-पावर्ड ATM वैन का नाम 'TGB ऑन व्हील्स' रखा गया है।
• The initiative aims to provide banking services to remote and underserved areas using renewable energy.
• इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है।
• In July 2023, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman formally inaugurated the pioneering ATM van initiative during her visit to Tripura.
• जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा दौरे के दौरान इस ATM वैन पहल का औपचारिक उद्घाटन किया था।
• The project was launched with the support of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
• यह परियोजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के सहयोग से शुरू की गई।
• As of now, Tripura Gramin Bank operates three solar-powered ATM vans in Tripura.
• वर्तमान में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक त्रिपुरा में तीन सोलर-पावर्ड ATM वैन संचालित कर रहा है।
• Due to this innovative initiative, TGB was honoured with the SKOCH Silver Award, which is one of India's most respected awards for excellence in governance and innovation.
• इस नवोन्मेषी पहल के लिए TGB को SKOCH सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जो सुशासन और नवाचार के लिए भारत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है।

Ques : What was India's Wholesale Price Index (WPI) based inflation rate in December, according to recent data?
हालिया आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर कितनी रही?

A) –0.32%

B) 0.50%
C) 0.83%
D) 1.20%
E) 2.00%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• India's Wholesale Price Index (WPI) inflation for December stood at 0.83%.
• दिसंबर में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर 0.83% दर्ज की गई।
• In comparison, for the month of November, India's WPI-based inflation was recorded at –0.32%.
• तुलना के तौर पर, नवंबर महीने में भारत की WPI आधारित महंगाई दर –0.32% थी।
• This reflects a rise in wholesale inflation from negative territory in November to positive levels in December.
• यह नवंबर में नकारात्मक स्तर से दिसंबर में सकारात्मक स्तर तक थोक महंगाई में वृद्धि को दर्शाता है।

Ques: What has been a major factor driving the recent surge in municipal bond issuances in India?
भारत में हाल के वर्षों में नगर निगम बॉन्ड जारी होने में तेज़ी का प्रमुख कारण क्या रहा है?

A) Increase in foreign direct investment / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि
B) Fiscal incentives under AMRUT 2.0 / AMRUT 2.0 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन
C) Mandatory bond issuance by municipalities / नगर निकायों के लिए बॉन्ड जारी करना अनिवार्य होना
D) Reduction in interest rates by RBI / RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती
E) Privatization of urban local bodies / शहरी स्थानीय निकायों का निजीकरण

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• By December of the current financial year, nine municipal bond issuances

had already entered the market, indicating growing participation by urban local bodies.
• चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक नौ नगर निगम बॉन्ड बाजार में आ चुके थे, जो शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
• Data shows that the total outstanding value of municipal bonds stood at ₹3,783.9 crore as of September 30, 2025.
• आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक नगर निगम बॉन्ड का कुल बकाया मूल्य ₹3,783.9 करोड़ था।
• Nearly ₹1,000 crore was raised in the calendar year 2025 alone, marking the strongest single-year issuance so far.
• केवल वर्ष 2025 में ही लगभग ₹1,000 करोड़ जुटाए गए, जो अब तक का सबसे मजबूत एकलरहा। निर्गम वर्षीय-
• The recent momentum in municipal bond issuances is largely attributed to fiscal incentives provided under the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT 2.0).
• नगर निगम बॉन्ड में हालिया गति का मुख्य कारण अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन हैं।
• Under AMRUT 2.0, a first-time municipal bond issuer can receive incentives of up to ₹13 crore for every ₹100 crore raised.
• AMRUT 2.0 के अंतर्गत, पहली बार बॉन्ड जारी करने वाले नगर निकाय को प्रत्येक ₹100 करोड़ जुटाने पर ₹13 करोड़ तक का प्रोत्साहन मिल सकता है।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) for the Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnerships of the General Insurance Council?
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Praveen Kumar / प्रवीण कुमार
B) Anup Kumar Saha / अनुप कुमार साहा
C) Karthikeyan Manickam / कार्तिकेयन मणिकम
D) Ida Liu / इडा लियू
E) S Prakash / एस प्रकाश

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The General Insurance Council appointed S Prakash as the Chief Executive Officer for the Health Insurance Ecosystem and Strategic Partnerships.
• जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया।
• He replaced Praveen Kumar in this role.
• उन्होंने इस पद पर प्रवीण कुमार का स्थान लिया।
• The appointment aims to strengthen coordination and development in India's health insurance ecosystem.
• यह नियुक्ति भारत के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में समन्वय और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

Ques: Who has been appointed as the chairperson of the high-level committee formed to formulate guidelines for assured payouts under the National Pension System (NPS)?
प्रश्न) प्रणाली पेंशन राष्ट्रीय :NPS) के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Ajay Tyagi / अजय त्यागी
B) Supratim Bandyopadhyay / सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
C) M S Sahoo / एमसाहू .एस .
D) Ramesh Abhishek / रमेश अभिषेक
E) Urjit Patel / उर्जित पटेल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has constituted a high-level committee to formulate guidelines and regulations to enable a framework for assured payouts under the National Pension System (NPS).
• पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण)PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)NPS) के

तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु दिशानिर्देश और विनियम बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
• The committee is a 15-member body aimed at strengthening confidence and predictability in NPS payout mechanisms.
• यह समिति 15 सदस्यों वाली है, जिसका उद्देश्य NPS भुगतान प्रणाली में विश्वास और सुनिश्चितता को मजबूत करना है।
• The committee is chaired by M S Sahoo, former Chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).
• इस समिति की अध्यक्षता दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया)IBBI) के पूर्व अध्यक्ष एमहैं। रहे कर साहू .एस .

About PFRDA :

- Established : 2003
- HQ : New Delhi
- Chairman : Sivasubramanian Ramann

Ques: What restriction has the Reserve Bank of India imposed on resident Indians under the Foreign Exchange Management Regulations, 2026?
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस, 2026 के तहत RBI ने भारतीय निवासियों पर कौन-सी पाबंदी लगाई है?

A) Ban on foreign investments / विदेशी निवेश पर प्रतिबंध
B) Prohibition on issuing credit guarantees to NRIs / NRI को क्रेडिट गारंटी जारी करने पर रोक
C) Restriction on remittances / रेमिटेंस पर रोक
D) Ban on foreign borrowing / विदेशी उधार पर रोक
E) Restriction on export payments / निर्यात भुगतान पर रोक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India issued the Foreign Exchange Management Regulations, 2026.

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस, 2026 जारी किए।
• Under these regulations, resident Indians are prohibited from issuing credit guarantees in favour of non-resident Indians (NRIs).
• इन नियमों के तहत भारत में रहने वाले भारतीयों को गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के पक्ष में क्रेडिट गारंटी जारी करने से रोका गया है।
• RBI clarified that no person resident in India shall be a party to a guarantee if any other party to the guarantee is resident outside India.
• RBI ने स्पष्ट किया कि यदि गारंटी का कोई भी पक्ष भारत के बाहर रहता है, तो भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति उस गारंटी का पक्ष नहीं बन सकता।
• Resident Indians may act as surety or principal debtor only if the underlying transaction is permitted under foreign exchange law.
• निवासी भारतीय तभी ज़मानती या प्रधान देनदार बन सकते हैं जब मूल लेन-देन विदेशी मुद्रा कानून के तहत अनुमत हो।
• Both parties must also be eligible to lend or borrow under FEMA (Borrowing and Lending) Regulations, 2018.
• दोनों पक्षों को FEMA (उधार लेना और देना) रेगुलेशंस, 2018 के तहत पात्र होना चाहिए।
• These conditions do not apply to fully collateralised dealer banks, agents of foreign shipping or airline companies, and resident-to-resident guarantees.
• ये शर्तें पूर्ण रूप से कोलैटरलाइज्ड डीलर बैंक, विदेशी शिपिंग या एयरलाइन कंपनी के एजेंट और निवासी-से-निवासी गारंटी पर लागू नहीं होतीं।

Ques: Which Indian financial institution became the first Indian issuer in 2026 to raise overseas debt through a dual-tranche, long-duration US dollar-denominated bond issue worth $1 billion?
2026 में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ड्यूलट्रांच-, दीर्घ बॉन्ड मूल्यांकित-डॉलर अमेरिकी अवधि-बना कौन संस्थान भारतीय पहला वाला जुटाने ऋण से विदेशों कर जारी?

A) State Bank of India (SBI) / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
B) Export-Import Bank of India (EXIM Bank) / भारतीय निर्यातबैंक आयात-
C) Power Finance Corporation (PFC) / पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
D) National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक
E) India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) / इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Export-Import Bank of India (EXIM Bank) accepted bids worth $1 billion for its dual-tranche, long-duration US dollar-denominated bonds, marking the first overseas debt issuance by an Indian issuer in 2026.
• भारतीय निर्यात) बैंक आयात-EXIM Bank) ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ड्यूलट्रांच-, दीर्घ-कीं स्वीकार बोलियाँ लिए के बॉन्ड मूल्यांकित-डॉलर अमेरिकी अवधि, जिससे यह 2026 में विदेशी ऋण जारी करने वाला पहला भारतीय जारीकर्ता बना।

• The bond issue consists of two tranches:

– 10-year bond: $500 million, coupon rate 5.00%, spread 85 basis points over the 10-year US Treasury yield.
– 10-वर्षीय बॉन्ड :500 मिलियन डॉलर, कूपन दर 5.00%, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 85 बेसिस पॉइंट अधिक।
– 30-year bond: $500 million, coupon rate 5.75%, spread 95 basis points over the 30-year US Treasury yield.
– 30-वर्षीय बॉन्ड :500 मिलियन डॉलर, कूपन दर 5.75%, 30-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड से 95 बेसिस पॉइंट अधिक।

• The bonds are rated BBB– by Fitch Ratings, in line with EXIM Bank's issuer rating.
• इन बॉन्ड्स को फिच रेटिंग्स द्वारा BBB– रेटिंग दी गई है, जो EXIM Bank की जारीकर्ता रेटिंग के अनुरूप है।
• The bonds will be listed on exchanges in Singapore, London and India.
• ये बॉन्ड सिंगापुर, लंदन और भारत के एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
• Proceeds from the issue will be used for general funding requirements, financing overseas investments, and funding the import of capital goods.
• इस बॉन्ड इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग सामान्य फंडिंग आवश्यकताओं, विदेशी निवेशों के लिए ऋण, तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण में किया जाएगा।

Ques: What does the World Bank Group's 'Global Economic Prospects (January 2026)' report project for India's economic growth?
विश्व बैंक समूह की 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जनवरी)2026)' रिपोर्ट भारत की

आर्थिक वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाती है?

A) India's GDP growth is projected to decline to below 6% in FY26 / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 6% से नीचे रहने का अनुमान
B) India's GDP growth is projected at 7.2% in FY26, revised upward from earlier estimates / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 7.2% रहने का अनुमान, जो पहले के अनुमान से अधिक है
C) India's GDP growth is projected to remain unchanged at 6.3% in FY26 / भारत की GDP वृद्धि FY26 में 6.3% पर ही बनी रहने का अनुमान
D) India's GDP growth is projected to accelerate to above 8% in FY27 / भारत की GDP वृद्धि FY27 में 8% से अधिक होने का अनुमान
E) India's GDP growth is projected to stagnate with no moderation in FY27 / भारत की GDP वृद्धि FY27 में बिना किसी कमी के स्थिर रहने का अनुमान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The World Bank Group released its flagship 'Global Economic Prospects (GEP): January 2026' report.
• विश्व बैंक समूह ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट 'ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स)GEP): जनवरी 2026' जारी की।
• The report has revised India's GDP growth projection for FY 2025–26 upward to 7.2%, compared to the earlier estimate of 6.3% made in June 2025.
• रिपोर्ट में भारत की FY 2025–26 की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, जो जून 2025 में 6.3% आंका गया था।
• According to the report, India's economic growth is expected to moderate to 6.5% in FY27, lower than the previous estimate of 7.2%.
• रिपोर्ट के अनुसार, FY27 में भारत की आर्थिक वृद्धि घटकर 6.5% रहने की संभावना है, जो पहले 7.2% अनुमानित थी।
• These projections reflect both strong near-term economic momentum and expectations of gradual moderation in the medium term.
• ये अनुमान निकट अवधि में मजबूत आर्थिक गति और मध्यम अवधि में क्रमिक धीमेपन की संभावना को दर्शाते हैं।

Ques: How many cryptocurrency exchanges were registered with India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) during FY 2024–25, and under which law were crypto exchanges brought for AML–CTF compliance?
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) के साथ कितने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पंजीकृत हुए और उन्हें किस कानून के तहत AML–CTF अनुपालन में लाया गया?

A) 49 exchanges – PMLA / 49 एक्सचेंज – PMLA
B) 41 exchanges – IT Act / 41 एक्सचेंज – आईटी अधिनियम
C) 32 exchanges – FEMA / 32 एक्सचेंज – FEMA
D) 55 exchanges – RBI Act / 55 एक्सचेंज – RBI अधिनियम
E) 60 exchanges – Companies Act / 60 एक्सचेंज – कंपनी अधिनियम

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• During FY 2024–25, a total of 49 cryptocurrency exchanges were registered with India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND), most of them being domestic platforms.
• वित्त वर्ष 2024–25 में कुल 49 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) के साथ पंजीकृत हुए, जिनमें से अधिकांश घरेलू थे।
• As of March 2025, 45 onshore exchanges and 4 offshore exchanges were registered with FIU-IND, allowing them to operate under India's regulatory and compliance framework.
• मार्च 2025 तक 45 ऑनशोर और 4 ऑफशोर एक्सचेंज FIU-IND के साथ पंजीकृत थे, जिससे वे भारत के अनुपालन ढांचे के तहत काम कर सकते हैं।
• During FY25, FIU-IND imposed penalties amounting to ₹28 crore on certain non-compliant crypto exchanges.
• वित्त वर्ष 2025 के दौरान FIU-IND ने कुछ गैर-अनुपालक क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ₹28 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• In 2023, all crypto exchanges in India were brought under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), making them reporting entities for Anti-Money Laundering (AML) and Counter Terror Financing (CTF).
• वर्ष 2023 में भारत के सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लाया गया, जिससे वे AML और CTF के लिए रिपोर्टिंग इकाइयाँ बन गईं।
• Cryptocurrencies are legally classified as Virtual Digital Assets (VDAs), and

crypto trading platforms are designated as VDA Service Providers (VDA SPs).
• क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी रूप से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को VDA सर्विस प्रोवाइडर (VDA SPs) माना गया है।

Ques: Which bank has partnered with NPCI BHIM Services Limited (NBSL) to use its bank plugins for offering UPI services on its banking app?
किस बैंक ने अपने बैंकिंग ऐप पर UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI BHIM Services Limited (NBSL) के बैंक प्लगहै अपनाया को इन्स-?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) Canara Bank / केनरा बैंक
D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Canara Bank will use NPCI BHIM Services' (NBSL) bank plugins to offer Unified Payments Interface (UPI) services on its banking payments app, Canara ai1Pe.
• केनरा बैंक अपने बैंकिंग भुगतान ऐप Canara ai1Pe पर UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI BHIM Services (NBSL) के बैंक प्लगकरेगा। उपयोग का इन्स-
• This partnership enables Canara Bank to integrate the latest UPI payment launches and feature upgrades within its app, similar to functionalities available on the BHIM app.
• इस साझेदारी के तहत केनरा बैंक अपने ऐप में BHIM ऐप जैसी नवीनतम UPI सुविधाएँ और फीचर अपग्रेड्स को एकीकृत कर सकेगा।
• Canara Bank is the first bank to adopt this technology-sharing approach from NBSL.
• केनरा बैंक NBSL द्वारा अपनाए गए इस टेक्नोलॉजी पहला वाला अपनाने को मॉडल शेयरिंग- है। बैंक
• In 2025, BHIM had presented a proof of concept for BHIM Vishwas, allowing banks to leverage BHIM's technology stack.
• वर्ष 2025 में BHIM ने 'BHIM विश्वास' के तहत एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था,

जिससे बैंक BHIM की तकनीकी संरचना का उपयोग कर सकें।

Ques: Which organisation has been recognised by the Reserve Bank of India (RBI) as a Self-Regulatory Organisation (SRO) for all Authorised Dealers under the Omnibus SRO Framework in January 2026?
जनवरी 2026 में RBI के ओम्निबस SRO फ्रेमवर्क के तहत सभी अधिकृत डीलरों के लिए किस संगठन को स्व) संगठन नियामक-SRO) के रूप में मान्यता दी गई है?

A) FIMMDA – Fixed Income Money Market & Derivatives Association / फिम्मडा
B) FIDC – Finance Industry Development Council / फिडक
C) FEDAI – Foreign Exchange Dealers' Association of India / फेडाई
D) FACE – Fintech Association for Consumer Empowerment / फेस
E) AMFI – Association of Mutual Funds in India / एम्फी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) submitted an application to the RBI under the Omnibus Framework for recognition of Self-Regulatory Organisations (SROs) for Regulated Entities.
• फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)FEDAI) ने विनियमित संस्थाओं के लिए SRO की मान्यता हेतु RBI के ओम्निबस फ्रेमवर्क के तहत आवेदन किया था।
• After examining the application, RBI decided to recognise FEDAI as an SRO for all Authorised Dealers, considering that it has long functioned like an SRO through its rules governing member conduct.
• आवेदन की समीक्षा के बाद RBI ने FEDAI को सभी अधिकृत डीलरों के लिए SRO के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया, क्योंकि यह पहले से ही अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के माध्यम से SRO की तरह कार्य कर रहा था।
• FEDAI has been granted one year to align its governance and operational framework with the Omnibus SRO Framework.
• FEDAI को अपने प्रशासनिक और परिचालन ढांचे को ओम्निबस SRO फ्रेमवर्क के अनुरूप करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।
• It must also extend its membership to all categories of Authorised Dealers during this period.

• इस अवधि में FEDAI को सभी श्रेणियों के अधिकृत डीलरों तक अपनी सदस्यता का विस्तार करना होगा।
• As of January 2026, RBI has recognised four SROs under the new Omnibus Framework:
– FEDAI (Forex Authorised Dealers) – January 14, 2026
– FIDC (NBFCs) – October 3, 2025
– FIMMDA (Bonds & Derivatives Markets) – May 7, 2025
– FACE (Fintech) – August 2024
• जनवरी 2026 तक RBI ने नए ओम्निबस फ्रेमवर्क के तहत चार SRO को मान्यता दी है : FEDAI, FIDC, FIMMDA और FACE।
• Apart from this, RBI-recognised SROs also exist in the microfinance sector (MFIN and Sa-Dhan), while SEBI recognises bodies like AMFI (Association of Mutual Funds in India), BSE, NSE, RAIN (Registrars Association of India), IVCA (Indian Venture and Alternate Capital Association) and others as SROs in capital markets.
• इसके अतिरिक्त, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में MFIN और Sa-Dhan RBI-मान्यता प्राप्त SRO हैं, जबकि पूंजी बाजार में AMFI, BSE, NSE आदि SEBI द्वारा SRO के रूप में माने जाते हैं।

Ques: What is the focus of the fifth edition of NITI Aayog's Trade Watch Quarterly **launched in New Delhi?**
नई दिल्ली में लॉन्च किए गए नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली **के पाँचवें संस्करण का मुख्य फोकस क्या है?**

A) India's agricultural subsidies and WTO disputes / भारत की कृषि सब्सिडी और WTO विवाद
B) Structural shifts in India's trade profile and export competitiveness / भारत की व्यापार संरचना में बदलाव और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता
C) Impact of global inflation on India's domestic prices / वैश्विक मुद्रास्फीति का भारत की घरेलू कीमतों पर प्रभाव
D) Bilateral trade agreements signed in FY 2025–26 / FY 2025–26 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार समझौते
E) Performance of public sector enterprises in exports / निर्यात में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• NITI Aayog launched the fifth edition of **Trade Watch Quarterly**, covering the first quarter (Q1) of FY 2025–26.
• नीति आयोग ने **ट्रेड वॉच क्वार्टरली** का पाँचवाँ संस्करण लॉन्च किया, जो FY 2025–26 की पहली तिमाही)Q1) को कवर करता है।
• The report highlights emerging structural shifts in India's trade profile**,** including a rising share of technology-intensive exports and continued strength of services-led growth.
• रिपोर्ट भारत की व्यापार संरचना में उभरते बदलावों को दर्शाती है, जिसमें प्रौद्योगिकी-है। शामिल वृद्धि वाली नेतृत्व के सेवाओं और हिस्सेदारी बढ़ती की निर्यात प्रधान
• It also notes changes in import composition, reflecting deeper integration into Global Value Chains (GVCs)**.**
• इसमें आयात संरचना में बदलाव का भी उल्लेख है, जो वैश्विक मूल्य शृंखलाओं)GVCs) में भारत के गहरे एकीकरण को दर्शाता है।
• A special focus of the report is on the structure and competitiveness of India's exports, particularly automotive exports**,** their evolving composition, and India's position in global markets.
• रिपोर्ट का विशेष फोकस भारत के निर्यात की संरचना और प्रतिस्पर्धात्मकता पर है, खासकर ऑटोमोटिव निर्यात**,** उनकी बदलती संरचना और वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति पर।

Ques: Which bank has received RBI and Karnataka Government approval to collect State government revenue through the Khajane-2 Integrated Financial Management System (IFMS)?
किस बैंक को खजाने-2 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व संग्रह हेतु RBI और कर्नाटक सरकार की मंजूरी मिली है?

A) Canara Bank / केनरा बैंक
B) Karnataka Bank / कर्नाटक बैंक
C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Karnataka Bank has secured the necessary authorization from the Reserve Bank of India (RBI) and approval from the Department of Treasuries, Government of Karnataka.
• कर्नाटक बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और कर्नाटक सरकार के ट्रेजरी विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हुई है।
• This approval enables the bank to collect State government revenue receipts through the Khajane-2 Integrated Financial Management System (IFMS).
• इस मंजूरी के तहत बैंक खजाने-2 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से राज्य सरकार की राजस्व रसीदें जमा कर सकेगा।
• With this enablement, Karnataka Bank can collect various State government taxes and fees from citizens of Karnataka using its Internet banking services.
• इस सुविधा के साथ कर्नाटक बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से कर्नाटक के नागरिकों से विभिन्न राज्य सरकारी कर और शुल्क एकत्र कर सकेगा।
• Karnataka Bank was established in 1924 and is headquartered in Mangaluru, Karnataka.
• कर्नाटक बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
• The CEO & Managing Director of Karnataka Bank is Raghavendra Srinivas Bhat, and its tagline is “Your Family Bank Across India.”
• कर्नाटक बैंक के CEO एवं प्रबंध निदेशक राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं और इसका टैगलाइन “Your Family Bank Across India” है।

Ques: Which international financial institutions jointly provided a USD 350 million loan to Piramal Finance Limited?
पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने संयुक्त रूप से प्रदान किया?

A) World Bank and IMF / विश्व बैंक और IMF
B) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and ADB / AIIB और ADB
C) International Finance Corporation (IFC) and Asian Development Bank (ADB) / IFC और ADB
D) New Development Bank (NDB) and World Bank / NDB और विश्व बैंक

E) European Investment Bank (EIB) and ADB / EIB और ADB

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Piramal Finance Limited has received a total loan of USD 350 million.
• पिरामल फाइनेंस लिमिटेड को कुल 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है।
• The loan has been jointly provided by the International Finance Corporation (IFC) and the Asian Development Bank (ADB).
• यह ऋण अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम)IFC) और एशियाई विकास बैंक)ADB) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
• Of the total amount, IFC has contributed USD 200 million, while ADB has provided USD 150 million.
• कुल राशि में से IFC ने 200 मिलियन डॉलर और ADB ने 150 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।
• The loan has a tenure of five years.
• इस ऋण की अवधि पाँच वर्ष है।
• Piramal Finance Limited is headquartered in Mumbai.
• पिरामल फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
• The Managing Director and CEO of the company is Jairam Sridharan.
• कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी)MD & CEO) जयराम श्रीधरन हैं।

Ques: What major change did SEBI propose to ease liquidity strain for Foreign Portfolio Investors (FPIs)?
SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए तरलता दबाव कम करने हेतु कौन-सा प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किया?

A) Introduction of weekly settlement cycle / साप्ताहिक सेटलमेंट चक्र की शुरुआत
B) Same-day fund netting of buy and sell obligations / खरीद-बिक्री दायित्वों की उसी दिन फंड नेटिंग
C) Reduction in securities transaction tax / सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में कटौती
D) Mandatory escrow funding for FPIs / FPIs के लिए अनिवार्य एस्क्रो फंडिंग
E) Extension of trading hours for FPIs / FPIs के लिए ट्रेडिंग समय बढ़ाना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI proposed allowing Foreign Portfolio Investors (FPIs) to offset their purchase and sale obligations within the same trading day.
• SEBI ने FPIs को एक ही ट्रेडिंग दिन में अपनी खरीद और बिक्री की देनदारियों को समायोजित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया।
• This proposal aims to replace the existing system where settlements are required on a gross basis.
• यह प्रस्ताव मौजूदा ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट प्रणाली को बदलने के लिए है।
• At present, FPIs must separately fund every buy order and deliver securities for every sell order, even if both occur on the same day.
• वर्तमान में, FPIs को हर खरीद ऑर्डर के लिए अलग से फंडिंग करनी होती है और हर बिक्री ऑर्डर के लिए सिक्योरिटीज़ डिलीवर करनी होती हैं, भले ही दोनों लेनदेन एक ही दिन हों।
• Even when the value of buy and sell transactions is equal, the investor must arrange full funds for the purchase leg.
• भले ही खरीद और बिक्री की राशि समान हो, निवेशक को खरीद के लिए पूरी फंडिंग का इंतज़ाम करना पड़ता है।
• For example, an investor buying and selling shares worth ₹100 crore each still needs to arrange ₹100 crore in funds.
• उदाहरण के तौर पर, ₹100 करोड़ के शेयर खरीदने और बेचने वाले निवेशक को फिर भी ₹100 करोड़ की फंडिंग करनी होती है।
• The proposed same-day fund netting will reduce liquidity pressure and improve capital efficiency for FPIs.
• प्रस्तावित उसी दिन फंड नेटिंग से FPIs पर तरलता दबाव कम होगा और पूंजी दक्षता बढ़ेगी।

Ques: Why is JPMorgan Chase replacing Goldman Sachs as the issuer of the Apple Card?
जेपीमॉर्गन चेज़, एप्पल कार्ड के जारीकर्ता के रूप में गोल्डमैन सैक्स की जगह क्यों ले रहा है?

A) To exit the premium digital credit card segment / प्रीमियम डिजिटल क्रेडिट कार्ड से बाहर निकलने के लिए
B) To transfer Apple Card operations to a fintech company / एप्पल कार्ड संचालन

को किसी फिनटेक कंपनी को सौंपने के लिए
C) To strengthen JPMorgan's consumer banking business while Goldman scales back retail finance / जेपीमॉर्गन के उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार को मजबूत करने और गोल्डमैन के रिटेल फाइनेंस से पीछे हटने के लिए
D) Due to Apple ending its credit card partnership / एप्पल द्वारा क्रेडिट कार्ड साझेदारी समाप्त करने के कारण
E) Because of regulatory penalties on Goldman Sachs / गोल्डमैन सैक्स पर नियामकीय जुर्माने के कारण

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• JPMorgan Chase will replace Goldman Sachs as the issuer of the Apple Card.
• जेपीमॉर्गन चेज़, एप्पल कार्ड के जारीकर्ता के रूप में गोल्डमैन सैक्स की जगह लेगा।
• The move will transfer over $20 billion in Apple Card credit balances to JPMorgan's platform.
• इस बदलाव से एप्पल कार्ड के 20 अरब डॉलर से अधिक के क्रेडिट बैलेंस जेपीमॉर्गन के प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होंगे।
• For JPMorgan Chase, the deal strengthens its credit card and consumer banking business.
• जेपीमॉर्गन चेज़ के लिए यह सौदा उसके क्रेडिट कार्ड और उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार को मजबूत करता है।
• It also expands JPMorgan's presence in the premium digital credit card segment.
• इससे प्रीमियम डिजिटल क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में जेपीमॉर्गन की मौजूदगी बढ़ेगी।
• For Goldman Sachs, the move aligns with its strategy to scale back consumer finance operations.
• गोल्डमैन सैक्स के लिए यह कदम उसके उपभोक्ता वित्त को कारोबार (फाइनेंस कंज़्यूमर) है। अनुरूप के रणनीति की करने सीमित
• It reflects Goldman Sachs' continued retreat from retail-focused ventures such as co-branded credit cards.
• यह को पीछे लगातार के सैक्स गोल्डमैन से उपक्रमों केंद्रित-रिटेल जैसे कार्ड क्रेडिट ब्रांडेड- है। दर्शाता को हटने
• The transaction is subject to regulatory approvals and is expected to be completed in about two years.
• यह लेनदेन नियामकीय मंज़ूरियों पर निर्भर है और लगभग दो वर्षों में पूरा होने की उम्मीद

है।

Ques: What is the key provision introduced under the RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2026 to strengthen customer grievance redressal?
RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत ग्राहक शिकायत निवारण को मज़बूत करने के लिए कौन-सा प्रमुख प्रावधान किया गया है?

A) Manual review of complaints by RBI offices / RBI कार्यालयों द्वारा शिकायतों की मैनुअल समीक्षा
B) Auto-transfer of unresolved complaints to Internal Ombudsman / अनसुलझी शिकायतों का इंटरनल ओम्बड्समैन को स्वतः ट्रांसफर
C) Closure of complaints by the same bank branch / उसी बैंक शाखा द्वारा शिकायत निपटान
D) Extension of complaint resolution time to 60 days / शिकायत निवारण समय 60 दिन करना
E) Limiting the scheme only to public sector banks / योजना को केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• To strengthen customer protection in the financial system, the Reserve Bank of India issued new directions on grievance redressal.
• वित्तीय प्रणाली में ग्राहक संरक्षण को मज़बूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिकायत निवारण पर नए निर्देश जारी किए।
• RBI issued Master Circular–1 under the Integrated Ombudsman Scheme, 2026. The revised scheme will come into force from 1 July 2026.
• RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत मास्टर सर्कुलर-1 जारी किया। संशोधित योजना 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
• Under the revised norms, banks and eligible NBFCs must automatically transfer unresolved complaints to their Internal Ombudsman.
• नए नियमों के तहत बैंकों और पात्र NBFCs को अनसुलझी शिकायतें अपने इंटरनल ओम्बड्समैन को स्वतः ट्रांसफर करनी होंगी।
• This provision ensures that the final decision is communicated to customers

within 30 days of receipt of the complaint.
• यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक को अंतिम निर्णय बताया जाए।
• RBI has mandated that banks and eligible NBFCs establish a fully automated Complaint Management System (CMS).
• RBI ने बैंकों और पात्र NBFCs के लिए पूरी तरह ऑटोमेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) अनिवार्य किया है।
• The CMS must allow seamless access to the Internal Ombudsman (IO) and Deputy Internal Ombudsman (DIO).
• CMS से इंटरनल ओम्बड्समैन (IO) और डिप्टी इंटरनल ओम्बड्समैन (DIO) तक आसानी से पहुँच होनी चाहिए।
• For complaints where RBI, NPCI, or card network rules prescribe timelines, the IO must be given at least 10 days for review.
• जिन शिकायतों में RBI, NPCI या कार्ड नेटवर्क नियमों में समयसीमा तय है, उनमें IO को समीक्षा के लिए कम से कम 10 दिन मिलेंगे।
• For all other complaints, a 20-day timeline from the date of receipt applies for IO review.
• अन्य सभी शिकायतों के लिए, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से IO समीक्षा हेतु 20 दिन की समयसीमा होगी।
• Banks must classify complaints into three categories within the CMS: fully resolved, partially resolved, and wholly rejected.
• बैंकों को CMS में शिकायतों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा: पूरी तरह सुलझी, आंशिक रूप से सुलझी, और पूरी तरह अस्वीकृत।
• Only partially resolved or wholly rejected complaints will be transferred to the Internal Ombudsman.
• केवल आंशिक रूप से सुलझी या पूरी तरह अस्वीकृत शिकायतें ही इंटरनल ओम्बड्समैन को भेजी जाएँगी।
• RBI clarified that the same branch or unit cannot close a complaint, whether resolved or rejected, to avoid conflict of interest and ensure fairness.
• RBI ने स्पष्ट किया कि हितों के टकराव से बचने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई भी शाखा या यूनिट स्वयं शिकायत बंद नहीं कर सकती।
• These norms apply to banks having 10 or more outlets in India as on 31 March 2025.
• ये नियम 31 मार्च 2025 तक भारत में 10 या उससे अधिक आउटलेट वाले बैंकों पर लागू होंगे।
• For NBFCs, the rules apply to deposit-taking NBFCs with 10 or more branches and non-deposit-taking NBFCs having assets of ₹5,000 crore or more with a public customer interface.

• NBFCs के मामले में, ये नियम 10 या उससे अधिक शाखाओं वाली डिपॉज़िट-टेकिंग NBFCs और ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक एसेट वाली नॉन-डिपॉज़िट-टेकिंग NBFCs पर लागू होंगे, जिनका सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है।

Ques: What is the key objective behind Amazon Pay launching fixed deposit (FD) services on its fintech app?
अमेज़न पे ने अपने फिनटेक ऐप पर फिक्स्ड डिपॉज़िट)FD) सेवाएँ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) To offer cryptocurrency-based investments / क्रिप्टोकरेंसी आधारित निवेश प्रदान करना
B) To expand into fixed-income investment products / फिक्स्ड निवेश इनकम-कर विस्तार में उत्पादोंना
C) To replace traditional bank fixed deposits / पारंपरिक बैंक एफडी को समाप्त करना
D) To provide unsecured personal loans / असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना
E) To act as a full-fledged commercial bank / पूर्ण वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Amazon Pay has launched fixed deposit (FD) services on its fintech app as part of its expansion into fixed-income assets.
• अमेज़न पे ने फिक्स्ड पर ऐप फिनटेक अपने तहत के विस्तार में परिसंपत्तियों इनकम-ड फिक्स्डिपॉज़िट)FD) सेवाएँ शुरू की हैं।
• The FD offerings provide interest rates of up to 8%.
• इन एफडी पर 8% तक की ब्याज दर उपलब्ध कराई जा रही है।
• Amazon Pay has partnered with two NBFCs—Shriram Finance and Bajaj Finance—and five banks.
• अमेज़न पे ने दो एनबीएफसी—श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस—तथा पाँच बैंकों के साथ साझेदारी की है।
• The partner banks include Shivalik Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank, South Indian Bank, Slice, and Utkarsh Small Finance Bank.
• साझेदार बैंकों में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ

इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं।
• Users can start investing in FDs with a minimum amount of ₹1,000 without opening separate bank accounts with each institution.
• उपयोगकर्ता मात्र ₹1,000 से एफडी में निवेश शुरू कर सकते हैं और अलग में बैंकों अलग-होती। नहीं आवश्यकता की खोलने खाते
• Deposits made through the platform are insured up to ₹5 lakh per depositor per bank under DICGC rules.
• प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए गए जमा DICGC नियमों के तहत प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक बीमित हैं।

Ques: What was the key outcome of Bajaj Finserv's acquisition of Allianz SE's stake in its insurance businesses?
बजाज फिनसर्व द्वारा अपनी बीमा कंपनियों में एलियांज़ SE की हिस्सेदारी अधिग्रहण का प्रमुख परिणाम क्या रहा?

A) Complete exit of Bajaj Group from insurance business / बजाज समूह का बीमा कारोबार से पूर्ण रूप से बाहर निकलना
B) Reduction of Bajaj Finserv's ownership below majority level / बजाज फिनसर्व की हिस्सेदारी बहुमत से नीचे आना
C) Increase in Bajaj Group's ownership to 97% with full management control / बजाज समूह की हिस्सेदारी बढ़कर 97% होना और पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण मिलना
D) Merger of Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance / बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस का विलय
E) Listing of Allianz SE as a majority partner in India / एलियांज़ SE का भारत में बहुमत भागीदार बनना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bajaj Finserv, along with Bajaj Holdings & Investment Limited and Jamnalal Sons Private Limited, has completed the acquisition of Allianz SE's 23% stake in its insurance subsidiaries.
• बजाज फिनसर्व ने बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड तथा जमनालाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी बीमा सहायक कंपनियों में एलियांज़ SE की 23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया है।

• The acquisition involved Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance.
• यह अधिग्रहण बजाज जनरल इंश्योरेंस और बजाज लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है।
• The transaction value was ₹12,190 crore for Bajaj General Insurance and ₹9,200 crore for Bajaj Life Insurance.
• इस लेनदेन में बजाज जनरल इंश्योरेंस के लिए ₹12,190 करोड़ और बजाज लाइफ इंश्योरेंस के लिए ₹9,200 करोड़ का भुगतान किया गया।
• The total consideration for the acquisition amounted to ₹21,390 crore.
• अधिग्रहण के लिए कुल भुगतान राशि ₹21,390 करोड़ रही।
• Post-acquisition, Bajaj Group's ownership increased from 74% to 97%.
• अधिग्रहण के बाद बजाज समूह की हिस्सेदारी 74% से बढ़कर 97% हो गई।
• Bajaj Finserv now holds a 75.01% stake, giving it complete management control over the insurance businesses.
• बजाज फिनसर्व के पास अब 75.01% हिस्सेदारी है, जिससे उसे बीमा व्यवसायों पर पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण प्राप्त हो गया है।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of ICICI Bank Limited for a two-year tenure starting October 04, 2026?
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक)MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) के रूप में 04 अक्टूबर 2026 से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है?

A) Uday Kotak / उदय कोटक
B) Shikha Sharma / शिखा शर्मा
C) Sandeep Bakshi / संदीप बख्शी
D) Chanda Kochhar / चंदा कोचर
E) N. S. Kannan / एनकन्नन .एस .

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Sandeep Bakshi has been appointed as the MD and CEO of ICICI Bank Limited for a two-year term.
• संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

• His tenure will be effective from October 04, 2026 to October 03, 2028.
• उनका कार्यकाल 04 अक्टूबर 2026 से 03 अक्टूबर 2028 तक होगा।
• Bakshi was first appointed as MD and CEO of ICICI Bank in October 2018.
• संदीप बख्शी को पहली बार अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया था।
• His term was subsequently extended until October 2026 before the current reappointment.
• इसके बाद उनके कार्यकाल को अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था।

About ICICI Bank :

- Established : 1994
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- CEO & MD : Sandeep Bakhshi
- Tagline : Hum Hai Na, Khayal Apka

Ques: Which bank won the 'Best Fintech & DPI Adoption' award at the 21st Indian Banks' Association (IBA) Banking Technology Awards 2026, and where was the event held?
21वें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स 2026 में 'बेस्ट फिनटेक एवं DPI अपनाने' श्रेणी का पुरस्कार किस बैंक ने जीता और यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ?

A) State Bank of India – New Delhi / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – नई दिल्ली
B) HDFC Bank – Bengaluru / एचडीएफसी बैंक – बेंगलुरु
C) Canara Bank – Chennai / केनरा बैंक – चेन्नई
D) ICICI Bank – Hyderabad / आईसीआईसीआई बैंक – हैदराबाद
E) Karnataka Bank – Mumbai / कर्नाटक बैंक – मुंबई

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• Karnataka Bank won the 'Best Fintech & DPI Adoption' award.
• कर्नाटक बैंक ने 'बेस्ट फिनटेक एवं DPI एडॉप्शन' श्रेणी का पुरस्कार जीता।
• The award was conferred at the 21st Indian Banks' Association (IBA) Banking Technology Awards 2026.

• यह पुरस्कार 21वें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवॉर्ड्स 2026 में प्रदान किया गया।
• The award ceremony was held in Mumbai.
• यह पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित हुआ।
• The recognition highlights Karnataka Bank's effective adoption of FinTech innovations and Digital Public Infrastructure (DPI) in banking services.
• यह सम्मान बैंकिंग सेवाओं में फिनटेक नवाचारों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को प्रभावी रूप से अपनाने में कर्नाटक बैंक की उपलब्धियों को दर्शाता है।

Ques: Bank of Baroda has signed an MoU with which institution to boost infrastructure financing?
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस संस्था के साथ MoU किया है?

A) NABARD / नाबार्ड
B) SIDBI / सिडबी
C) IIFCL / आईआईएफसीएल
D) NHB / एनएचबी
E) EXIM Bank / एक्सिम बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda signed a Memorandum of Understanding with India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL) to collaborate on infrastructure financing.
• बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)IIFCL) के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए।
• The partnership will facilitate joint lending and loan syndication for a wide range of infrastructure projects across India.
• यह साझेदारी देशभर में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए संयुक्त ऋण और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देगी।
• The objective is to accelerate infrastructure development and support long-term economic growth.

• इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देना और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना है।
• IIFCL will provide sectoral expertise, while Bank of Baroda will contribute its banking and credit capabilities.
• IIFCL अपने क्षेत्रीय अनुभव का उपयोग करेगा, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बैंकिंग और क्रेडिट क्षमताएँ प्रदान करेगा।

About IIFCL :

• Established: 2006
• Headquarters: New Delhi
• Managing Director: Shri Palash Srivastava

Ques: In which year did Public Sector Banks launch a Credit Assessment Model based on digital footprints for MSMEs?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल किस वर्ष लॉन्च किया?

A) 2022
B) 2023
C) 2024
D) 2025
E) 2026

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Public Sector Banks launched a Credit Assessment Model based on digital footprints for MSMEs in 2025.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025 में एमएसएमई के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल शुरू किया।
• Between 1 April and 31 December 2025, more than 3.96 lakh MSME loan applications amounting to over ₹52,300 crore were sanctioned under digital credit underwriting programmes.
• 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच, डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों के तहत 3.96

लाख से अधिक एमएसएमई ऋण आवेदन, ₹52,300 करोड़ से अधिक की राशि के लिए स्वीकृत किए गए।

• The model uses digitally fetched and verifiable data to enable automated MSME loan appraisal and model-based limit assessment for both Existing-to-Bank (ETB) and New-to-Bank (NTB) borrowers.

• यह मॉडल डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का उपयोग कर ETB और NTB दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए स्वचालित ऋण मूल्यांकन करता है।

• Digital footprints used include KYC authentication, mobile & email verification, GST data analysis, bank statement analysis via Account Aggregator, ITR verification, Credit Information Companies (CICs) data, and fraud checks.

• डिजिटल फुटप्रिंट में केवाईसी प्रमाणीकरण, मोबाइल व ईमेल सत्यापन, जीएसटी डेटा विश्लेषण, अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण, आईटीआर सत्यापन, क्रेडिट सूचना कंपनियों का डेटा और धोखाधड़ी जांच शामिल हैं।

• Benefits to MSMEs include online application from anywhere, reduced paperwork and branch visits, instant in-principle sanction, faster turnaround time, objective credit decisions, and integration with CGTMSE credit guarantee schemes.

• एमएसएमई को कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन, कम कागजी कार्रवाई, कम शाखा विज़िट, त्वरित इनस्वीकृति प्रिंसिपल-, कम समय में निर्णय और CGTMSE जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं का एकीकरण का लाभ मिलता है।

• Loan applications are sourced through an end-to-end digital journey on the Jan Samarth Portal.

• ऋण आवेदन जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से एंड जाते किए प्राप्त से प्रक्रिया डिजिटल एंड-टू-हैं।

Ques: The World Bank approved a USD 286 million loan for which programme in India?

विश्व बैंक ने भारत में किस कार्यक्रम के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है?

A) National Health Mission (NHM) / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

B) Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission / आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

C) West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP) / पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम

D) National Digital Health Mission / राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
E) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana / प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The World Bank approved a loan of USD 286 million for the West Bengal Health System Reform Program (WBHSRP).
• विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम)WBHSRP) के लिए 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया।
• The loan is provided through the World Bank's financing arm, the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
• यह ऋण विश्व बैंक की वित्तीय इकाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट)IBRD) के माध्यम से दिया गया है।
• The loan has a tenure of 16.5 years with a grace period of 3 years.
• ऋण की अवधि 16.5 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष की ग्रेस पीरियड शामिल है।
• The programme aims to strengthen and reform the health system in West Bengal.
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ और सुधारना है।

Ques: The Union Cabinet approved ₹5,000 crore equity support to which institution?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता किस संस्था को दी है?

A) NABARD / नाबार्ड
B) SIDBI / सिडबी
C) RBI / आरबीआई
D) EXIM Bank / एक्ज़िम बैंक
E) NHB / एनएचबी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Union Cabinet approved equity support of ₹5,000 crore to the Small Industries Development Bank of India (SIDBI).
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया)SIDBI) को ₹5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता को मंज़ूरी दी है।
• The decision was taken under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi.
• यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया।
• The equity will be infused by the Department of Financial Services (DFS) in three tranches.
• यह इक्विटी वित्तीय सेवा विभाग)DFS) द्वारा तीन चरणों में डाली जाएगी।
• ₹3,000 crore will be infused in FY 2025–26, while ₹1,000 crore each will be provided in FY 2026–27 and FY 2027–28.
• ₹3,000 करोड़ वित्त वर्ष 2025–26 में तथा ₹1,000–₹1,000 करोड़ वित्त वर्ष 2026–27 और 2027–28 में दिए जाएंगे।
• The move will enhance SIDBI's lending capacity, improve credit flow to MSMEs, and help maintain a healthy CRAR.
• इससे SIDBI की ऋण क्षमता बढ़ेगी, MSMEs को ऋण प्रवाह बेहतर होगा और CRAR संतुलित बना रहेगा।

Ques: Which UN body projected India's GDP growth at 7.2% for FY 2025–26?
FY 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.2% किस संयुक्त राष्ट्र निकाय ने अनुमानित की?

A) UNDP / यूएनडीपी
B) IMF / आईएमएफ
C) UN DESA / यूएन DESA
D) World Bank / विश्व बैंक
E) WTO / डब्ल्यूटीओ

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) projected India's GDP growth at 7.2% for the fiscal year 2025–26.

• संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग)UN DESA) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की GDP वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान लगाया है।
• This projection is slightly lower than the Indian government's estimate of 7.4% for FY 2025–26.
• यह अनुमान भारत सरकार द्वारा लगाए गए 7.4% के अनुमान से थोड़ा कम है।
• UN DESA stated that strong domestic consumption and public investment are expected to offset the impact of global trade tensions and tariffs.
• UN DESA के अनुसार, मजबूत घरेलू उपभोग और सार्वजनिक निवेश वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित करेंगे।
• The projection was mentioned in the UN DESA report titled *World Economic Situation and Prospects*.
• यह अनुमान UN DESA की *World Economic Situation and Prospects* रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।
• India is expected to continue as one of the fastest-growing major economies in the world.
• भारत के विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बने रहने की उम्मीद जताई गई है।

Ques: Which institution has sanctioned a USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited for developing a 100 MW solar power project in Zambia?
स्वर्णा सोलर लिमिटेड को जाम्बिया में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किस संस्था ने स्वीकृत किया है?

A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
B) International Finance Corporation (IFC) / अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
C) IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) / इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड
D) World Bank / विश्व बैंक
E) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• IREDA Global Green Energy Finance IFSC Limited (IGGEFIL) has sanctioned a

USD 22.5 million loan to Swarna Solar Limited.
• इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड)IGGEFIL) ने स्वर्णा सोलर लिमिटेड को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
• The loan is for developing a 100 MW photovoltaic (PV) solar power project in Serenje District, Central Province of Zambia.
• यह ऋण जाम्बिया के सेंट्रल प्रांत के सेरेनजे जिले में 100 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए है।
• This sanction marks IGGEFIL's first international loan since its incorporation.
• यह स्वीकृति IGGEFIL के गठन के बाद दिया गया पहला अंतरराष्ट्रीय ऋण है।
• IGGEFIL is incorporated at Gujarat International Finance TecCity (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat.
• IGGEFIL का पंजीकरण गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक) सिटी-GIFT सिटी(, गांधीनगर, गुजरात में है।

Ques: Indian Army has renewed its MoU for banking and insurance services till 2029 with which bank?
भारतीय सेना ने 2029 तक बैंकिंग और बीमा सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ MoU नवीनीकृत किया है?

A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
B) Axis Bank / एक्सिस बैंक
C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Indian Army and HDFC Bank have renewed their Memorandum of Understanding (MoU) for another three years, extending it till 2029.
• भारतीय सेना और HDFC बैंक ने अपने समझौता ज्ञापन)MoU) को अगले तीन वर्षों के लिए, यानी 2029 तक नवीनीकृत किया है।
• The MoU aims to provide banking services and Personal Accident Insurance coverage to serving and retired Army personnel.

• इस MoU का उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएँ और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है।
• The agreement includes an enhanced Personal Accident Insurance cover of ₹1 crore for serving personnel, including Agniveers and pensioners.
• इस समझौते में अग्निवीरों और पेंशनरों सहित सेवारत कर्मियों के लिए ₹1 करोड़ का उन्नत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज शामिल है।
• An Air Accident Insurance cover of ₹1 crore is also provided under the MoU.
• MoU के तहत ₹1 करोड़ का एयर दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया है।
• Additional benefits include a child education cover of ₹5 lakh and a girl child marriage cover of ₹5 lakh.
• अतिरिक्त लाभों में ₹5 लाख की बाल शिक्षा सहायता और ₹5 लाख की कन्या विवाह सहायता शामिल है।

Ques: RBI has approved the re-appointment of whom as Whole-Time Director of HDFC Bank?

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति को मंज़ूरी दी है?

A) Sashidhar Jagdishan / सशिधर जगदीशन
B) Kaizad Bharucha / काइज़ाद भरूचा
C) Aditya Puri / आदित्य पुरी
D) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन
E) Uday Kotak / उदय कोटक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) approved the re-appointment of Kaizad Bharucha as Whole-Time Director (Deputy Managing Director) of HDFC Bank.
• भारतीय रिज़र्व बैंक) RBI) ने काइज़ाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक) डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंज़ूरी दी।
• The approval was communicated by RBI on 20 January 2026.
• यह स्वीकृति आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2026 को दी गई।
• His re-appointment will be for a further period of three years starting from

19 April 2026.
• उनकी पुनर्नियुक्ति 19 अप्रैल 2026 से अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
• HDFC Bank disclosed this information through a regulatory filing.
• एचडीएफसी बैंक ने इस निर्णय की जानकारी नियामक फाइलिंग के माध्यम से दी।
• After the announcement, HDFC Bank shares closed at ₹931.15 on BSE, registering a rise of 0.38%.
• घोषणा के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर बीएसई पर ₹931.15 पर बंद हुए, जिसमें 0.38% की बढ़त दर्ज की गई।

Ques: State Bank of India (SBI) signed an MoU with which state government to extend enhanced benefits under the Corporate Salary Package for State PSU employees?
भारतीय स्टेट बैंक)SBI) ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों)PSU) के कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत बढ़े हुए लाभ देने हेतु किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन)MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

A) Government of Karnataka / कर्नाटक सरकार
B) Government of Kerala / केरल सरकार
C) Government of Tamil Nadu / तमिलनाडु सरकार
D) Government of Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश सरकार
E) Government of Telangana / तेलंगाना सरकार

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India signed an MoU with the Government of Tamil Nadu.
• भारतीय स्टेट बैंक ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• The MoU aims to extend enhanced benefits under the Corporate Salary Package to employees of Tamil Nadu's State PSUs.
• इस समझौते का उद्देश्य तमिलनाडु के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों को कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत बेहतर लाभ प्रदान करना है।
• The package includes zero-balance salary accounts. It also offers concessional interest rates on home, car and personal loans, along with waiver of processing fees on select services.

• पैकेज में शून्य हैं। शामिल खाते सैलरी बैलेंस-इसके तहत गृह, कार और व्यक्तिगत ऋणों पर रियायती ब्याज दरें तथा चयनित सेवाओं पर प्रोसेसिंग फीस में छूट दी जाएगी।

Ques: The Government of India is planning the merger of which two public sector banks?
भारत सरकार किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की योजना बना रही है?

A) Punjab National Bank & Canara Bank / पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक
B) Union Bank of India & Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया
C) Bank of Baroda & Central Bank of India / बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
D) Indian Bank & UCO Bank / इंडियन बैंक और यूको बैंक
E) SBI & Bank of Maharashtra / एसबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Government of India is planning a merger between Union Bank of India and Bank of India as part of banking sector consolidation.
• भारत सरकार बैंकिंग क्षेत्र के समेकन के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के विलय की योजना बना रही है।
• The objective of the proposed merger is to strengthen Public Sector Banks (PSBs).
• प्रस्तावित विलय का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)PSBs) को मजबूत करना है।
• The merger aims to improve operational efficiency, scale of operations, and overall financial capacity.
• इस कदम का लक्ष्य परिचालन दक्षता, संचालन के पैमाने और समग्र वित्तीय क्षमता को बढ़ाना है।
• Bank consolidation is viewed as a reform to create globally competitive and resilient banks.
• बैंक समेकन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और मजबूत बैंक बनाने वाले सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

Ques: What is one of the key objectives of the RBI's revised Priority Sector Lending (PSL) guidelines effective from April 1, 2025?
1 अप्रैल 2025 से प्रभावी RBI की संशोधित प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग)PSL) गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) To completely eliminate priority sector lending / प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को पूरी तरह समाप्त करना
B) To ensure more effective delivery of bank credit to priority sectors / प्रायोरिटी सेक्टरों तक बैंक ऋण की अधिक प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करना
C) To increase service charges on small PSL loans / छोटे PSL ऋणों पर सेवा शुल्क बढ़ाना
D) To restrict lending to cooperative institutions / सहकारी संस्थानों को ऋण सीमित करना
E) To allow multiple banks to claim the same PSL loan / एक ही PSL ऋण पर कई बैंकों को दावा करने की अनुमति देना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• RBI issued revised Priority Sector Lending guidelines to improve effective delivery of bank credit to priority sectors.
• RBI ने प्रायोरिटी सेक्टरों तक बैंक ऋण की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संशोधित PSL दिशानिर्देश जारी किए हैं।
• The new PSL guidelines will come into effect from April 1, 2025.
• नई PSL गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
• RBI introduced external auditor certification to ensure that the same PSL loan is not claimed by more than one bank.
• RBI ने यह सुनिश्चित करने के लिए बाहरी ऑडिटर प्रमाणन की व्यवस्था की है कि एक ही PSL ऋण पर एक से अधिक बैंक दावा न करें।
• Loans given to the National Cooperative Development Corporation (NCDC) are now eligible for PSL, capped at 5% of a bank's total PSL.
• नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)NCDC) को दिए गए ऋण अब PSL के अंतर्गत आएंगे, जो बैंक के कुल PSL के 5% तक सीमित होंगे।
• Banks cannot charge any type of fee on PSL loans up to ₹50,000.

• ₹50,000 तक के PSL ऋणों पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकते।
• Regional Rural Banks must achieve 75% PSL of ANBC, but lending to Medium Enterprises, Social Infrastructure and Renewable Energy together is capped at 15% of ANBC.
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ANBC का 75% PSL हासिल करना होगा, लेकिन मध्यम उद्यम, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा को मिलाकर 15% तक ही गिना जाएगा।
• Under amended norms, PSL targets for Small Finance Banks and Urban Co-operative Banks have been reduced from 75% to 60% of ANBC.
• संशोधित नियमों के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंकों और अर्बन को का बैंकों ऑपरेटिव-PSL लक्ष्य 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है।
• Co-lending for PSL is now permitted among Scheduled Commercial Banks themselves.
• अब PSL के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच आपसी को गई दी अनुमति की लेंडिंग- है।
• Loans to National Cooperative Development Corporation (NCDC) are now eligible for PSL, capped at 5% of the bank's total PSL.
• नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) को दिए गए ऋण अब पीएसएल के लिए पात्र हैं, जो बैंक के कुल पीएसएल के 5% तक सीमित है।

Ques: What was the credit-to-deposit (CD) ratio of Indian banks as of December 31, according to RBI data?
RBI के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात कितना रहा?

A) 75.25%
B) 78.60%
C) 80.10%
D) 81.75%
E) 85.00%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Indian banks' credit-to-deposit (CD) ratio rose to an all-time high of 81.75% as of December 31, as per RBI data.

• RBI के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर तक भारतीय बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) अनुपात रिकॉर्ड 81.75% तक पहुँच गया।
• A CD ratio of 81.75% means banks lend ₹81.75 for every ₹100 deposited.
• 81.75% के CD अनुपात का अर्थ है कि बैंक हर ₹100 जमा पर ₹81.75 का ऋण देते हैं।
• The record-high CD ratio indicates that bank credit growth is outpacing deposit growth.
• यह रिकॉर्ड CD अनुपात दर्शाता है कि बैंक ऋण की वृद्धि, जमाओं की वृद्धि से तेज़ है।
• In 2025, bank credit grew by 11.4%, while deposits increased by 10.1%.
• वर्ष 2025 में बैंक ऋण 11.4% बढ़ा, जबकि जमाओं में केवल 10.1% की वृद्धि हुई।
• Outstanding deposits were around ₹248.5 लाख करोड़, while outstanding credit stood at nearly ₹202 लाख करोड़.
• कुल बकाया जमाएँ लगभग ₹248.5 लाख करोड़ रहीं, जबकि कुल ऋण लगभग ₹202 लाख करोड़ तक पहुँच गया।

Ques : What is the minimum initial and annual contribution required under the NPS Vatsalya Scheme as per PFRDA Guidelines 2025?
PFRDA द्वारा जारी NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 के अनुसार न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान कितना है?

A) ₹100
B) ₹250
C) ₹500
D) ₹1,000
E) ₹2,000

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) issued the NPS Vatsalya Scheme Guidelines 2025 to strengthen long-term financial security for minors.
• पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण)PFRDA) ने नाबालिगों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए NPS वात्सल्य योजना दिशानिर्देश 2025 जारी किए।
• NPS Vatsalya is a contributory savings and long-term financial security

scheme designed exclusively for minors.
• NPS वात्सल्य एक योगदान आधारित बचत एवं दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा योजना है, जिसे विशेष रूप से नाबालिगों के लिए तैयार किया गया है।
• The scheme was announced in the Union Budget 2024–25 and launched on 18 September 2024 by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
• इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई थी और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया।
• The scheme is open to all Indian citizens, including NRI/OCI, below 18 years of age.
• यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिकों)NRI/OCI सहित खुली लिए के (है।
• The minor is the sole beneficiary; the account is opened in the minor's name and operated by the guardian.
• नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी होता है; खाता नाबालिग के नाम पर खुलता है और अभिभावक द्वारा संचालित होता है।
• The minimum initial and annual contribution under the scheme is ₹250, with no maximum limit.
• योजना के तहत न्यूनतम प्रारंभिक एवं वार्षिक योगदान ₹250 है और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
• Contributions can also be gifted by relatives and friends.
• रिश्तेदार और मित्र भी उपहार के रूप में योगदान कर सकते हैं।
• Partial withdrawal is allowed after completion of three years from account opening.
• खाता खोलने के तीन वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।
• Up to 25% of own contributions (excluding returns) can be withdrawn.
• केवल स्वयं के योगदान का 25% तक (रिटर्न को छोड़करहै। सकता जा निकाला (
• Withdrawals are permitted for education, medical treatment, and specified disabilities.
• शिक्षा, चिकित्सा उपचार और निर्दिष्ट दिव्यांगता के लिए निकासी की अनुमति है।
• Partial withdrawal is allowed twice before 18 years and twice between 18–21 years, subject to conditions.
• 18 वर्ष से पहले दो बार और 18–21 वर्ष के बीच दो बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है।

Ques : Which institution has revamped its ATM infrastructure to make banking services more accessible and user-friendly across the country?

देशभर में बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए किस संस्था ने अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है?

A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) Department of Posts / डाक विभाग
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• In a major step towards enhancing financial inclusion, the Department of Posts has revamped its ATM infrastructure across India.
• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाक विभाग ने देशभर में अपनी ATM अवसंरचना का नवीनीकरण किया है।
• A total of 887 ATMs have been installed at various post offices, enabling citizens to access essential banking services near their homes.
• विभिन्न डाकघरों में 887 ATM स्थापित किए गए हैं, जिससे नागरिकों को अपने घर के पास ही आवश्यक बैंकिंग सेवाएँ मिल सकें।
• These ATMs allow customers to withdraw cash, check account balances, and perform other basic banking transactions conveniently.
• इन ATM के माध्यम से ग्राहक नकद निकासी, खाता शेष जांच और अन्य बुनियादी बैंकिंग लेन-देन आसानी से कर सकते हैं।
• The initiative strengthens the role of post offices as important centers for last-mile banking services in rural and urban areas.
• यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लास्ट-माइल बैंकिंग सेवाओं के रूप में डाकघरों की भूमिका को मजबूत करती है।

Ques: Why has the Reserve Bank of India (RBI) proposed reopening the licensing window for new Urban Co-operative Banks (UCBs) after 22 years?
22 वर्षों बाद RBI ने नए शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए लाइसेंसिंग विंडो फिर से खोलने का प्रस्ताव क्यों रखा है?

A) To privatise Urban Co-operative Banks / शहरी सहकारी बैंकों का निजीकरण करने के लिए

B) To increase foreign investment in UCBs / UCBs में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए

C) After sector reforms, to allow eligible cooperative credit societies to become banks / क्षेत्रीय सुधारों के बाद योग्य सहकारी ऋण संस्थाओं को बैंक बनने की अनुमति देने के लिए

D) Due to shortage of scheduled commercial banks / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कमी के कारण

E) To merge all UCBs with public sector banks / सभी UCBs को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय करने के लिए

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The RBI has proposed reopening the licensing window for new Urban Co-operative Banks after 22 years.

• RBI ने 22 वर्षों बाद नए शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

• The previous licensing window was closed in 2004 due to widespread failures of newly licensed UCBs.

• वर्ष 2004 में नए लाइसेंस प्राप्त UCBs की व्यापक विफलताओं के कारण यह प्रक्रिया बंद कर दी गई थी।

• At that time, around 31% of newly licensed Urban Co-operative Banks had failed.

• उस समय लगभग 31% नए लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक असफल हो गए थे।

• Under the proposed norms, a cooperative credit society must have a minimum capital of ₹300 crore as on March 31 of the preceding financial year to apply for a banking licence.

• प्रस्तावित नियमों के अनुसार, किसी सहकारी ऋण संस्था के पास पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक न्यूनतम ₹300 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए।

• The assessed Capital Adequacy Ratio (CAR) should not be less than 12% at the time of grant of licence.

• लाइसेंस दिए जाने के समय आकलित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 12% से कम नहीं होना चाहिए।

• The net Non-Performing Assets (NPA) ratio should not exceed 3%.

• शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का अनुपात 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।

• After multiple reforms in the cooperative banking sector, RBI is now reconsidering restarting the licensing process.
• सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधारों के बाद अब RBI लाइसेंसिंग प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रहा है।

Ques : By which platform will EPFO subscribers be able to withdraw EPF money directly into their bank accounts from April?
अप्रैल से EPFO सदस्य किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे?

A) NEFT / एनईएफटी
B) RTGS / आरटीजीएस
C) IMPS / आईएमपीएस
D) UPI / यूपीआई
E) AEPS / एईपीएस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• EPFO subscribers will be able to withdraw their Employees' Provident Fund (EPF) directly into bank accounts through the UPI payment gateway by April.
• EPFO सदस्य अप्रैल तक UPI पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में EPF राशि निकाल सकेंगे।
• The auto-settlement withdrawal limit has been increased from ₹1 lakh to ₹5 lakh, enabling higher instant withdrawals.
• ऑटो को सीमा निकासी सेटलमेंट-₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
• This move will allow EPFO members to access funds within three days for purposes such as illness, education, marriage, and housing.
• इस कदम से EPFO सदस्यों को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के लिए 3 दिनों के भीतर धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
• The Labour Ministry is working on a system where a part of EPF savings will be frozen, while a major portion will be available for quick withdrawal via UPI.
• श्रम मंत्रालय ऐसी प्रणाली पर काम कर रहा है जिसमें EPF का एक हिस्सा फ्रीज रहेगा, जबकि बड़ा हिस्सा UPI के जरिए त्वरित निकासी के लिए उपलब्ध होगा।

• The current interest rate on EPF deposits is 8.25% per annum.
• वर्तमान में EPF पर ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।

Ques : When will the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026 come into effect?
रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 कब से प्रभावी होगी?

A) January 1, 2026
B) April 1, 2026
C) July 1, 2025
D) October 1, 2026
E) July 1, 2026

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank–Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) 2026, a revised grievance redressal framework aimed at simplifying complaint resolution for customers of banks and other financial institutions.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिज़र्व बैंक–एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS) 2026 जारी की है, जिसका उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाना है।
• The RB-IOS 2026 supersedes the earlier RB-IOS 2021 and will be effective from July 1, 2026.
• RB-IOS 2026, RB-IOS 2021 का स्थान लेगी और 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
• The Scheme applies to various Regulated Entities, including commercial banks, co-operative banks, eligible NBFCs, non-bank PPI issuers, and credit information companies.
• यह योजना विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, पात्र NBFC, नॉन-बैंक PPI जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ शामिल हैं।
• There is no monetary limit on disputes that can be taken to the RBI Ombudsman.
• RBI लोकपाल के समक्ष लाए जाने वाले विवादों की कोई राशि सीमा नहीं है।
• The compensation limit for consequential loss has been increased to ₹30 lakh

(previously Rs 20 lakh), and up to ₹3 lakh(previously Rs 1 lakh), can be awarded for mental agony, harassment, and expenses.
• परिणामी नुकसान के लिए मुआवज़ा सीमा ₹30 लाख कर दी गई है, जबकि मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न आदि के लिए ₹3 लाख तक का मुआवज़ा दिया जा सकता है।
• RBI will set up a Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) for handling complaints under the scheme.
• RBI शिकायतों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित करेगा।
• RBI Ombudsman and Deputy Ombudsman will be appointed for a three-year term.
• RBI लोकपाल और उप-लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

Ques: Public Sector Banks (PSBs) sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications worth more than ₹52,300 crore under which digital initiative during April–December 2025?
अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किस डिजिटल पहल के तहत 3.96 लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन स्वीकृत किए?

A) Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) / आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना
B) Jan Samarth Portal / जन समर्थ पोर्टल
C) Credit Assessment Model (CAM) based digital underwriting / क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) आधारित डिजिटल अंडरराइटिंग
D) MSME Credit Guarantee Scheme / MSME क्रेडिट गारंटी योजना
E) Account Aggregator Framework / अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Public Sector Banks sanctioned over 3.96 lakh MSME loan applications amounting to more than ₹52,300 crore between April 1 and December 31, 2025.
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के बीच 3.96 लाख से अधिक MSME ऋण आवेदन, ₹52,300 करोड़ से अधिक राशि के, स्वीकृत किए।

• These loans were sanctioned under digital credit underwriting programmes.
• ये ऋण डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए।
• In 2025, PSBs launched the Credit Assessment Model (CAM) for MSMEs.
• वर्ष 2025 में PSBs ने MSMEs के लिए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (CAM) शुरू किया।
• CAM is based on digital footprints of Micro, Small and Medium Enterprises.
• CAM सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित है।
• The initiative aims to enable faster, data-driven and transparent credit flow to MSMEs.
• इस पहल का उद्देश्य MSMEs को तेज़, डेटा-आधारित और पारदर्शी ऋण उपलब्ध कराना है।

Ques : Which foreign bank has received approval to acquire a majority stake in RBL Bank Limited?
किस विदेशी बैंक को RBL बैंक लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने की मंज़ूरी मिली है?

A) Emirates NBD Bank / एमिरेट्स NBD बैंक
B) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
C) HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक
D) DBS Bank / डीबीएस बैंक
E) Barclays Bank / बार्कलेज बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Commission has approved the proposed acquisition of shareholding in RBL Bank Limited by Emirates NBD Bank (P.J.S.C.).
• आयोग ने एमिरेट्स NBD बैंक (P.J.S.C.) द्वारा RBL बैंक लिमिटेड में हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंज़ूरी दी है।
• The proposed combination involves acquisition of up to 74% (minimum 51%) shareholding in RBL Bank.
• प्रस्तावित सौदे के तहत RBL बैंक में न्यूनतम 51% और अधिकतम 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।
• This acquisition will be carried out through a mandatory open offer (up to

26%) under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, along with a preferential allotment of up to 60% equity shares.
• यह अधिग्रहण SEBI (SAST) विनियम, 2011 के तहत अनिवार्य ओपन ऑफर (26% तक) और प्राथमिक आवंटन (60% तक इक्विटी शेयर) के माध्यम से किया जाएगा।
• Additionally, Emirates NBD's banking operations in India, currently operating through three branches, will be amalgamated with RBL Bank on a going concern basis.
• इसके अतिरिक्त, भारत में एमिरेट्स NBD की तीन शाखाओं के माध्यम से संचालित बैंकिंग परिचालन को RBL बैंक में विलय किया जाएगा।
• Emirates NBD Bank is a public joint stock company, listed on the Dubai Financial Market, and is headquartered in Dubai, UAE.
• एमिरेट्स NBD बैंक एक पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट में सूचीबद्ध है और इसका मुख्यालय दुबई, UAE में स्थित है।

About RBL Bank Limited:

- Established : 1943
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- MD & CEO : R Subramaniakumar
- Tagline : Apno ka bank

Ques : From which date will the new FEMA Export-Import Regulations, 2026 come into effect?
नई FEMA निर्यात-आयात विनियम, 2026 किस तिथि से लागू होंगे?

A) 1 April 2026 / 1 अप्रैल 2026
B) 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026
C) 1 October 2026 / 1 अक्टूबर 2026
D) 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027
E) 15 August 2026 / 15 अगस्त 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has notified the Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, *2026*.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात-आयात) विनियम, *2026* को अधिसूचित किया है।
• The new FEMA trade regulations will come into effect from 1 October 2026.
• नई FEMA व्यापार नियमावली 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
• Authorised Dealer (AD) banks must enter Export Declaration Form (EDF) details for goods exported through non-EDI ports into the Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) within five working days.
• अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को नॉन-EDI पोर्ट्स से निर्यात किए गए माल का EDF विवरण 5 कार्यदिवस के भीतर EDPMS प्रणाली में दर्ज करना होगा।
• AD banks are also required to upload EDF details of services exports into EDPMS within five working days of receipt from exporters.
• AD बैंकों को निर्यातकों से प्राप्त सेवा निर्यात के EDF विवरण भी 5 कार्यदिवस के भीतर EDPMS में अपलोड करने होंगे।
• The move aims to strengthen export-import data monitoring, improve compliance, and enhance transparency under FEMA.
• इस कदम का उद्देश्य FEMA के तहत निर्यात-आयात डेटा निगरानी को मजबूत करना, अनुपालन बढ़ाना और पारदर्शिता में सुधार करना है।

Ques : According to the *International Monetary Fund (IMF)'s World Economic Outlook (WEO)* titled "Global Economy: Steady amid Divergent Forces", what is the revised GDP growth projection for India for FY 2025–26?
"ग्लोबल इकोनॉमी :स्टेडी अमिड डाइवर्जेंट फोर्सेस" शीर्षक वाली IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

A) 6.4%
B) 6.6%
C) 7.0%
D) 7.3%
E) 7.4%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The International Monetary Fund (IMF) released its World Economic Outlook (WEO) titled *"Global Economy: Steady amid Divergent Forces"*.
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने *"ग्लोबल इकोनॉमी: स्टेडी अमिड डाइवर्जेंट फोर्सेस"* शीर्षक से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) जारी की।
• The IMF upwardly revised India's GDP growth forecast for FY 2025–26 to 7.3%, from 6.6% projected in October 2025.
• IMF ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अक्टूबर 2025 के 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया।
• This projection is slightly lower than the Government of India's estimate of 7.4% for the same period.
• यह अनुमान भारत सरकार के 7.4% के आकलन से थोड़ा कम है।
• The IMF further projected that India's growth would moderate to 6.4% in both FY 2026–27 and FY 2027–28.
• IMF के अनुसार FY27 और FY28 में भारत की वृद्धि दर 6.4% पर आ सकती है।

Ques: What is the key proposal in the RBI's draft amendment directions regarding the calculation of Owned Fund / Tier-1 Capital for NBFCs and ARCs?
NBFCs और ARCs के लिए ओन्ड फंड / टियर-1 कैपिटल की गणना से संबंधित RBI के मसौदा संशोधन निर्देशों का प्रमुख प्रस्ताव क्या है?

A) Excluding free reserves completely from Owned Fund / ओन्ड फंड से फ्री रिज़र्व को पूरी तरह हटाना
B) Allowing Tier-1 Capital calculation only once every three years / टियर-1 कैपिटल की गणना केवल तीन वर्षों में एक बार करना
C) Including free reserves and quarterly profits in Owned Fund with conditions / शर्तों के साथ फ्री रिज़र्व और त्रैमासिक लाभ को ओन्ड फंड में शामिल करना
D) Increasing credit concentration limits for NBFCs / NBFCs के लिए क्रेडिट एकाग्रता सीमा बढ़ाना
E) Removing concentration norms for ARCs / ARCs के लिए एकाग्रता मानदंड समाप्त करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India issued draft amendment directions to clarify the calculation of Owned Fund / Tier-1 Capital for NBFCs and Asset Reconstruction Companies (ARCs).
• RBI ने NBFCs और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) के लिए ओन्ड फंड / टियर-1 कैपिटल की गणना स्पष्ट करने हेतु मसौदा संशोधन निर्देश जारी किए।
• The draft aims to ensure proper compliance with credit and investment concentration limits.
• इसका उद्देश्य क्रेडिट और निवेश एकाग्रता सीमाओं के पालन को सुनिश्चित करना है।
• RBI has invited public comments on the draft till 28 January 2026.
• RBI ने इस मसौदे पर 28 जनवरी 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं।
• Currently, NBFCs (other than NBFC-UL) and ARCs calculate Tier-1 Capital based on figures as of 31 March of the previous year.
• वर्तमान में NBFCs (NBFC-UL को छोड़कर) और ARCs पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार टियर-1 कैपिटल की गणना करते हैं।
• Under the new draft, free reserves, including quarterly profits, may be included in Owned Fund, subject to specified conditions.
• नए मसौदे के तहत, निर्धारित शर्तों के अधीन फ्री रिज़र्व, जिसमें त्रैमासिक लाभ भी शामिल हैं, को ओन्ड फंड में जोड़ा जा सकता है।
• Eligible profits will be reduced by 25% of the average dividend paid over the last three years, multiplied by the number of completed quarters in the year.
• पात्र लाभ से पिछले तीन वर्षों में दिए गए औसत लाभांश का 25%, वर्ष में पूर्ण हुए तिमाहियों की संख्या से गुणा कर, घटाया जाएगा।

Ques : What was the unemployment rate (UR) among persons aged 15 years and above in India as per the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletin – December 2025?
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मासिक बुलेटिन – दिसंबर 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोज़गारी दर कितनी रही?

A) 4.5%
B) 4.7%
C) 4.8%
D) 5.1%
E) 6.7%

Answer : Option C

Explanation | व्याख्या

• The National Statistical Office (NSO) under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the 9th edition of the PLFS Monthly Bulletin – December 2025.
• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने PLFS मासिक बुलेटिन – दिसंबर 2025 का 9वाँ संस्करण जारी किया।
• The overall unemployment rate (UR) for persons aged 15 years and above remained stable at 4.8% in December 2025, compared to 4.7% in November 2025.
• 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल बेरोज़गारी दर 4.8% रही, जो नवंबर 2025 के 4.7% के लगभग समान है।
• The rural unemployment rate remained unchanged at 3.9%.
• ग्रामीण बेरोज़गारी दर 3.9% पर स्थिर रही।
• The urban unemployment rate increased to 6.7%, up from 6.5% in the previous month.
• शहरी बेरोज़गारी दर 6.5% से बढ़कर 6.7% हो गई।
• Unemployment Rate (UR) is defined as the percentage of people in the labour force who are without work but are available for and actively seeking employment.
• बेरोज़गारी दर (UR) का अर्थ है—श्रम बल में शामिल वे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम के लिए उपलब्ध हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

Ques : Who has been appointed as the part-time Chairman of IndusInd Bank effective January 31?
31 जनवरी से इंडसइंड बैंक के पार्टहै गया किया नियुक्त किसे में रूप के चेयरमैन टाइम-?

A) Rajiv Anand / राजीव आनंद
B) Sunil Mehta / सुनील मेहता
C) Arijit Basu / अरिजीत बसु
D) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
E) Dinesh Kumar Khara / दिनेश कुमार खारा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• IndusInd Bank has appointed veteran banker Arijit Basu as its part-time Chairman with effect from January 31.
• इंडसइंड बैंक ने वरिष्ठ बैंकर अरिजीत बसु को 31 जनवरी से अपना पार्ट चेयरमैन टाइम- है। किया नियुक्त
• He will succeed Sunil Mehta after the completion of his tenure.
• वह सुनील मेहता के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उनका स्थान लेंगे।
• Arijit Basu has over 42 years of banking experience, including 37 years with the State Bank of India (SBI).
• अरिजीत बसु के पास 42 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव है, जिसमें 37 वर्ष SBI में शामिल हैं।
• He joined SBI in 1983 and retired in 2020 as Managing Director.
• उन्होंने 1983 में SBI जॉइन किया और 2020 में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
• He earlier served as Managing Director & CEO of SBI Life Insurance from 2014 to 2018.
• वह 2014 से 2018 तक SBI लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO भी रह चुके हैं।
• He also served as Chairman of HDB Financial Services, the NBFC arm of HDFC Bank.
• वह HDFC बैंक की NBFC शाखा, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
• The appointment comes at a time when IndusInd Bank has witnessed leadership changes following governance-related issues.
• यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों के बाद इंडसइंड बैंक में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिले हैं।

Ques: Suryoday Small Finance Bank has partnered with which company to deploy an AI-powered Video KYC (VKYC) solution?
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-आधारित वीडियो KYC (VKYC) समाधान लागू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

A) HyperVerge / हाइपरवर्ज
B) TCS / टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
C) Infosys / इंफोसिस
D) Paytm / पेटीएम

E) Razorpay / रेज़रपे

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Suryoday Small Finance Bank has partnered with HyperVerge to implement an AI-powered Video KYC (VKYC) solution.
• सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-आधारित वीडियो KYC समाधान लागू करने के लिए HyperVerge के साथ साझेदारी की है।
• The collaboration aims to modernize the customer onboarding process while maintaining strong regulatory compliance.
• इस सहयोग का उद्देश्य ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है।
• The AI-driven VKYC solution also enhances data security and operational efficiency.
• AI-आधारित VKYC समाधान डेटा सुरक्षा और परिचालन दक्षता को भी मजबूत करता है।

About Suryoday Small Finance Bank :

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- MD & CEO : Baskar Babu Ramachandran
- Tagline : A Bank of Smiles

Ques: Which TReDS platform became the first in India to declare and pay an interim dividend, marking a historic milestone in the TReDS ecosystem?
भारत का कौन सा TReDS प्लेटफॉर्म अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान करने वाला पहला बना, जिससे TReDS पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई?

A) M1xchange / एम1एक्सचेंज
B) A.TReDS / ए.टी.आर.डी.एस.
C) Receivables Exchange of India Limited (RXIL) / रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल)
D) Invoicemart / इनवॉइसमार्ट

E) SIDBI TReDS / एसआईडीबीआई टी.आर.डी.एस.

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Receivables Exchange of India Limited (RXIL), a Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform, declared and paid an interim dividend of 21.6% on the face value of its shares.
• ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म RXIL ने अपने शेयरों के अंकित मूल्य पर 21.6% का अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया।
• RXIL is the first TReDS platform in India to return capital to its stakeholders, marking a historic milestone in India's TReDS ecosystem.
• RXIL भारत का पहला TReDS प्लेटफॉर्म है जिसने हितधारकों को पूंजी लौटाई, जो TReDS पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक कदम है।
• RXIL received RBI approval in December 2016 and executed its first TReDS transaction on 9 January 2017.
• RXIL को दिसंबर 2016 में RBI की मंजूरी मिली थी और उसने 9 जनवरी 2017 को पहला TReDS लेनदेन किया।
• RXIL is a joint venture of SIDBI and NSE, along with SBI, ICICI Bank, and Yes Bank as partners.
• RXIL, SIDBI और NSE का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें SBI, ICICI बैंक और Yes बैंक भागीदार हैं।

Ques : Which Indian fintech firm received NPCI approval to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP)?
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन की मंजूरी किस भारतीय फिनटेक कंपनी को मिली?

A) PhonePe / फोनपे
B) Paytm / पेटीएम
C) ZET / ज़ेट
D) BharatPe / भारतपे
E) Cred / क्रेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Credit-focused Indian fintech firm ZET secured approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
• क्रेडिट-केंद्रित भारतीय फिनटेक कंपनी ZET को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन हेतु NPCI से मंजूरी मिली।
• The service is enabled through a banking partnership with RBL Bank, earlier known as Ratnakar Bank Limited.
• यह सेवा आरबीएल बैंक (पूर्व में रत्नाकर बैंक लिमिटेड) के साथ बैंकिंग साझेदारी के माध्यम से सक्षम की गई है।
• The platform is powered by Juspay's technology infrastructure for transaction processing.
• यह प्लेटफॉर्म लेन-देन प्रसंस्करण के लिए Juspay की तकनीकी अवसंरचना पर आधारित है।

Ques : Who has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of Karnataka Bank Limited?
कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Srikrishnan Hari Hara Sarma / श्रीकृष्णन हरि हर सरमा
B) Raghavendra Srinivas Bhat / राघवेंद्र श्रीनिवास भट
C) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन
D) Ashok Chandra / अशोक चंद्र
E) Murali Natrajan / मुरली नटराजन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Mr. Raghavendra Srinivas Bhat has been appointed as the Managing Director (MD) and Chief Executive Officer (CEO) of Karnataka Bank Limited.
• श्री राघवेंद्र श्रीनिवास भट को कर्नाटक बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
• He replaced Srikrishnan Hari Hara Sarma.
• उन्होंने श्रीकृष्णन हरि हर सरमा का स्थान लिया है।
• Karnataka Bank was established in 1924.
• कर्नाटक बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी।
• The headquarters of Karnataka Bank is located in Mangaluru, Karnataka.
• कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।
• The tagline of Karnataka Bank is "Your Family Bank Across India".
• कर्नाटक बैंक का टैगलाइन "Your Family Bank Across India" है।

Ques : After the 4th phase of consolidation, how many Regional Rural Banks (RRBs) are operational in India?
चौथे चरण के विलय के बाद भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)RRB) कार्यरत हैं?

A) 43
B) 35
C) 28
D) 30
E) 25

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Finance Ministry held its first high-level meeting with heads of Public Sector Banks (PSBs) and Regional Rural Banks (RRBs) after the 4th phase of RRB consolidation, effective from May 1.
• वित्त मंत्रालय ने 1 मई से लागू RRB विलय के चौथे चरण के बाद PSB और RRB प्रमुखों के साथ पहली उच्चकी। बैठक स्तरीय-
• After the latest consolidation, the number of RRBs reduced from 43 to 28.
• नवीनतम विलय के बाद RRB की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई।
• On May 1, 15 RRBs across 11 states were merged to form state-owned RRBs to improve efficiency and reduce operational costs.

• 1 मई को 11 राज्यों के 15 RRB का विलय कर दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के उद्देश्य से राज्य वाले स्वामित्व-RRB बनाए गए।

• Phase-wise RRB consolidation:
– Phase 1 (FY 2006–10): 196 → 82
– Phase 2 (FY 2013–15): 82 → 56
– Phase 3: 56 → 43

• चरणबद्ध RRB विलय:
– चरण 1 (FY 2006–10): 196 → 82
– चरण 2 (FY 2013–15): 82 → 56
– चरण 3: 56 → 43

• RRBs were established under the RRB Act, 1976 to provide credit to small farmers, agricultural labourers, and artisans.
• RRB की स्थापना RRB अधिनियम, 1976 के तहत छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और कारीगरों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई।
• The Act was amended in 2015, allowing RRBs to raise capital from sources other than the Centre, States, and sponsor banks.
• 2015 के संशोधन से RRB को केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति मिली।
• Authorised capital was increased from ₹5 crore to ₹2,000 crore, with minimum authorised capital raised to ₹1 crore.
• अधिकृत पूंजी ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ की गई और न्यूनतम अधिकृत पूंजी ₹1 करोड़ तय की गई।
• Even after dilution, the combined stake of the Centre and sponsor banks cannot fall below 51%.
• हिस्सेदारी घटने के बाद भी केंद्र और प्रायोजक बैंकों की संयुक्त हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती।
• Current shareholding pattern: Centre (50%), Sponsor Banks (35%), State Governments (15%).
• वर्तमान हिस्सेदारी संरचना) केंद्र :50%), प्रायोजक बैंक)35%), राज्य सरकार)15%)।
• The Finance Ministry also unveiled a new unified logo for RRBs symbolising trust, growth, progress, support, and empowerment.
• वित्त मंत्रालय ने RRB के लिए नया एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया, जो विश्वास, विकास, प्रगति, सहयोग और सशक्तिकरण को दर्शाता है।

Ques : What was the growth rate of Foreign Direct Investment (FDI) inflows into India in 2025?
2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)FDI) प्रवाह की वृद्धि दर क्या रही?

A) 25%
B) 40%
C) 55%
D) 73%
E) 90%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• FDI inflows into India rose by 73% to USD 47 billion in 2025.
• 2025 में भारत में FDI प्रवाह 73% बढ़कर 47 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
• The growth was driven mainly by investments in manufacturing, services, digital infrastructure, IT and R&D.
• यह वृद्धि विनिर्माण, सेवाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और R&D में निवेश के कारण हुई।
• In contrast, FDI inflows into China declined for the third consecutive year, falling 8% to USD 107.5 billion.
• इसके विपरीत, चीन में FDI प्रवाह लगातार तीसरे वर्ष 8% घटकर 107.5 अरब डॉलर रहा।
• Globally, FDI flows increased by 14% to about USD 1.6 trillion in 2025, with uneven regional growth.
• वैश्विक स्तर पर FDI प्रवाह 14% बढ़कर लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर रहा, हालांकि क्षेत्रीय असमानता बनी रही।
• The United States remained the largest FDI recipient, led by cross-border M&A in technology and semiconductors.
• प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सीमा अमेरिका कारण के अधिग्रहण एवं विलय पार- बड़ा सबसेFDI प्राप्तकर्ता बना रहा।

Ques : Which company has received in-principle approval from the Reserve Bank of India to operate as a Payment Aggregator – Cross Border (PA-CB)?
भारतीय रिज़र्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर–क्रॉस बॉर्डर)PA-CB) के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किस कंपनी को मिली है?

A) Payoneer India Private Limited / पेयोनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
B) Razorpay / रेज़रपे
C) Paytm Payments Services / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज
D) Stripe India / स्ट्राइप इंडिया
E) Worldline India / वर्ल्डलाइन इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• RBI granted in-principle approval to Payoneer India Private Limited, a subsidiary of US-based Payoneer Global, to operate as a PA–Cross Border.
• RBI के अनुसार, पेयोनीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)Payoneer Global की सहायक कंपनी को (PA–क्रॉस बॉर्डर के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
• Non-bank PAs must maintain minimum net worth norms, follow ₹25 lakh per-transaction limit, and keep separate import–export accounts without netting.
• गैर बैंक-PA को न्यूनतम नेट वर्थ मानदंड, ₹25 लाख प्रति लेनआयात और सीमा देन-–निर्यात के लिए अलग खाते बनाए रखने होंगे।

Ques : What is the percentage hike approved in the wage bill for employees of Public Sector General Insurance Companies (PSGICs)?
पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों)PSGICs) के कर्मचारियों के वेतन बिल में कितनी प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है?

A) 8% / 8%
B) 10% / 10%
C) 12.41% / 12.41%
D) 14% / 14%
E) 18% / 18%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Central Government has approved the wage revision for Public Sector General Insurance companies (PSGICs) and National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Additionally, it has approved pension revision for retirees of Reserve Bank of India (RBI) and NABARD.
• केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
• The Central Government approved wage revision for PSGIC employees effective from 01.08.2022.
• केंद्र सरकार ने PSGIC कर्मचारियों के लिए 01.08.2022 से वेतन संशोधन को मंजूरी दी है।
• The overall increase in the wage bill is 12.41%, including a 14% hike in Basic Pay and Dearness Allowance.
• कुल वेतन बिल में 12.41% की वृद्धि की गई है, जिसमें बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते में 14% की बढ़ोतरी शामिल है।
• NPS contribution for employees who joined after 01.04.2010 has been enhanced from 10% to 14%.
• 01.04.2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है।
• Family pension has been revised to a uniform rate of 30% from the date of official gazette notification.
• फैमिली पेंशन को राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से समान रूप से 30% कर दिया गया है।
• The total financial outgo for PSGIC-related revisions is estimated at Rs 8,170.30 crore.
• PSGIC से जुड़े संशोधनों पर कुल वित्तीय भार लगभग 8,170.30 करोड़ रुपये आंका गया है।

NABARD

• All Group "A," "B," and "C" employees at NABARD will have a wage and benefit increase of roughly 20% starting on November 1, 2022.
• NABARD के सभी ग्रुप "A," "B," और "C" कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 1 नवंबर, 2022 से लगभग 20% की वृद्धि होगी।
• NABARD retirees who were initially hired by the organization and retired prior to November 1st, 2017, now get a basic pension or family pension that is comparable to that of former RBI NABARD retirees.
• NABARD के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें संगठन द्वारा शुरू में नियुक्त किया गया था और जो 1 नवंबर, 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें अब पूर्व RBI NABARD के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन मिलेगी।

RBI

• With effect from November 1st, 2022, the authorized revision will increase pensions and family pensions by 10% on base pension plus dearness relief.
• 1 नवंबर, 2022 से प्रभावी, स्वीकृत संशोधन के अनुसार मूल पेंशन और महंगाई राहत में 10% की वृद्धि के साथ पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि होगी।
• The anticipated overall financial impact is ₹2,696.82 crore, comprising a recurrent annual cost of ₹211.80 crore and a one-time expenditure of ₹2,485.02 crore towards arrears.
• अनुमानित कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,696.82 करोड़ है, जिसमें ₹211.80 करोड़ की आवर्ती वार्षिक लागत और बकाया राशि के लिए ₹2,485.02 करोड़ का एकमुश्त व्यय शामिल है।

Ques : Pine Labs has partnered with which bank to build a payment acquiring system in the UAE?
UAE में पेमेंट अक्वायरिंग सिस्टम बनाने के लिए Pine Labs ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

A) Emirates NBD / एमिरेट्स एनबीडी
B) First Abu Dhabi Bank / फर्स्ट अबू धाबी बैंक
C) Mashreq Bank / माशरेक बैंक
D) Wio Bank / Wio बैंक
E) Abu Dhabi Commercial Bank / अबू धाबी कमर्शियल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Indian payments technology company Pine Labs has partnered with UAE-based Wio Bank to build a payment acquiring system.
• भारतीय भुगतान तकनीक कंपनी पाइन लैब्स ने UAE स्थित Wio बैंक के साथ पेमेंट अक्वायरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए साझेदारी की है।
• As part of the partnership, Wio Bank will deploy Credit+, Pine Labs' API-based acquiring platform.
• इस साझेदारी के तहत Wio बैंक Pine Labs का API आधारित प्लेटफॉर्म Credit+ तैनात करेगा।

• Acquiring platforms help merchants process digital payments efficiently.
• अक्वायरिंग प्लेटफॉर्म व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रोसेस करने में सहायता करते हैं।
• Pine Labs currently offers Credit+ services in India, Sri Lanka, Middle East, Africa, and Southeast Asia.
• Pine Labs वर्तमान में भारत, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिणमे एशिया पूर्व-ं Credit+ सेवाएं प्रदान करता है।
• The partnership strengthens digital payment infrastructure in the UAE.
• यह साझेदारी UAE के डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करेगी।

Ques: PhonePe recently received SEBI approval to launch its IPO. Which of the following statements about the IPO is/are correct?
हाल ही में PhonePe को अपना IPO लॉन्च करने के लिए SEBI की मंजूरी मिली। IPO से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. The IPO aims to raise about ₹12,000 crore, mainly through a pure Offer for Sale (OFS).
1. आईपीओ का उद्देश्य मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से लगभग ₹12,000 करोड़ जुटाना है।

2. The IPO will include fresh capital infusion into the company.
2. आईपीओ के माध्यम से कंपनी में नई पूंजी का निवेश होगा।

3. Walmart will sell around 9.06% stake (about 4.59 crore shares) through the IPO.
3. वॉलमार्ट आईपीओ के जरिए लगभग 9.06% हिस्सेदारी (लगभग 4.59 करोड़ शेयर) बेचेगी।

4. Microsoft and Tiger Global will completely exit PhonePe by selling their shares.
4. माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल अपने शेयर बेचकर PhonePe से पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे।

A) 1 and 3 only / केवल 1 और 3
B) 1, 3 and 4 only / केवल 1, 3 और 4
C) 2 and 4 only / केवल 2 और 4
D) 1 and 2 only / केवल 1 और 2

E) 1, 2, 3 and 4 / 1, 2, 3 और 4

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• PhonePe has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch its IPO.
• PhonePe को अपना IPO लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की मंजूरी मिली है।
• The company is targeting a fund-raise of ₹12,000 crore, revised upward from ₹10,000 crore.
• कंपनी ₹12,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है, जो पहले ₹10,000 करोड़ था।
• The IPO will be primarily a pure Offer for Sale (OFS) with no fresh capital infusion.
• यह IPO मुख्य रूप से शुद्ध ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा, जिसमें कोई नया पूंजी निवेश नहीं होगा।
• Walmart, PhonePe's largest shareholder, will sell about 9.06% stake (around 4.59 crore shares).
• PhonePe की सबसे बड़ी शेयरधारक Walmart लगभग 9.06% हिस्सेदारी (लगभग 4.59 करोड़ शेयर) बेचेगी।
• Microsoft and Tiger Global will fully exit PhonePe by selling a combined 47 lakh shares in the IPO.
• Microsoft और Tiger Global IPO के जरिए कुल 47 लाख शेयर बेचकर PhonePe से पूरी तरह बाहर निकलेंगे।
• The IPO is being managed by banks such as Kotak Mahindra Capital, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital, and Goldman Sachs.
• इस IPO का प्रबंधन Kotak Mahindra Capital, Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital और Goldman Sachs जैसे बैंक कर रहे हैं।

Ques : SAARG (Strategic Asset Allocation and Risk Governance) has been formed by which regulatory body?
SAARG (स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस द्वारा संस्था नियामक किस गठन का (है गया किया?

A) SEBI / सेबी
B) RBI / आरबीआई
C) IRDAI / आईआरडीएआई
D) PFRDA / पीएफआरडीए
E) IFSCA / आईएफएससीए

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• SAARG has been constituted by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
• SAARG का गठन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण)PFRDA) द्वारा किया गया है।
• It is a 10-member committee chaired by Shri Narayan Ramachandran, former Country Head and CEO of Morgan Stanley India.
• यह 10 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता मॉर्गन स्टेनली इंडिया के पूर्व कंट्री हेड एवं CEO श्री नारायण रामचंद्रन कर रहे हैं।
• The committee has a deadline of 9 months to submit its recommendations.
• समिति को अपनी सिफारिशें देने के लिए 9 महीने की समयहै। गई दी सीमा-
• Its objective is to strengthen investment architecture, promote long-term retirement wealth creation, enhance diversification, improve risk management practices, and expand subscriber choice.
• इसका उद्देश्य निवेश ढांचे को मजबूत करना, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति संपत्ति सृजन को बढ़ावा देना, विविधीकरण सुधारना, जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना और ग्राहकों के विकल्पों का विस्तार करना है।

About PFRDA :

- Established : 2003
- HQ : New Delhi
- Chairman : Sivasubramanian Ramann

Ques: According to the RBI report “State Finances: A Study of Budgets of 2025–26”, what is the gross fiscal deficit of States budgeted for 2025–26 as a percentage of GDP?

RBI की रिपोर्ट "स्टेट फाइनेंसेज़: बजट्स का अध्ययन 2025–26" के अनुसार 2025–26 के लिए राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है?

A) 2.5%
B) 2.8%
C) 3.0%
D) 3.3%
E) 3.8%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India released the report titled "State Finances: A Study of Budgets of 2025–26".
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने "स्टेट फाइनेंसेज़: बजट्स का अध्ययन 2025–26" नामक रिपोर्ट जारी की।
• The theme of the report is "Demographic Transition in India – Implications for State Finances."
• रिपोर्ट की थीम "भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन – राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव" है।
• States' consolidated gross fiscal deficit rose to 3.3% of GDP in 2024–25 after staying below 3.0% during the previous three years.
• पिछले तीन वर्षों तक 3.0% से नीचे रहने के बाद 2024–25 में राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% हो गया।
• For 2025–26, States have budgeted a gross fiscal deficit of 3.3% of GDP.
• 2025–26 के लिए राज्यों ने सकल राजकोषीय घाटा GDP का 3.3% निर्धारित किया है।
• The thrust on capital expenditure has been sustained, with capex steady at 2.7% of GDP in 2023–24 and 2024–25.
• पूंजीगत व्यय पर ज़ोर बना रहा, जो 2023–24 और 2024–25 में GDP का 2.7% रहा।
• Capital expenditure is budgeted to increase to 3.2% of GDP in 2025–26.
• 2025–26 में पूंजीगत व्यय को GDP के 3.2% तक बढ़ाने का बजट रखा गया है।
• The consolidated outstanding liabilities of States are estimated at 29.2% of GDP by end-March 2026.
• मार्च 2026 के अंत तक राज्यों की संयुक्त बकाया देनदारियाँ GDP के 29.2% रहने का अनुमान है।

Ques : What is the main purpose of introducing hybrid ATMs by the government?
सरकार द्वारा हाइब्रिड ATM शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A) Promote credit card usage / क्रेडिट कार्ड उपयोग को बढ़ावा देना
B) Increase digital wallet adoption / डिजिटल वॉलेट अपनाने को बढ़ाना
C) Improve availability of small-denomination currency notes / छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाना
D) Reduce ATM maintenance costs / ATM रखरखाव लागत कम करना
E) Replace traditional ATMs / पारंपरिक ATM को बदलना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The central government is planning to introduce hybrid ATMs to improve the availability of small-denomination currency notes.
• केंद्र सरकार छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ATM शुरू करने की योजना बना रही है।
• These hybrid ATMs will be able to dispense ₹10, ₹20 and ₹50 notes on demand.
• ये हाइब्रिड ATM मांग पर ₹10, ₹20 और ₹50 के नोट उपलब्ध कराएंगे।
• They will also facilitate the exchange of large denomination notes into smaller notes and coins.
• ये बड़े मूल्य के नोटों को छोटे नोटों और सिक्कों में बदलने की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
• The move aims to address the persistent shortage of small notes faced during daily cash transactions.
• इस पहल का उद्देश्य रोजमर्रा के नकद लेन वाली रहने बनी लगातार की नोटों छोटे में देन- है। करना दूर को कमी
• The initiative comes nearly a decade after demonetisation, which significantly altered cash circulation patterns.
• यह पहल नोटबंदी के लगभग एक दशक बाद लाई जा रही है, जिसने नकदी के प्रचलन के स्वरूप को काफी प्रभावित किया था।
• Despite the rapid growth of UPI and digital payments, the demand for small-denomination cash remains high.
• UPI और डिजिटल भुगतान के तेज़ विस्तार के बावजूद छोटे मूल्य वर्ग के नकद नोटों की मांग

अभी भी अधिक बनी हुई है।

Ques : Which entity received in-principle approval for Payment Service Provider authorisation from IFSCA at GIFT-IFSC?
GIFT-IFSC में IFSCA से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्राधिकरण की सैद्धांतिक मंजूरी किस इकाई को मिली?

A) Buyforex / बायफॉरेक्स
B) Eraaya Lifespaces Limited / एराया लाइफस्पेसेज़ लिमिटेड
C) EbixCash World Money / एबिक्सकैश वर्ल्ड मनी
D) Ebix Forex Services / एबिक्स फॉरेक्स सर्विसेज
E) GIFT City Payments Ltd / गिफ्ट सिटी पेमेंट्स लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• EbixCash World Money, a subsidiary of Eraaya Lifespaces Limited, announced that its wholly owned entity Buyforex received in-principle approval for Payment Service Provider authorisation from the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).
• Eraaya Lifespaces Limited की सहायक कंपनी EbixCash World Money ने घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई Buyforex को International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्राधिकरण की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
• The approval has been granted at Gujarat International Finance Tec-City – International Financial Services Centre (GIFT-IFSC).
• यह मंजूरी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी-– इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर)GIFT-IFSC) में दी गई है।
• With this approval, Buyforex became the first Authorised Dealer Category-II (AD-II) licensed group entity to achieve this milestone.
• इस मंजूरी के साथ Buyforex यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली Authorised Dealer Category-II (AD-II) लाइसेंस प्राप्त समूह इकाई बन गई है।

Ques: RBI signed a MoU with which organisation to resolve long-standing bond clearing disputes?

RBI ने लंबे समय से चले आ रहे बॉन्ड क्लीयरिंग विवाद सुलझाने के लिए किस संगठन के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए?

A) World Bank / विश्व बैंक
B) International Monetary Fund (IMF) / अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
C) European Securities and Markets Authority (ESMA) / यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण
D) Bank for International Settlements (BIS) / अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
E) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and information exchange related to Central Counterparties (CCPs).
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण)ESMA) ने सेंट्रल काउंटरपार्टी)CCPs) से जुड़े सहयोग और सूचना आदानलिए के प्रदान- MoU पर हस्ताक्षर किए।
• The MoU aims to resolve long-standing bond clearing disputes between Indian and European Union regulators.
• इस MoU का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के नियामकों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बॉन्ड क्लीयरिंग विवाद को सुलझाना है।
• ESMA agreed to recognise the Clearing Corporation of India Limited (CCIL) as a valid clearing party for EU banks.
• ESMA ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)CCIL) को EU बैंकों के लिए वैध क्लीयरिंग संस्था के रूप में मान्यता देने पर सहमति दी।
• This recognition will allow European banks to seamlessly process bond and derivatives transactions through CCIL.
• इससे यूरोपीय बैंक CCIL के माध्यम से बॉन्ड और डेरिवेटिव लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।
• The dispute began in October 2022, when ESMA sought direct supervisory

access to Indian clearing firms, which was opposed by the RBI.
• यह विवाद अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था, जब ESMA ने भारतीय क्लीयरिंग फर्मों पर प्रत्यक्ष निगरानी अधिकार की मांग की थी, जिसका RBI ने विरोध किया था।
• The new MoU replaces the earlier agreement of February 2017.
• यह नया MoU फरवरी 2017 में हुए पुराने समझौते का स्थान लेता है।
• The agreement supports smoother cross-border bond market operations and enhances financial stability.
• यह समझौता सीमासंचालन बाजार बॉन्ड पार- को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक होगा।

Ques : The World Bank approved a loan of ₹5,700 crore for which project in Haryana?
विश्व बैंक ने हरियाणा में किस परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण मंजूर किया है?

A) Jal Jeevan Mission Haryana / जल जीवन मिशन हरियाणा
B) Jal Sanrakshit Haryana Project / जल संरक्षित हरियाणा परियोजना
C) Namami Gange Haryana Extension / नमामि गंगे हरियाणा विस्तार
D) Atal Bhujal Yojana Haryana / अटल भूजल योजना हरियाणा
E) Har Khet Ko Pani Scheme / हर खेत को पानी योजना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The World Bank has approved a loan of ₹5,700 crore for the Jal Sanrakshit Haryana Project.
• विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए ₹5,700 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
• The objective of the project is to help Haryana achieve self-reliance in water resources.
• इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा को जल संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाना है।
• The loan amount will be disbursed in phases between 2026 and 2032.
• यह ऋण राशि 2026 से 2032 के बीच चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी।

Ques : According to Swiss Re, which country is projected to be the fastest-growing major insurance market globally during 2026–2030?
स्विस री)Swiss Re) के अनुसार 2026–2030 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाजार होगा?

A) China / चीन
B) United States / संयुक्त राज्य अमेरिका
C) South Africa / दक्षिण अफ्रीका
D) Brazil / ब्राज़ील
E) India / भारत

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

• According to Swiss Re, India's insurance premiums are projected to grow at a real annual rate of 6.9% during 2026–2030, making India the fastest-growing major insurance market globally.
• Swiss Re के अनुसार 2026–2030 के दौरान भारत के बीमा प्रीमियम में वास्तविक वार्षिक 6.9% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख बीमा बाजार बन जाएगा।
• India's insurance growth rate is significantly higher than China (around 4%) and the United States (around 2%).
• भारत की बीमा वृद्धि दर चीन लगभग)4%) और अमेरिका लगभग)2%) से काफी अधिक है।
• This growth marks a strong rebound from slower growth of only 3.1% in 2025, when the market adjusted to new regulations.
• यह वृद्धि 2025 में नए नियमों के समायोजन के कारण दर्ज की गई 3.1% की धीमी वृद्धि के बाद मजबूत वापसी को दर्शाती है।
• In life insurance, India is the second-largest market among emerging economies, with expected annual growth of 6.8% over the next five years, driven by expanding distribution networks.
• जीवन बीमा क्षेत्र में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां अगले पांच वर्षों में 6.8% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, जिसका कारण वितरण नेटवर्क का विस्तार है।
• Health insurance in India is expected to grow at an average rate of 7.2% per

year during 2026–2030.

• भारत में स्वास्थ्य बीमा के 2026–2030 के दौरान औसतन 7.2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है।